लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation
24-8-92
Fumigated
On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, मंगलवार, 26 फरवरी, 1974/7 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 6, *Tuesday, February* 26, 1974/*Phalguna* 7, 1895 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary Reference	1–2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

83 राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कैपेसिटरों का उपयोग न किये जाने के कारण बिजली का व्यर्थ जाना	Power Wastage due to Non use of a Capacitor by State Electricity Boards . . .	2–5
84 फरस की खाड़ी वाले देशों से अशोधित तेल की सप्लाई	Crude Oil Supplies from Persian Gulf Countries . . .	5–8
85. औषध उद्योग पर भट्ठी-तेल की कमी का प्रभाव	Impact of Shortage of Furnace Oil on Drug Industry . .	9–11
87 ईंधन संसाधनों को सुरक्षित रखने के उपाय	Measures to Conserve Fuel Resources	11–12
88. पोंग बांध के विस्थापितों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Pong Dam Oustees	12–13
89 पेट्रौल में उसकी कीमत बढ जाने के कारण मिलावट	Adulteration of Petrol due to increase in its price . .	13–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

81 राज्यों में कोयले से पैट्रोल बनाने ने के संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Plants for producing Petrol from Coal in States .	14
82 पश्चिमी बंगाल से बंगला देश होते हुए त्रिपुरा तक सीधी रेल सेवा	Direct Train Service from West Bengal to Tripura via Bangladesh	15
86 भारतीय उर्वरक निगम का नया आधुनिक एकक	New Modern Unit of FCI .	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually was asked on the floor of the House by him.

1—2 L.S.S./74

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
90	काली नदी जल विद्युत परियोजना में बिजली का उत्पादन	Generation of Power at Kalinadi Hydro-Electric Project .	15
91	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token strike by O & NGC Officers	16
92	भारत रक्षा निगम के अधीन अनिर्णीत मामलों का वापस लिया जाना	Withdrawal of Pending Cases under DIR	16
93	"करप्शन इन कोर्टस इन इंडिया" नामक पुस्तक	Book Entitled "Corruption in Courts in India". . .	16–17
94	नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन पर तेल संकट का प्रभाव	Impact of Oil Crisis on production of Nitrogenous Fertilizers .	17
95	आर० डी० एस० ओ० लखनऊ का दुमंजिले रेल डिब्बे बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Manufacturing of Double-Decker Coaches by RDSO Lucknow . . .	17–18
96	रेलवे वैगनो की अत्यधिक कमी	Acute Shortage of Railway Wagons	18–19
97	केरल तट पर तट-दूर खुदाई के लिये केरल सरकार के प्रस्ताव	Proposals from Kerala Government for off shore drilling in Kerala Coast . . .	19
98	आल इंडिया रेलवे टैक्नीशियन स्टाफ द्वारा कार्यवाही आरम्भ करने की धमकी	Threat of action by All India Railway Technician Staff .	19–21
99	आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ द्वारा इलेक्ट्रानिक आटौमैटिक वारनिंग सिस्टम का विकास	Electronic Automatic Warning System development by RDSO Lucknow	21
100	'चूले' के लिये नये डिजाइन का विकास	Development of new Design for Chullah	21

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

801	उर्वरकों के भंडार के लिये गोदाम	Godowns for Storing Fertilizers	21–22
802	मंगलौर-पानाम्बूर रेलवे लाइन का प्रयोग	Use of Mangalore Panambur Railway Line . . .	22
803	कर्नाटक के पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी समुद्री तटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की जल विद्युत क्षमता के लिये सर्वेक्षण	Survey for Hydro electric power potential of Rivers flowing in Western Ghat and Western Coast region of Karnataka .	22–23
804	'वाराही' जल विद्युत परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कर्नाटक सरकार का सहायता के लिये अनुरोध	Assistance sought by Karnataka for implementation of 'Varahi' Hydro Electric Project .	23

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
805	कोचीन, मद्रास और बम्बई तेल शोधक कारखानों से कर्नाटक को ढोये गये पैट्रोलियम उत्पाद	Petroleum products transported to Karnataka from Cochin, Madras and Bombay Refineries	23
806	उर्वरकों और कोयल के परिवहन के लिये कर्नाटक राज्य की मांग को पूरा करने की कार्यवाही	Steps taken to meet the demand of Karnataka State for Transportation of Fertilizers and Coal	23–24
807	पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	Export of Petrol and Petroleum Products	24
808	राजस्थान में बनाये जाने वाले प्रस्तावित उपरिपुल	Proposed Over Bridges to be constructed in Rajasthan .	25
809	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और विद्युत परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in U.P.	25
810	दक्षिण रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Temporary Employees of Southern Railway .	26
811	पूर्वोत्तर रेलवे में हड़ताल के कारण रेल-संम्पत्ति की क्षति	Loss of Railway Property on North Eastern Railway due to Strike	26
812	मध्य प्रदेश में पंजीकृत तथा परिसमाप्त हुई कम्पनियां	Companies Registered and Liquidated in Madhya Pradesh	26
813	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Plant in Madhya Pradesh . .	27
814	भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण में बाधा	Disruption in Working of FCI .	27
815	केरल में इदिक्कि परियोजना का निर्माण कार्य	Construction of Idikki power project in Kerala . .	28
816	केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना	Vamanapuram Irrigation Project in Kerala	29
817	अशोधित तेल का आयात तथा उस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Import of crude oil and the foreign Exchange spent therefore .	29
818	बम्बई और कोचीन के बीच सीधी रेल सेवा	Through Train Service between Bombay and Cochin . .	30
820	गत वर्ष के दौरान पश्चिम रेलवे में अपराध	Crimes on Western Railway during the last year . .	30–31
821	तेल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statements on Oil Situation .	31
822	रूस के तेल मंत्री का भारत के तेल क्षेत्रों का दौरा	Visit of Soviet Oil Minister to Oil Fields in India . .	31–32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
823	मानसी रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजपथ संख्या-31 की सुरक्षा के लिये बिहार सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for protection of Mansi Railway Station and National Highway No. 31	32
824	हिंदुस्तान एल्युमिनियम कम्पनी, मिर्जापुर द्वारा बिजली घर की स्थापना	Power Station set up by Hindustan Aluminium Co. at Mirzapur	32
825	अत्यावश्यक वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में वैगनों की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of Wagons in Movement of Essential Commodites	33
826	कोयले पर आधारित रसायनों का विकास	Development of Coal Based Chemicals	33
827	तलचेर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र	Talcher Coal Based Fertilizer Plant	33
828	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड के अन्तर्गत केरल में औषध एकक स्थापित किया जाना	Locating of a drug unit at Kerala Under Indian Drugs and Pharmaceutical Limited	34
829	नेपाल को और अधिक मात्रा में पैट्रोल और स्नेहक तेल की सप्लाई	Supply of more Petrol and Lubricating Oil to Nepal . .	34
830	निर्यात से होने वाली आय को अशोधित तेल के आयात पर व्यय करना	Export Earnings utilised on Import of Crude Oil . .	34
831	विदेशी नियंत्रण वाली औषध कंपनियों के लाभों के बार में लागत-लेखा समिति की शिफारिशें	Recommendations of the Cost and Accounts Committee on Profits of Foreign Controlled drug Companies	35
832	कोचीन स्थित फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना	Non Utilization of full capacity of F.A.C.T. Plants at Cochin	35
833	खाद्यान्नों के राशन की मात्रा बढ़ाने के लिए नागपुर के रेल कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation for more ration by Railway Employees in Nagpur .	35
834	मध्य-प्रदेश में हवाई-फोटो जांच विधि से सिंचाई तथा परियोजनाओं के बारे में प्रारूप प्रतिवेदन	Preparation of Draft report on Irrigation and Power Projects in Madhya Pradesh through Aerial Photographic Survey System	36
835	पैट्रोल और डीजल के रंगों को बदलना	Changing Colours of Petrol and Diesel	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
836	धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन	Railway line Between Dharamanagar and Kumarghat .	36
837	रेल गाड़ियों के चालकों के लिये सतर्कता युक्ति	Trains with Drivers Vigilance Device	36–37
838	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान के मरूक्षेत्र में तेल की खोज	O. & N.G.C. Search for Oil in desert region of Rajasthan .	37
839	अज्ञात तेल संसाधनों की खोज	Search for Hidden Oil Resources	37–38
840	केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पैट्रोल की खपत	Petrol Consumption by Central Ministries . . .	38
841	अधिकतम पैट्रोल की खपत करने वाले दस बड़े नगर	Ten Major Cities where Maximum Petrol Consumed .	38
842	गत वर्ष के दौरान बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling during the Last Year	38–39
843	गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये दिये गये लाइसेंस	Licences issued by setting up of Fertilizer Plants in Private Sector	39
844	पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को नया रूप प्रदान करने की योजना	Scheme to give New Look to Patna Junction Railway Station	40
845	आल इंडिया ट्रेन एक्सामिनर्स के आन्दोलन के कारण रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains due to Agitation by All India Train Examiners . . .	40
846	राज्यों में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Bastis in States	40
847	बिहार में 'सुपर' तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of a 'Super' Thermal Power Station in Bihar .	41
848	तटवर्ती नौवहन के लिये रियायती दरों पर ईंधन तेल की सप्लाई	Supply of Fuel Oil for Coastal Shipping at Concessional Rates	41–42
849	कांगडा घाटी रेलवे लाइन का पूरा होना	Completion of Kangra Valley Railway Line . . .	42
850	चेतक एक्सप्रैस का दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर देर से पहुंचना	Late arrival of Chetak Express at Delhi Sarai Rohilla Station .	42–43
851	तटवर्ती जहाजी बेड़े के लिए 'बेंकर आयल' के मूल्य	Prices of Bunker Oil for Coastal Fleet	43
852	एकाधिकार ग्रहों के प्रबंध बोर्डों में सरकारी निदेशकों को मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव	Proposal to nominate Government Directors on the Boards of Management of Monopoly Houses	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
853	रेल तथा तटवर्ती जहाजों द्वारा कोयला, नमक तथा सीमेंट की ढुलाई के लिये समन्वय निकाय	Body to Co-ordinate Haulage of Coal-Salt and Cement by Rail and Coastal Ships . .	43-44
854	रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा में कमी	Decline in Freight carried by Railways	44-45
855	घांस बागमती नदी पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजना तथा मोहिनी नदी पर तटबंध बनाने के कार्य को अंतिम रूप देना	Finalisation of Flood Control-cum-Irrigation Schemes over River Dhans Bagmati and Embankments over River Mohini	45
856	बिहार में खिरोई नदी पर स्लूस फाटक एवं पुल बनाना	Construction of sluice Gate-cum-Bridge over River Khiroi in Bihar	45-46
857	सिंचाई परियोजनाओं के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for Irrigation Projects .	46
858	मेरठ में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग	Demand for setting up a Bench of High Court at Meerut .	46
859	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले तथा न्यायाधिशों के रिक्त पड़े स्थान	Cases pending and Seats of Judges Vacant in Supreme Court and High Courts . . .	46-47
860	राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे के नियतन में कटौती	Cut in Allocation of Kerosene Quotas to States . . .	47
861	त्रिवेंद्रम तथा कन्याकुमारी के बीच रेल सम्पर्क और एर्नाकुलम-त्रिवेंद्रम रेल लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना	Rail Link between Trivandrum and Cape Commorin and Conversion of Ernakulam Trivandrum Railway Line into Broad Gauge	47-48
862	केरल में रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains in Kerala	48
863	कर्नाटक राज्य में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of metre gauge lines into broad gauge in Karnataka State	48-49
864	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to meet financial deficit during current financial year	49
866	हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को लाइसेंस के बारे में एकाधिकार तथा निबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सिफारिशों पर निर्णय	Decision on the recommendation of MRTP Commission on licence to Hindustan Lever Limited	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
867	कम मूल्य के बीजक बनाने और चोर बाजारी जैसी व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में एकाधिकार तथा निबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच करने का प्रस्ताव	Proposal to probe into the Trade practices like underinvolving and black marketing by MRTP Commission . . .	49–50
868	तेनुघाट में सुपर तापीय बिजलीघर की स्थापना	Setting up of Super Thermal Power Station at Tenughat .	50
869	वर्ष 1973 में भारतीय उर्वरक निगम के लाभ की राशि में गिरावट	Decline in profit of FCI in 1973	50–51
870	सरकारी कारों में पैट्राल की खपत	Consumption of Petrol by Government Cars . . .	51
871	सऊदी-फ्रांस तेल समझौते का भारत को की जाने वाली अशोधित तेल की सप्लाई पर प्रभाव	Impact of Saudi French Oil Agreement on Crude Supplies to India	51
872	ड्राइवरों द्वारा 10 घंटे के कार्य के बाद छोड़ दी गई रेलगाड़ियां	Trains Abandoned by Drivers after 10 Hours Duty . .	51–52
873	थीन बांध परियोजना का निर्माण न होने के कारण पंजाब को हुई हानि	Loss suffered by Punjab due to non construction of Thien Dam Project	52
874	दुर्गापुर परियोजना में आग	Fire in Durgapur Project. .	52
875	आरामबाग, हुगली के लोगों से लोअर दामोदर योजना के पुनर्विचार के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding revision of Lower Damodar Scheme from Arambag, Hooghly .	53
876	राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in States	53–54
877	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का उस प्रणाली के बारे में विरोध जिसमें कि उसे मामले भेजे जाते हैं	MRTP Commission's objection to the manner in which cases are referred to it . . .	54
878	पांचवीं योजना में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही	Steps to boost Fertilizer production in Fifth Plan .	54–55
879	विदेशी औषधि फर्मों का भारत में बनी दवाइयों को अपने ब्रैंडों के नाम से बेचना	Foreign Drug Firms Marketing Indian made drugs under their brand names . . .	55
880	मट्टी के तेल की कमी तथा इसके आयात के लिये किये गये प्रयत्न	Shortage of furnace oil and efforts made for its import . .	56
881	नेपाल स्थित करनाली पन-बिजली परियोजन से बिजली की खरीद	Purchase of Power from Karnali Hydro Electric Project of Nepal	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
882	भारत में तेल के खोज की लिये अमरीकी सहायता	U.S. Assistance for Oil Exploration in India . . .	57
883	श्रीलंका द्वारा भारत को जल विद्युत की सप्लाई	Supply of Hydro Power to India by Sri Lanka . . .	57
884	गरीबों को कानूनी सहायता देने संबंधी प्रयोग	Experiments on giving Legal Aid to the Poor . . .	58
885	रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना, दोहरा करना, बंद लाइनों को फिर से चलाना तथा नई रेल लाइनें बिछाना	Conversion to Broad Gauge, Doubling Restoration and laying of New Railway Lines . .	58
886	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया गतिविधियों में लगी विदेशी कंपनियों के नाम	Foreign Companies charged with Monopolies and Restrictive Trade Practices . . .	58–59
887	गुजरात में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	Medium and Major Irrigation Projects in Gujarat . .	59–60
888	गुजरात में सोवियत संघ की सहायता से प्राकृतिक तेल तथा गैस आयोग द्वारा तेल की खोज	Oil Exploration by O. & N. G.C. in Gujarat with the help of USSR. . . .	60
889	गुजरात राज्य में नायलोन-उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Nylon Factory in Gujarat State . . .	61
890	बाढ़ों और हड़तालों से नष्ट हुई रेल संपत्ति की क्षतिपूर्ति और मरम्मत में हुआ व्यय	Amount spent on Restoration and Repair of Railway Property due to Floods and Strikes .	61
891	मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सोन नदी के जल का वितरण	Distribution of Sone Water amongst M. P., Bihar and Andhra Pradesh . .	62
892	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनायें	Rural Electrification Projects sanctioned by Rural Electrification Corporation . .	62
893	बंगलोर-मैसूर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Bangalore-Mysore Meter Gauge Line into Broad Gauge	62–63
894	रॉक फोस्फेट क्षेत्रों के विकास के लिये समिति	Committee for Development of Rock Phosphate Areas .	63
895	वर्ष 1973 के दौरान घायल होने तथा मृत्यु होने के दौरान दिया गया मुआवजा	Compensation paid for Death and Injury during 1973 .	63
896	हावड़ा में इंस्पैक्टर कार्यालय का तोड़ा फोड़ा जाना	Ransacking of Inspector's Office at Howrah . . .	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
897	सियालदह साउथ रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा का अस्त-व्यस्त होना	Dislocation of Train Services at Sealdah South Railway Station	64
898	मालदा से बलूरघाट बरास्ता गाजोल या अकलाकली से बलूरघाट रेल लाइन	Railway Line from Malda to Balurghat via Gajol or from Aklakli to Balurghat . .	64
899	पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिये बिजली का मूल्यांकन	Assessment of power for Irrigation in West Bengal in Fifth Plan .	65
900	योजना आयोग का अशोधित तेल का आयात कम करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना	Rejection of Proposal from Planning Commission to reduce Crude Oil Imports . .	65
901	बागमती परियोजना को पूरा करना	Execution of Bagmati Project .	65
902	बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	Rural Electrification Programme in Bihar	66
903	उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में बिजली की कमी	Power Shortage in U.P. and other areas	66–67
904	कुप्रबंध के कारण फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, त्रावनकोर को घाटा	Loss in FACT due to Mismanagement	67–68
905	चार रेलवे जोनों में चालू की गई और की जाने वाली रेल सेवाएं	Trains Services introduced and to be introduced on four Railway Zones	68
906	कोचीन जाने वाली जयंती जनता एक्सप्रैस गाड़ी का रद्द किया जाना	Cancellation of Jayanti Janta Express to Cochin . . .	68
907	रेल-लाइनों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway Lines	69
908	विभिन्न यूनियनों के लिये संचार साधनों की व्यवस्था करना	Provision of means of communication to various Unions .	69
909	आल इंडिया ट्रेन एक्जामिनर्स एसोसियेशन द्वारा "नियमानुसार कार्य" करने का आह्वान	Work to Rule call by All India Train Examiners Association	69–70
910	पैट्रोल, गैस और मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था में सुधार के लिये उपाय	Steps to improve Distribution machinery for Petrol, Gas and Kerosene . . .	70
911	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मस्यूटिकल लिमिटेड के कर्मचारियों की मांग का समझोता	Settlement on Demands of IDPL Employees . . .	70
912	पैट्रोल का राशन करने के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ मतभेद	Differences with Finance Ministry on Petrol Rationing .	71
913	औषधि अकाल की संभावना	Possibility of a Drug Famine .	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
914	रेल कमचारियों की हड़ताल के दोरान प्रादेशिक सेना का तैनात किया जाना	Deployment of Territorial Army during the Railwaymen's Strike	71
915	मिया भाई न्यायाधिकरण को सफारिशों के परिणामस्वरूप नैमित्तिक कर्मचारियों के अधिकृत वेतन	Authorised Scales of Payment for casual labour due to recommendations of Miabhoy Tribunal	72
916	तापीय बिजलीघरों में कोयले का प्रयोग	Use of Coal in Thermal Power Station	72–73
917	पांचवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं	Irrigation facilities in Adivasi areas during Fifth Plan .	73
918	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण	Electrification of Tribal areas in M.P.	73
919	साहिबगंज रेलवे कार्यालय की आल्मारी से 1,25,000 रुपए लापता होना	Rs. 1,25,000 missing from the safe of Sahibganj Railway Office .	74
920	रुमानिया के सहयोग से तेल की खुदाई करने वाल एक एकक की स्थापना	Setting up of an Oil Drilling Unit in collaboration with Romania	74
921	असम सरकार द्वारा अशोधित तेल पर रायल्टी की वृद्धि की मांग	Demand for increase in royalty on oil crude by Assam Government	74
922	लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में 'तयार' भोजन देने की योजना को लागू करना	Introduction of scheme of ready-to-serve meals in long distance trains	75
923	विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर रेलगाड़ियों का रोका जाना	Detention of trains on the requests of V.I.Ps.	75–76
924	थीन बांध परियोजना का पांचवी योजना में सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Thien Dam Project in Fifth Plan . . .	76
925	उर्वरकों में नेफ्था का विकल्प	Substitute for Naphtha in fertilisers	76
926	पोचमपड्ड, श्रीसेलम तथा नागार्जुन सागर परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Pochampad, Srisailam and Nagarjun Sagar Projects . . .	76–77
927	अशोधित तेल के आयात में कमी	Cut in Import of Crude Oil .	77
928	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में ग्रामों के विद्युतीकरण का उपबंध	Provision for Electrification of Villages in West Bengal in Fifth Plan	77
929	इंडियन ड्रग्ज एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० के अधीन स्थापित किए जाने वाल दो औषध कारखानों का स्थान	Location of Two Drug Units to be set up under IDPL .	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
930	पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल के लिए सिचाई योजना	Irrigation Projects for West Bengal in Fifth Plan . . .	78–79
931	पश्चिम बंगाल में पैट्रोल रसायन उद्योग	Petro Chemical Industries in West Bengal. . . .	79–80
932	पट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन द्वारा भारत के साथ विशिष्ट व्यवहार करने के लिए भारत द्वारा अनुरोध	Request for Special Treatment of India by OPEC . .	80
933	पैट्रोल के स्थान पर डीजल का प्रयोग करने की विधि	Device to Replace Petrol by Diesel	80
934	सिचाई कुएं तेल की प्राप्ति के बारे में किसानों का दावा	Farmers Claims on Oil find in Irrigation Well . . .	81
935	उर्वरक उद्योग में पूंजी निवेश पर लाभप्रदता को बढ़ाने के उपाय	Measures to Improve Profitability on Investment in Fertiliser Industry	81
936	बदरपुर बिजली घर से पंजाब को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Punjab from Badarpur Thermal Station .	81
937	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कार्यों में कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अधीन निरीक्षण	Inspection under Section 209(4) of the Companies Act on the Affairs of Hindustan Lever Ltd.	82
938	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के भारतीयकरण के लिए कार्यवाही	Steps taken to Indians Hindustan Lever Ltd. . . .	82
939	पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पेनल बनाया जाना	Setting up of a Panel for Rural Electrification in Eastern States	82–83
940	हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए बिजली बोर्डों द्वारा धन का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Funds by Electricity Boards for Electrification of Harijan Bastis .	83
941	बुलंदर शहर को डिबाई रेल मार्ग से जोड़ना	Linking of Bulandshahr with Dibai	83
942	अरब देशों द्वारा समृद्ध देशों को कम मूल्यों में तेल की सप्लाई किया जाना	Supply of oil by Arab Countries to Affluent Countries at redduced Prices . . .	84
943	22 जनवरी, 1974 को उत्तेजित भीड़ द्वारा मेरठ स्टेशन पर पथराव	Brick batting by excited crowd at Meerut Station on 22nd January, 1974 . .	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
944	तेल का उत्पादन करने वाले देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के पश्चात् इसके आयात पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on Import of Crude Oil after increase in its prices by Oil producing Countries .	84–85
945	कोटा वर्कशाप में अनुसूचित जाति के ड्राइवरों को सरकारी आवास का आबंटन	Allotment of Quarters to drivers belonging to Scheduled Castes in Kota Workshop . .	85
946	रेलवे के लोको कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि के लिए भुगतान	Payment to Railways Loco Employees for strike period .	85
947	पांचवी योजना में उड़ीसा की स्वर्णरेखा परियोजना का शामिल किया जाना	Inclusion of Subarnarekha Project of Orissa in Fifth Plan -	85
948	ईरान द्वारा विदेशी की तुलना में भारत से अशोधित तेल की वसूली की जाने वाली दरें	Rates of Crude Oil charged by Iran from Foreign countries vis-a-vis India . . .	86
949	रुपसा तथा बांगरीपोश लाइन को बड़ी लाइन (दक्षिण) पूर्व रेलवे में बदलने के बारे में सर्वेक्षण	Survey to make Rupsa and Bangriposh line into Broad Gauge (Southern Railway) . .	86
950	रेलवे खान-पान संबंधी समिति का भंग किया जाना	Abolition of Railway Catering Committee	86
951	बांकुरा दामोदर सैक्शनों में यात्री गाडियां	Passenger trains on Bankura-Damodar Sections . . .	87
952	यात्रियों तथा बर्दवान रेल अधिकारियों के बीच झगड़ा	Clash between passengers and Burdwan Railway Authorities	87
953	दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र का पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य चलाना	Working of Durgapur Fertilizer Plant to full capacity . .	87–88
954	गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Gujarat	88
955	लम्बी दूरी की यात्रा करने वालों को दी जाने वाली अग्रिम आरक्षण सुविधाओं तथा सेवाओं में सुधार	Improvement in advance reservation facilities and services to long distance jouney passengers	88
956	महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टालों की संख्या में वृद्धि	Increase in Book Stalls on Important Stations . . .	89
957	गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये सहायता	Assistance for construction of Irrigation projects and Extension of Irrigation facilities in Gujrat	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
958	अहमदाबाद से वाराणसी तक सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिये किया गया अभ्यावेदन	Representation made for direct train from Ahmedabad to Varanasi	90
959	विदेशी औषध कम्पनियों के बारे में कार्यकारी दल	Working group on foreign drug Companies	90-91
960	नेफथा आधारित उर्वरक परियोजनाओं का उत्पादन कार्यक्रम	Production Schedule of Naphtha based fertiliser projects .	91-92
961	राज्यों में सिंचाई दरों तथा बिजली प्रशुल्कों में वृद्धि	Increase in irrigation rates and Electricity tariffs in States .	92
962	गुजरात को बिजली की सप्लाई	Supply of Power in Gujarat	92-93
963	उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश द्वारा अंतर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना	Setting up of a control Board for Inter State river valley Projects by U.P. and M.P. .	93
964	ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Rural Electrification Programmes	93-94
965	नई सिंचाई परियोजना के लिये केरल सरकार का प्रस्ताव	Kerala's proposal regarding new Irrigation project . .	94
966	तेल और गैस की खोज के लिये स्थानों का पता लगाया जाना	Location of places by Geologists for oil and gas exploration .	94-95
967	22 जनवरी, 1974 को रेलवे पुलिस द्वारा एक सवारी गाड़ी पर छापा मारा जाना	Raid on passenger train by Railway police on 22nd January, 1974	95
968	खंभात से कालोल क्षेत्र में कोयले की खानों के बीच तेल का पाया जाना	Presence of oil in Coal Quarries Kalol region of Khambat .	95
969	नौकरी करने आने वाले लोगों के लिए रेलगाडियां	Trains for Office coming people in Delhi	95-96
971	बाढ नियंत्रण और जल साधनों के विकास हेतु भारत-बंगलदेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा दिया गया सुझाव	Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission Plan regarding Flood control and Development of Water Resources . .	96
972	तल शोधक कारखानों में बचे हुये भारी ईधन तेल का पुन: परिष्करण	Secondary processing of Heavy residual Fuel Oil in Refineries	96-97
973	सोनिपत/पानिपत और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करना	Doubling of Railway Line from Sonepat/Panipat to Delhi .	97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
974	पालामऊ तथा रांची को नई रेलवे लाईन से मिलाना	Connection of Palamau and Ranchi with New Railway Line .	97
975	बी० डी०, डी० तथा सी० जी० लाईनों पर चलने वाली गाड़ियों की बिगड़ती स्थिती	Deteriorating condition of Train running on the BDGD and C.G. Line	97–98
976	डीजल के अभाव के कारण डिजल इंजनों के स्थान पर कोयला द्वारा चलने वाले इंजनों का लगाया जाना	Replacement of Diesel Engines by Steam Engines due to shortage of Diesel	98
978	रेलवे के विद्युतीकरण के लिए केरल सरकार का अनुरोध	Request of Kerala Government for Electrification of Railways	98
979	आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज	Oil Exploration by Oil Indian Limited	98
980	केरल बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए कावेरी जल का मार्ग परिवर्तन	Diversion of Cauvery Water for Power Generation and Irrigation in Kerala . . .	99
981	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट को बर्खास्त करना	Dismissal of a Delhi Magistrate by the High Court of Delhi .	99
982	राजस्थान को नर्मदा नदी के पानी की सप्लाई	Supply of Narmada water to Rajasthan	99
983	राजस्थान में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation schemes in Rajasthan	99–100
984	पाली और जोधपुर के बीच चलने वाली शटल गाड़ी का बंद किया जाना	Withdrawal of Shuttle Train running between Pali and Jodhpur	100
987	मोरारका समूह द्वारा 1962 से चलाई जा रही फर्मे	Concerns managed by the Morarkas since 1962 . . .	100–101
988	उर्वरकों के निर्माण के लिए आधार	Bases for Manufacture of Fertilisers	102
990	विदेशी सहयोग के साथ तेल की खोज	Oil Exploration with Foreign Collaboration . . .	102
991	फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा योजना का विविधीकरण	Plan for Diversification by FACT	103
992	अनुमति पत्रों के अतंर्गत निर्धारित क्षमताओं के अतिरिक्त मिश्रित उत्पाद बनाना	Formulations in excess of the capacities covered by Permission letters	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
993	भारतीय औषध उद्योग का भारतीयकरण करने के बारे में आई० डी० एम० ए० का ज्ञापन	Memorandum from IDMA regarding Indianisation of Indian Drug Industries . . .	104
994	बिहार में सिंचाई और विद्युत के विकास की योजना	Scheme for development of Irrigation and Power in Bihar .	104
995	राजस्थान में उर्वरक संयत्र की स्थापना	Location of a Fertiliser Plant in Rajasthan	104–105
996	पूर्वोत्तर सीमात रेलवे में खानपान कर्मचारी विभाग	Department of Catering Staff on North East Frontier Railway	105
997	खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training for Catering Staff .	105–106
998	रेलवे खान-पान तथा यात्री सुविधा संबंधी समिति का प्रतिवेदन, 1967	Railway Catering and Passengers Amenities Committee Report, 1967	106–107
999	बंगाल की खाड़ी में एक विदेशी कम्पनी द्वारा तेल के बड़े भंडारों का पाया जाना	Discovery of Large Oil Deposits in Bay of Bengal by a Foreign Company . . .	107
1000	चुनाव होने वाले राज्यों को तेल की सप्लाई	Supply of Oil to States where Elections are being held .	108
1001	आसाम और गुजरात में तेल क्षेत्रों में गैस की बरबादी	Wastage of Gas in Oil Fields in Assam and Gujarat . .	108–109
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	109–111
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	111
	भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Reserve Bank of India (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha.	111
	एशियन कबल्स कारपोरेशन के बारे मे 21-12-1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर के सम्बन्ध में एक सदस्य द्वारा दिया गया वक्तव्य—	Statement by Member re. Answer to S. Q. No. 591 dated 21-12-73 on Asian Cables Corporation—	
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotiromoy Bosu . .	111
	श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Shri D. P. Chathopadhyaya .	112व 113–114
	नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
	पटना और दानापुर (बिहार) में राशन की दुकानों में राशन उपलब्ध न होना	Alleged non-availability of wheat in Ration Shops of Patna and Danapur (Bihar) . . .	115–116

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on the President's Address—	
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	116–117
श्री निंबालकर	Shri Nimbalkar . . .	117–118
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	119व 120–121
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	122–123
श्री क० के० शेट्टी	Shri K. K. Shetty .	123
श्रीमती कृष्णकुमारी	Shrimati Krishna Kumari	123
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra .	124–125
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai .	125–127
डॉ० कर्ण सिंह	Dr. Karn Singh . .	127–128
श्री ए० दुराईरासु	Shri A. Darairasu .	128–129
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque .	129–131
श्री सी० एच० मोहमद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya .	131–132
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi .	132
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	132
श्री पन्नालाल बारुपाल	Shri Pannalal Barupal .	133
डा० कैलास	Dr. Kailas . . .	133–134

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 26 फरवरी, 1974/7 फाल्गुन, 1895 (शक)
Tuesday, February 26, 1974/Phalguna 7, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री तुलसीदास मूलजीभाई सेठ के दुखद निधन की सूचना देता हूं जिनका 66 वर्ष की आयु में 22 फरवरी 1974 को अहमदाबाद में स्वर्गवास हो गया है।

श्री तुलसीदास सेठ वर्ष 1967–70 में चौथी लोकसभा के सदस्य थे और गुजरात के कच्छ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, वह पहले वकील थे और भूतपूर्व कच्छ राज्य के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश थे और बाद में गजरात राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में सिविल अधिकारी थे, इनका संबंध अनेक शैक्षिक और दानपात्री संस्थाओं से था, सरकारी सेवा से 1963 में सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में पुनः वकालत आरंभ की। लोक सभा के सदस्य क नाते वह सत्यनिष्ठ रहे और सभा की कार्यवाही में नियमित रूप से भाग लेते रहे और उपस्थित होते रहे।

हमें अपने इस मित्र के निधन का शोक है और सभा मेरे सहित संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करती है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हमें श्री तुलसीदास सेठ के दुखद निधन पर गहरा शोक है जिन्होंने गुजरात और कच्छ की वकील न्यायाधीश, प्रशासक और विधायक के रुप में सेवा की । उनके निधन से अनेक समाजसवी संस्थाओं को हानि हुई है जिनको उनसे मार्गदर्शन मिलता था । हम आपके माध्यम से संतप्त परिवार को अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना भेजते हैं ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अपने दल की ओर से मैं अपने को आपके उद्गारों सम्बद्ध करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) **:** While associating myself with the sentiments of sympathy and grief expressed by you and the Prime Minister, I, on behalf of my party and on my own behalf, request you to convey our condolences to the bereaved family.

2—2 L. S. S./74

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं भी अपनी और अपने दल की और से इन उद्गारों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : समाजवादी दल की और से मैं संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

Km. Maniben Patel (Sabarkantha) : I Recall Shri Sheth here in Lok Sabha and his work also. Kindly convey our condolences to the bereaved family.

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : Sir, I convey heartfelt condolences on behalf of my Party and on my own behalf on the sad demise of Shri Sheth. I pray to God to give courage to the bereaved family to bear this loss. Kindly convey our condolences to the bereaved family.

श्री पी० जी मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं आपके साथ, सभा की नेता के साथ और अन्य सदस्यों के साथ इस संवेदना में अपने को सम्बन्द्ध करते हुए श्री तुलसीदास सेठ के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। म कुछ समय स उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। बम्बई से अहमदाबाद जाते हुए जब गाडी वहां रुकी और वह रेल डिब्बे से बाहर आ रह थे तो अचानक उनका प्राणान्त हो गया।

उनके निधन से गुजरात और विशेषकर कच्छ को एक समाज सेवक, और बहुत भले आदमी से वंचित होना पडा है, लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य के तौर पर मुझे पता लगता रहा है कि वह यहां उपस्थिति और अपने विभिन्न संसदीय कर्तव्यों के प्रति कितने नियमबद्ध थे, गुजरात और कच्छ के हम लोगों को इससे बहुत हानि हुई है। मैं संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सम्मान स्वरुप सभा कुछ समय के लिए मौन खडी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे ।
The Members then stood in silence for a while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा केपेसिटरों का उपयोग न किये जाने के कारण बिजली का व्यर्थ जाना

*83. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली नष्ट होने की प्रतिशतता 20 से 27 तक प्रतिशत तक पहुंच गई है;

(ख) क्या ऐसा अंशत: इस लिए भी होता है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा निर्मित विशेष कैपेसिटरों का ट्रांस्मिशन लाइनों में उपयोग नहीं किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के बिजली बोर्डों को सलाह दी है कि वे कैपेसिटर का उपयोग करके इस हानि को कम करें; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) विद्युत के परिणमन, पारेषण और वितरण में सदा ही कुछ हानि निहित होती है। अनुमान लगाया गया है कि 1972–73 के दौरान देश में औसतन उर्जा शक्ति 18.3 प्रतिशत हुई थी।

(ख) शंट संधारित्रों जैसे कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स ने निर्मित किए हैं, के प्रतिष्ठापन से कुछ स्थितियों में पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी होती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने, अन्य उपायों के अतिरिक्त, राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी है कि अपनी प्रणालियों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिये शंट संधारित्रों को प्रतिष्ठापन करें।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों ने केन्द्रीय सरकार के सुझावों पर अमल किया है और उर्जा हानियों को कम करके अपनी प्रणालियों को कार्य कुशलता-बढ़ाने के लिए कार्यवाही कर रहे है।

श्री डी० डी० देसाई : देश में बिजली की बहुत कमी है, और हम इसकी क्षति नहीं होने दे सकते, तो क्या इंडक्शन और रिसिस्टेंस से बिजली की क्षति रोकने के उपाय किए जा रहे है या केवल कैपेसिटरों से इंडक्शन द्वारा होने वाली क्षति ही रोकी जा रही है? मेरे विचार में इस संबंध में कोई कठिनाई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम परिणमन, वितरण या पारेषण में बिजली की क्षति में कमी करने का प्रयास कर रहे है, इस संदर्भ में राज्य सरकारों को दिए गए सुझावों में कैपेसिटर लगाने का सुझाव भी शामिल है, इस समस्या के ध्यान देने योग्य और भी पहलू है, जैसे कंडक्टरों का प्रयोग और अधिक संख्या में पारेषण लाइनें तथा विभिन्न प्रणालियों का समेकित परिचालन जो कुछ समय के लिए अधिकतर राज्यों के आधार पर है। बड़े राज्यों में इस के एकछोर के लिए पड़ोसी राज्य के बिजली घर से बिजली लेना बेहतर होगा न कि उसी राज्य के दूसरे छोर से जिससे कि बिजली की हानि होती है। इन सभी बातों पर तुरन्त ध्यान देना होगा जिसके लिए मंत्रालय में एक समिति बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही अपेक्षित है, तब हम नए सिरे से राज्यों के बिजली बोर्डों से बातचीत करेंगे।

श्री डी० डी० देसाई : यह क्षति रोकने के लिए बिजली पैदा करने के लिए, अतिरिक्त प्रतिष्ठापित तथा आपरेटिंग पुंजीगत उपकरणों की आवश्यकता होगी और पारेषण और वितरण कार्यों के निरन्तर बचत होगी। क्या मंत्री महोदय के पास कैंपेसिटरों और बडे कंडक्टरों पर आने वाली अतिरिक्त लागत और नए विद्युत प्रजनन उपकरणों की लागत तथा क्षति रोकने से लाभ तथा प्रेषण तथा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने संबंधी आंकडे है तथा दूसरी ओर यदि इन्डक्शन और रिजिस्टेन्स में जितनी बचत होगी यदि उतनी क्षमता की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापत की जाये तो उस पर कितनी लागत आयेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इसका उत्तर न दे सकूंगा फिर भी केपेसिटरों आदि लगाने में ही काफी पूंजी व्यय होगा और ऐसा संतुलन रखना होगा जिससे व्यय की गई पुंजी का अधिकतम लाभ हो सके और जिस संतुलन की कल्पना माननीय सदस्य ने की उसके लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन करना होगा।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने बताया है कि पारेषण में बिजली की क्षति रोकने के लिए काफी पुंजी व्यय करना होगा और उन्हीं के अनुसार क्षति 18.3 प्रतिशत है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान स्थितिमें साधारण क्षति कितनी मानी जानी चाहिये और क्या इसमें का अन्तर इतने भारी पुंजी व्यय के लिए न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि कुछ बिजली बोर्डों के बिजली के घाटे बहुत अधिक है, कहीं कहीं 30 प्रतिशत है जबकि 18.3 प्रतिशत तो औसत है। वर्तमान व्यवस्था से भी सभी बोर्डों में वही लोड प्राप्त नहीं किया जा सकता?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विशेषज्ञों के अनुसार पांचवीं योजना के अन्त में हमें इस क्षति को 14 प्रतिशत तक घटा देना चाहिये। पूंजी कम अधिक होने का यह अर्थ नहीं है कि यह व्यय नहीं किया जाएगा। मैं यह खर्च करना तो चाहता हूं परन्तु तभी जब से इससे अधिकतम लाभ होता हो। कुछ हद तक क्षति को बर्दाश्त की जा सकती है परन्तु इसमें वृद्धि होने पर कहीं अधिक व्यय करना होगा जो ठीक नहीं है।

यह ठीक है कि राज्यों में यह क्षति समान नहीं है, जैसे पंजाब में यह अधिकतम लगती है, अर्थात 35.46 प्रतिशत और उडीसा में जो दामोदर घाटी निगम का क्षेत्र है, वहां क्षति सबसे कम अर्थात 13.46 प्रतिशत है। इसके कारण सरल नहीं है। एक कारण तो पंजाब में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच जाना है जिसके लिए लम्बी पारेषण लाइने लगी हुई है जबकि डी० बी० सी० में कोयला खानें और इस्पात संयंत्र एक ही क्षेत्र में जुडे हुए हैं अतः क्षति न्यूनतम है दूसर पंजाब में कुछ क्षेत्रों मीटर नहीं है और एक मुष्ट आधार पर बिजली बेची जाती है। और भी कई कारण है।

श्री एच० एम० पटेल : प्रत्येक राज्य में ग्राम विद्युतीकरण से तो लम्बी लाइनें बनेंगी ही, फिर भी कुछ राज्यों में यह क्षति 20 प्रतिशत से कहीं कम है। 35 प्रतिशत तो असाधारण है। लगता है कि पहला कदम तो यह उठाना होगा कि वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक राज्य में बिजली की क्षति अनुकूल राज्य की स्तर तक कम की जाये जहां ग्राम विद्युतीकरण काफी हद तक हो चुका हो।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कार्यवाही के लिए अच्छा सुझाव है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों ने शिकायत की है कि विभिन्न बिजली घरों में विभिन्न कारणों से स्थापित क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। पांच कारण बताए गए हैं—(1) उन्हें दिया गया कोयला मिलावट वाला है, (2) देसी उपकरणों की किस्म खराब है, (3) विदेशों से अतिरिक्त पुर्जों आदि मंगाने के मामलों में अत्यधिक सरकारी विलम्ब जो कुछ मामलों में 12 मास तक का है, और अन्ततः (4) रखरखाव व्यवस्था के त्रुटियाँ जिनके परिणाम स्वरूप केंद्रीय एवं राज्यों के स्तर पर मशीनी एवं बिजली ोनों की अच्छी वर्कशापें नहीं है जहां मरम्मत सुविधाएं उपलब्ध हो, इन कारणों से स्थापित क्षमता कभी प्राप्त नहीं हो सकती, इस संदर्भ में क्या मंत्री महोदय इन पर विचार करेंगे और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए वह क्या ठोस उपाय करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव अच्छे है और मंत्री महोदय को उन पर ध्यान देना चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : ये सुझाव ही नहीं है — ये तो बिजली बोर्डों द्वारा उठाई गई समस्याएं है और इस प्रश्न से संबंधित है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस तर्क पर उत्तर नहीं दूंगा यद्यपि यह मूल प्रश्न से संबंधित नही है फिर भी मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं।

यहां पर हम केवल हानि की चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग के बारे में बता रहे है। अतः यह वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बातें उठाई है वे निश्चय ही क्षमता के उपयोग के बारे में प्रासंगिक है। कोयले तथा फालतू कल पूर्जों के बारे में विशेष रुप से हम अत्यधिक ध्यान दे रहे है और कुछ कोयला खानों को कुछ बिजलीघरों के साथ जोडने का हम भरसक प्रयास कर रहे है? जिससे उन्हें पता चल जाये कि उन्हें किस प्रकार का कोयला मिलने की आशा है और वे उसी के अनुसार तैयारी कर सकें। भारी

योजनाओं में भी हम कोयला खानों को बिजली घरों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे है। 'ऐश' की मात्रा में अलग अलग है और यह इतना सुगम सिद्ध नहीं हो रहा है जैसा कि यह दिखाई देता है ।

फालतू कल पूर्जों के बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम आर्डर देने और सप्लाई प्राप्त करने के समय को घटाने के बारे में प्रयास कर रहे है और जहां जहां राज्य विद्युत बोर्ड ने हमारी सहायता मांगी है, केन्द्र उस प्रत्येक मामले में सहायता कर रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह प्रश्न क्षमता के उपयोग के प्रश्न से उठता है । यही कारण है कि मैंने यह प्रश्न पूछा है ।

श्री नवल किशोर सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमें पारेषण में भारी घाटा हुआ है, क्या सरकार तापीय बिजली घरों को उपभोग क्षेत्रों के यथासंभव बिलकुल निकट स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जिससे पारेषण लाइनों को कम किया जाये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसके विपरीत भी विचार है जो यह है कि विद्युत प्रजनन केन्द्र को उस क्षेत्र के निकट स्थापित किया जाना चाहिये जहां खान के मुहाने आदि पर इंधन की उपलब्धता हो । अतः इन सभी मामलों में सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि प्रत्येक मामले पर विचार किया जाये और विभिन्न कारणों का संतुलन करके किसी निर्णय पर पहुंचा जाये ।

फारस की खाड़ी वाले देशों से अशोधित तेल की सप्लाई

*84. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी वाले देशों से इस समय प्रति वर्ष कितनी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया जाता है;

(ख) हाल ही में अक्तूबर 1973 के पश्चिम एशियाई युद्ध का देश को होने वाली अशोधित तेल की सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) सरकार का तेल की कमी को कैसे दूर करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) इस समय खाड़ी के देशों से प्रति वर्ष 135.0 लाख मी० टन कच्चे तेल का आयात किया जाता है ।

(ख) कच्चे तेल की सप्लाई में कुछ कमी हुई थी परन्तु देश की अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति से के लिए हर सम्भव प्रयास किए गए ।

(ग) तेल उत्पादक देशों से द्विपक्षीय संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि कच्चे तेल की सप्लाई निरन्तर बनाई रखी जा सके। देश में ही स्थल तथा समुद्र तट से दूर कच्चे तेल की खोज तथा उसके विकास के लिए भी प्रयास बढा दिए गए है। इस बीच तेल उत्पादों के गैर आवश्यक उपभोग में यथासम्भव कमी की जा रही है और देश में ही उपलब्ध होने वाले इंधन के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे है ।

Shri Shankar Dayal Singh : In my opinion there are two aspects about the oil imported in our country from the Persian Gulf Countries—one is commercial and the other is political. After the Arab-Israel War, the oil is being used more for political purposes than for the commercial. In this context may I know from the hon. Minister as to how

much difference has come in the prices and imports before and after the Arab-Israel War. What is the quantity of crude oil to be purchased from the Persian Gulf Countries and its total value ?

श्री देवकान्त बरूआ : गत वर्ष अर्थात वर्ष 1973 में हमने 133.8 लाख टन खरिदा था। इस वर्ष अनुमान है कि हम इन देशों ह 160.3 लाख टन खरिदेंगे। हम इन देशों से तेल खरिदते हैं, ईरान 19.4 लाख; सऊदी अरब 40.1 लाख और इराक 20.8 लाख। मूल्यों में 15 अक्तुबर से वृद्धि हुई है। यह मूल्य 1160 डालर तक बढ़ गये हैं। यह प्रचलित मूल्य हैं लेकिन कुछ देश से आस्थगित भुगतान के रुप में, भुगतान करने के मामले में हम कुछ रिआयातें पाने में सफल हुए हैं। इनमें से दो देश इराक और ईरान है। सउदी अरब के साथ भी हम इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसा होने पर यदि हम प्रति बैरल 10 डालर की रिआयत प्राप्त करते हैं तो भी इस पर हमें प्रति वर्ष लगभग दस सौ से बारह सौ करोड रुपये का व्यय करना पडेगा।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, as I have already mentioned that after the West Asian War the Gulf Countries are using the oil not as a commercial source but as a political weapon and the countries mentioned by the hon. Minister are almost the same countries who have participated recently in the Islamic Conference held at Lahore. May I know whether it is a fact that in the Islamic Conference held at Lahore, Pakistan has impressed upon those countries to stop oil supply to India in time of need? Whether it is in the knowledge of the Government of India or not ?

श्रीं देवकान्त बारुआ : मुझे यह जानकारी नहीं है।

Mr. Speaker : Why you are making a reference of summit conference and Islamic Conference. It is not relevant on this occasion.

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether it is a fact that the shortage of crude oil has been effecting the supply of diesel oil and as a result of it the pumping sets in villages have stopped working and the rabi crops is being destroyed.

Mr. Speaker : Have you read the question ?

Shri Ramavatar Shastri : The main question relates to it.

Mr. Speaker : Why are you asking irrelavant questions ?

Shri Ramavatar Shastri : Oil is related with diesel and therefore, I am asking this question.

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जाये। तत्संगत प्रश्न पूछें।

Shri Bibhuti Mishra : This question arises because the hon. Minister has stated in his reply that the oil is being used for the development of the economy of the country. Therefore the question arises what percentage of diesel oil is being used in connection with cultivation out of the total diesel oil supplied. This question has been asked specifically because the rabi crops is being destroyed due to the shortage of diesel oil.

Mr. Speaker : Then the question will arise about quantity of diesel oil is being supplied to the factories and for the vehicles. We have yet to make discussion on President's address and such questions may be asked at that time. The main question relates to the quantity of annual import. I am not allowing this.

Shri Bibhuti Mishra : I am rising on a point of order. The hon. Minister has stated in his reply that the diesel oil is being supplied for the development of country's economy. I want to know whether the crops production comes under the Indian economy or not ? If it is so, I want to know the percentage of diesel oil is being supplied for cultivation ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न तत्संगत नहीं है। मैं इसे पूछने की अनुमति नहीं देता।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether it is a fact that after the oil crisis, Caltex, Burma Shell and ESSO's crude oil supply has been cut and if it is so, whether the hon. Minister will place the figures in the regard on this Table of the House. I also want to know whether after obtaining 74 percent shares the ESSO has imposed a condition that the Government of India should have to make its own arrangement for 74 percent of crude oil ?

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक इन तेलसंशोधन कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई का प्रश्न है, इस में मामूली सी कमी हुई है। सऊदी अरब ने 20 प्रतिशत कटौती की सूचना दी थी। लेकिन जब हमने सऊदी अरब सरकार से इस सम्बन्ध में चर्चा की तो वह बिना कटौती तेल सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया।

बर्मा शैल ने हमें सूचित किया है कि यद्यपि उन्हें अपना समस्त तेल ईरान से प्राप्त हुआ है और इरान ने तेल की सप्लाई में कोइ कटौती नहीं की है फिर भी यह देखते हुए कि प्राय: समस्त देशों से प्राप्त होने वाले तेल में कमी हुई है, उसे 15 प्रतिशत तेल की कटौती लागू करना पड़ेगी।

काल्टेक्स ने भी इस आधार पर 12 प्रतिशत कटौती की सूचना दी है। काल्टेक्स को भी तेल की सप्लाई ईरान द्वारा ही की जाती है।

Shri Madhu Limaye : Have you permitted to do so ?

Shri D. K. Borooah : We have not permitted them to do so. We have not agreed to this, but they have said that they have intended this.

श्री मधु दण्डवते : काल्टेक्स अथवा सरकार किसके नियंत्रण में है?

श्री डी० के० बरुआ : तेल के मामले में यह कहना कठिन है कि अब किसका नियंत्रण है। यहां तक की हमारे से भी अधिक शक्तिशाली देशों का भी शोषण हुआ है। गत तिमाही में हमारे उत्पादन में कमी हुई है और हमें यह पता लगता है कि उक्त कमी 6.22 प्रतिशत है।

इस बीच इराक और ईरान हमें अधिक तेल सप्लाई करने पर सहमत हो गये ह जिससे उक्त तेल शोधक कारखानों द्वारा की गई 6.22 प्रतिशत की कटौती में कुछ सुधार होगा।

श्री आर० एस० पाण्डे : तेल के अन्तर्राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुए और इराक, ईराण और सऊदी अरब द्वारा हमें तेल की सप्लाई कर जिस सद्भावना का परिचय दिया है क्या हमने कुछ और देशों से उन्हीं शर्तों पर भारत को तेल सप्लाई करने का अनुरोध किया है।

दूसरे सदन बम्बई में गहरे समुद्र में तेल निकालने के बारे में भी जानना चाहेगा। इस बारे में क्या स्थिति है। हम यह जानना चाहेगें कि उसकी क्षमता कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न खाड़ी के देशों से तेल से सम्बन्धित है।

श्री आर० एस० पाण्डे : मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं। यदि माननीय मंत्री देश में हाल ही में पता लगे तेल के बारे में जानकारी दें तो बहुत उचित होगा यदि आप इसकी अनुमति देंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा। अन्यथा मैं इस प्रश्न पर जोर नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए यह उचित नहीं होगा।

श्री आर० एस० पाण्डे : प्रश्न का भाग (ग) निम्नलिखित है :-

"कि सरकार का तेल की कमी को कैसे दूर करने का विचार है ?"

अत: मूल प्रश्न का भाग (ग) इसके अन्तर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननिय मंत्री इस मामलेपर उत्तर देने की स्थिति में हैं तो मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है ।

श्री डी० के० बरुआ : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मैं इस मामले पर एक विस्तृत विवरण देना चाहूंगा । लेकिन इस समय इस मामले पर विस्तृत वक्तव्य देना मेरे लिये कठिन होगा क्योंकी यह एक व्यापक और नाजुक विषय है ।

श्री एस० ए० शमीम : नाजुक विषय !

श्री देवकान्त बरुआ : नाजुक नहीं बल्कि जटिल विषय है । जहां तक तेल के सम्बन्ध में अन्य देशों से अनुरोध करने का 'प्रश्न है,' हमारे लिए ऐसा करना आर्थिक दृष्टिसे लाभप्रद नहीं होगा क्योंकी खाड़ी क्षेत्र हमारे निकट है । अन्य देशों से तेल प्राप्त करना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा ।

श्री सी० के० चन्द्राप्पन : माननीय मंत्रि ने यह उल्लेख कियां है कि कुछ तेल कम्पनियां जैसे काल्टेक्स और बर्माशैल ने हमें अपने अशोधित तेल की सप्लाई में कुछ कटौती की है । क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि इनमें से कुछ कम्पनियों ने जो अन्तर्राष्ट्रिय तेल उत्पादक है, मूलतः भारत को दिय जाने वाले तेल की सप्लाई अमरीका, ब्रिटन तथा अन्य देशों को की है, जिनकी तेल की सप्लाई में अरब देशों ने कटौती कर दी है ?

श्री देवकान्त बरुआ : अरब देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मित्र देशों को दिये जानेवाले तेल को अन्य किसी देश को नहीं दिया जायेगा। जहां तक कम्पनियों का सम्बन्ध है, उन्होंने हमें सूचित किया है कि भारत को दिये जाने वाला तेल भारत को भेजा गया है और उसे किसी अन्य देश को नहीं दिया गया है । काल्टेक्स ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि वह इराम से भारत में अशोधित तेल का आयात करती है फिर भी वह इस क्षेत्र में अपने सम्बद्ध देशों और ग्राहकों के लिये अन्य खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में तेल का आयात कर रही है । उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है है कि भारत तथा अन्य देशों को दिये जानेवाला तेल अमरिका को सप्लाई नहीं किया जायेगा ।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : तेल के मूल्य के सम्बन्ध में भारत और ईरान के बीच हाल ही में हुई व्यवस्था अथवा समझौते का, विशेषकर देश पर तथा उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री डी० के० बरुआ : ईरान से विशेष मात्रा में तेल की सप्लाई के बारे में करार किया गया है । वह भविष्य में भुगतान करने की प्रणाली पर भी सहमत हो गया है । मूल्य के एक विशेष भाग का भुगतान अब किया जायेगा और बाकी का भुगतान आगामी पांच वर्षों में पांच किश्तों में किया जायेगा । अतः जहां तक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का सम्बन्ध है, हमें इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कुछ राहत मिलेगी ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उपभोक्ताओं के विचारानुसार स्थिति क्या है ?

श्री डी० एन० तिवारी : क्या तेल की सप्लाई की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को तेल की सप्लाई के मामले में प्राथमिकता देगी ?

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक डीजल तेल की सप्लाई का सम्बन्ध है, इसका प्रयोग अधिकांश औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता है । हमने डीजल तेल का उत्पादन और इसकी उपलब्धता को उसी स्तर पर बनाये रखा है । भट्टी के तेल के उत्पादन में 10 प्रतिशत कमी हुई है अतः हमने तकनीकी विकास महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो इस बात की और ध्यान देगी कि इसका आबंटन यक्ति-संगत तथा उचित आधार पर किया जाये ।

औषध उद्योग पर भट्ठी तेल की कमी का प्रभाव

*85. **श्री एम० सुदर्शनम्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग पर भट्टी तेल की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) औषध उद्योग से अभ्यावेदन मिले है जिनमें भट्ठो के तेल की कमी के बारे में शिकायत की है ।

(ख) विभिन्न उद्योगों को भट्टी के तेल की सप्लाई का नियतन करने के लिए महानिदेशक तकनीकी विकास और सचिव की अध्यक्षता के अधीन एक स्थाई समिति की स्थापना की गई है ।

श्री एम० सुदर्शनम् : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भट्टी-तेल देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में नियुक्त स्थायी समिति से भट्टी तेल के आबंटन के मामले में निर्यात उद्योग को उच्चतम प्राथमिकता देने का अनुरोध करेंगे जिससे वे देश के लिये अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : हमने औषध उद्योग को खाद्यान्न में सहायता देने वाला प्राथमिक उद्योग स्वीकार किया है। 10 करोड़ रुपये की औषधियों का निर्यात करने के अतिरिक्त हमने यह निर्णय किया है कि देश में औषधियों का उत्पादन अधिकतम स्तर पर होता रहे और भट्ठी-तेल की कमी का निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सचिव और महानिदेशक तकनीकी विकास की अध्यक्षता में स्थापित स्थायी समिति से अनुरोध किया गया है कि वह खपत पर सामान्य 10 प्रतिशत कटौती की शर्त न लगाकर औषध उद्योग की भट्टी के तेल की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे, समिति से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह ऐसे एककों को भट्टी तेल के आबंटन में वृद्धि करें जो इसका प्रयोग उत्पादन बढाने में करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Oil is very necessary in Drug Industry. You have accepted that their requirements would be fulfilled to some extent. I want to know the quantity of oil consumed by this industry and the cut imposed thereto. I also want to know when the committee will submit its report and the names of its members ?

Shri D. K. Borooah : It is a distribution committee and it is not going to submit any report. They have been told that the drug industry cannot work with coal and furnace oil not in much quantity is required for it. This industry substitutes and export medicines. Medicines are essentials for man's life. So we should continue this industry.

Shri Hukam Chand Kachwai : How much furnace oil is consumed every year.

Shri D. K. Borooah : It does not cost very much.

श्री एस० आर० दामाणी : अनेक वर्षों से चली आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बात का कोई संकेत दिया गया है और क्या इस बारे में पता लगाया गया है कि मंत्रालय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को

किस सीमा तक पूरा करने में सम्भव होगा जिससे वे उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अग्रिम योजना बना सकें और क्या इस कमी को दूर करने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है ।

श्री देवकान्त बरुआ : इसका उत्तर बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। उक्त समिति ने चार श्रेणियों के उद्योगो के बारे में निर्णय किया है। सर्वप्रथम वे ग्राहक है जो तकनीकी आधार पर भट्ठी तेल का प्रयोग करते है और उक्त तेल की मात्रा 560,000 किलो लिटर होगी, श्रेणी 'ख' में वे ग्राहक आते है जो बहुत अधिक परिवर्तन कर तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग कर सकते है और इस पर बहुत अधिक पूंजी विनियोजन होगा और उसमें छ: महीने से लेकर 1 वर्ष का समय लगेगा । उन्हें 15,28,000 किलो लिटर की आवश्यकता होगी। तीसरी 'ग' श्रेणी में वे ग्राहक आते है जो मामूलीसा परिवर्तन कर 3 से 6 महीने की अवधि में तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग कर सकते है । उनकी आवश्यकता 362.7 हजार किलो लिटर है । श्रेनी 'घ' के अन्तर्गत वे ग्राहक आते है जो शीघ्र ही तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग कर सकते है । बशर्तें उन्हें अपेक्षित किस्म और मात्रा में कोयला उपलब्ध हो। उनकी आवश्यकता लगभग 622,000 किलो लीटर होगी। यदि ऐसा किया जाता है तो मेरे विचार से देश में भट्ठी तेल की कोई कमी नहीं होगी।

श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में लघु इस्पात पुनर्वेलन उद्योग को भट्टी तेल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्या सरकार उक्त समिति से इस समय उद्योग के सामने आ रही कठिनाईयों की ओर ध्यान देने का अनुरोध करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न औषधियों से सम्बन्धित है ।

श्री अण्णासहिब गोटखिडे : समिति विभिन्न उद्योगों की साप्लाई नियमित करने के लिये नियुक्त की गई है । उत्तर में ऐसा कहा गया है यद्यपि मूल प्रश्न औषध उद्योग से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न उद्योग से सम्बन्धित है ।

श्री अण्णासाहेब गोटखिण्डे : कृपया मुझे संरक्षण दें। उत्तर यह है कि समिति की नियुक्ति विभिन्न उद्योगों को साप्लाई नियमित करने के लिये की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपाया बैठ जायें । मंत्री महोदय से औषध उद्योग के बारे में पूछा गया था ।

श्री देवकांत बरुआ : मेरा मंत्रालय पेट्रोलियम और रसायन से सम्बन्धित है । पुनर्वेलन मिलें औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आती है ।

अण्णासाहेब गोटखिण्डे : : मै यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त समिति पुनर्वेलन उद्योग को हो रही कठिनाइयां के बारे में जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न औषध उद्योग से सम्बन्धित है । आप अपने प्रश्न को उक्त उद्योग तक ही सीमित रखे अच्छा होगा यदि आप जब अन्य मंत्री आये तब उक्त प्रश्न पूछें ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं अपना प्रश्न औषध उद्योग तक ही सामित रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : किस प्रकार की औषधियों तक ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि भट्टी तेल की कमी के नाम पर बड़े बड़े औषध निर्माणकर्ता अत्यावश्यक औषधियों का उत्पादन घटाने का प्रयास कर रहे है और यदि हां, तो सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही कर रही है **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री देवकान्त बरुआ : उत्तर सरल है वे इस बात का तर्क नहीं दे सकते ।

इंधन संसाधनों को सुरक्षित रखने के उपाय

*87. **श्री श्रीकिशन मोदी** † :

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंधन संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार किन्हीं नए उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) देश में उपलब्ध उर्जा स्त्रोतों के अधिकतम प्रयोग से विशेष रूप से तरल इंधन के स्थान पर कोयला, विभिन्न औद्योगिक एककों तथा रेलवे को मिला कर परिवहन उपक्रमों के अधिकतम-परिचालनात्मक इंधनदक्षता प्राप्त करके, इंधन संसाधनों विशेष रुप से तरल इंधन को, बनाए रखने के लिए अनेक तत्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Shrikishan Modi : I want to know whether a meeting of the State's Chief Ministers has been called to discuss to economise in the use of petrol for there vehicles ? I also want to know the number of vehicles reduced by the Administration. and whether any scheme has been formulated to reduce the use of petrol ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : हमने विभिन्न राज्य सरकारों से इस बारे में विचार विमर्श किया है और उन्हें अपने वाहनों में पेट्रोल के प्रयोग में कमी करने के लिये पत्र और परिपत्र लिखे है । हमने सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न विभागों और विभिन्न सरकारी क्षेत्र संगठनों को यह सलाह दी है कि उन्हें अपनी पेट्रोल की खपत में कम से कम 15 प्रतिशत की कमी करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में हमने उन्हें मार्गदर्शक सिद्धान्त भी बताये हैं । जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है हमने उनके पट्रोल के कोटे में 10 लिटर प्रति दिन अर्थात् 300 लिटर प्रतिमास की कमी कर दी है । उससे अधिक पैट्रोल का प्रयोग करने पर मंत्री को स्वयं अपनी जेब से भुगतान करना होगा ।

Shri Shrikishan Modi : The hon. Minister has stated in his reply that coal will be used in place of oil in the Railways. I want to know whether the Ministry of Railways have been consulted in this matter ? I want to know whether it is not a fact that with the use of oil, the efficiency of the railway is increasing and so it is not economical to use coal in the Railway ?

Shri D. K. Borooah : Consultations are going on in this matter. It is true that we want to reduce the consumption of oil. But we do not like to do so at the cost of the efficiency.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Some people have tried to start motor car with the help of domestic gas. This experience has proved successful too. I want to know when motor car can be run with the help of domestic gas and when gas is also available in adequate quantity, the reasons for not giving permission for it by the Government ?

Shri D. K. Borooah : If preference has to be given out of 'meals' and 'travel', preferences should be given to 'meals'.

Shri Madhu Limaye : If the domestic gas runs short then the women will rise.

Shri D. K. Borooah : One thing is there. There is danger in using the gas. It is full of dangers.

Dr. Kailas : The hon. Minister has instructed to Chief Ministers, Public Sector Organisations and his colleagues not to consume more than 300 litres petrol per month then how far it was observed and how much petrol was saved......

Mr. Speaker : What are you asking ? The question is in regard to measures taken and he has stated the same.

Dr. Kailas : How much benefit was accrued from the measures ?

Mr. Speaker : You ask it in the next session. How he can tell you so early ?

Dr. Kailas : Is the hon. Minister going to ration it or not because from one of his speeches it was hinted that he is rationing it from 1st April. Such contradictory statements are not good in the interest of the country.

Shri D. K. Borooah : I have not said that rationing will be effected.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय सरकारी क्षेत्र के निगमों के अधिकारियों को, जिन पर पेट्रोल की सप्लाय नियमित करने का कार्यभार है, पेट्रोल की खपत सफल पूर्वक कम करने पर किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने पर विचार करेंगे ? दुसरा, पेट्रोल की खपत कम करने के लिए महुआ फूल से एल्कोहल और कोक भट्टी संयंत्र से उप-उत्पाद 30 प्रतिशत मिलाया जा सकता है, जैसा कि 1948 से 1952 की अवधि के दौरान किया गया था, विशेषकर क्योंकि छोटानागपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में महुआ के पेड हैं और इसका उपयोग बड़ी सफलता पूर्वक पट्रोल के साथ मिलाने में किया जा सकता है।

श्री डी० के० बरुआ : इस नीति में यह निर्देश भी हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी अनावश्यक यात्राओं को बंद करें।

पोंग बांध के विस्थापितों को भूमि का आवंटन

*88. **श्री विक्रम महाजन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए दो लाख एकड़ भूमी नियत की गयी थी;

(ख) कितने विस्थापितों का अब तक पुनर्वास किया गया है और 18 फरवरी, 1974 तक उन्हें कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है; और

(ग) बाकी बचे व्यक्तियों को कब तक भूमि का आबंटन होने और उनका पुनर्वास करने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) राजस्थान सरकार ने पोंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में 2.25 लाख एकड़ भूमि अलग रखी हुई है।

(ख) राजस्थान सरकार ने लगभग 7400 विस्थापितों को पहले ही 1.10 लाख एकड़ भूमि आबंटित कर दी है।

(ग) आशा है कि चालू वर्ष के दौरान अधिकतर विस्थापितों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के चरण-एक में भूमि आबंटित कर दी जाएगी।

श्री विक्रम महाजन : 11 मार्च 1970 को तत्कालीन मंत्री महोदय ने इस सभा में निम्नलिखित आश्वासन दिया था ।

"मेरे विचार में 12,000 परिवार को बेदखल किया जायेगा .... मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इन विस्थापितों को बताया नहीं जायगा तब तक हम पानी को रोकने की अनुमति नहीं देंगे",

सरकार के अधिसूचना के अनुसार पानी को रोकने का कार्य जून 1974 को किया जायेगा, अब मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि अब तक 7,400 विस्थापितों को बसाया गया है जिसका मतलब है कि लगभग 5,000 से 6,000 विस्थापितों को अभी बसाया जाना है, मैं जान सकता हूं कि क्या इस आश्वासन को पूरा किया जायेगा ? क्या जून 1974 में पानी को रोकने के कार्य से पूर्व उन्हें अन्यत्र बसाया जायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं ठीक-ठीक महीना अथवा तारीख नहीं बता सकता हूं । जैसे कि मैंने कहा है की अधिकांश विस्थापितों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के चरण एक में चालू वर्ष के दौरान भूमी दी जायेगी, मैं इस संबंध में माननीय सदस्य का सहयोग चाहता हूं कि वह उन लोगों को, जिन्हें भूमि अलाट की गई है, अपने स्थान में जाने को कहें । यहां तक कि जिन विस्थापितों को भूमि आबंटित की गई है, वे इस स्थान में नहीं गए है, इसलिए भूमि आबंटित करने के मामले में रुकावट होने का प्रश्न नहीं है । यह समस्या विस्थापितों द्वारा अपने स्थानों में न जाने से है ।

श्री विक्रम महाजन : मंत्री महोदय ने कहा है कि विस्थापितों को भूमि आबंटित की गई है और सभी विस्थापित उन स्थानों में नहीं गए है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कितने विस्थापितो कों भूमि आवंटित की है तथा उनमें से कितने इन स्थानो को नहीं गए हैं, दूसरा कुछ लोगों को जो भूमि दी गई है, वह कृषि योग्य नहीं है क्योंकि वहां सिचाई की सुविधाएं नहीं है, क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उन विस्थापितों को नई भूमी दी जायेगी जिन्हे जो भूमि दी गई है वह सिचाई सुविधाओं से रहित है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लगभग 7,400 विस्थापितों को भूमि के आबंटिन की गई है परतु उनमे से केवल 5,025 विस्थापितों निर्धारित अवधि के दौरान उन स्थानों में गए हैं । लगभग 4,788 मकान निमित किए गए हैं और अब तक केवल 85 विस्थापित उनमे गए हैं ।

श्री विक्रम महाजन : विस्थापितों कों भूमि के आवंटन का प्रश्न मकानों के आवंटन से भिन्न है ।

Shri Shrikishan Modi : The Rs. 100 crores meant for backward Rajasthan have been taken away openly and spent on Pong dam. I want to know that out of 7,000 oustees who have been alloted land, how many of them have taken possession of land and how many of them have came back indirectly from there after selling the land at Rs. one lakh ? I also want to know whether you will get the matter examined impartially and if it is proved correct that osutees have came back after selling their land then would you take the land from them and distribute it among those poor harijans who were deprived of their land years ago.

Shri K. C. Pant : I have given you information that 5025 oustees have taken possession of land within the stipulated time. Regarding the sale of land, I have no information at present.

Adulteration of Petrol Due to Increases in its price

89. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether all sorts of adulteration in petrol is being done due to recent increase in the price of petrol, and

(b) if so, the steps taken by Government in this connection ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि के बाद, मोटर स्पिरिट की मिलावट की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस प्रकार की मिलावट रोकने के लिये भारत सरकार ने निम्न प्रकार उठाये हैं :–

(i) राज्य सरकारों को सतर्क रहने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने का परामर्श दिया गया है।

(ii) सरल उद्धरणों से एक इश्तहार बनाया गया है जिसे तेल कम्पनियों के पैट्रोल पम्पों पर लटकाया जाएगा। ऐसी मिवालट का पता लगाने के लिये सरल तरीकों के बारे में मोटर चालकों को शिक्षित करना इस इश्तहार का आशय है।

(iii) मिट्टी के तेल को रंगदार बनाने के लिये किसी उपयुक्त काले रंग की खोज करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। रंगदार मिट्टी का तेल जब मोटर स्पिरिट में मिलाया जाएगा तो इसका आसानी से पता लग जाएगा।

Shri Lalji Bhai : I want to know when the scheme of surprised raid for collecting samples from Petrol Pumps for checking will be started and secondly, when it will be made legally compulsory for every Petrol Pump to make available plant for checking of adulteration in petrol on the spot.

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) : It is very simple to detect kerosene in petrol about which I have already given informations in the House. If more than ten percent kerosene is mixed in the petrol, the adulteration can be detected. So there is no need of any sophisticated plant to check it.

Shri Lalji Bhai : When the surprised raid to collect samples will be started ?

Shri D. K. Borooah : The scheme has been put into effect.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of plants for producing petrol from coal in states

*81. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state;

(a) whether Government proposes to set up a plant in Bihar for producing petrol from coal;

(b) if so, the main features in this regard; and

(c) whether Government are considering the proposal of setting up such plants Madhya Pradesh and other States also?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) : (a) to (c) On the basis of the exploratory studies made so far by the National Committee on Science and Technology and the Planning Commission, it has been decided to set up a group to make a feasibility study for establishing a plant for the manufacture of oil from coal. Further decision regarding implementation will be taken on the basis of this report.

पश्चिमी बंगाल से बंगला देश होते हुए त्रिपुरा तक सीधी रेल सेवा

*82, **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और बंगला देश की सरकार के बीच पश्चिम बंगला से बंगाल देश होते हुए त्रिपुरा तक सीधी रेलवे सेवा चालू करने के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले को पुनः बंगला देश सरकार के साथ उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी क़ुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) बंगला देश होकर भारत से त्रिपुरा को माल यातायात के मामले पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय उर्वरक निगम का नया आधुनिक एकक

*86. **श्री गजाधर माजी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उरक निगम के एक नये आधुनिक एकक की स्थापना की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रोसेस के आधार पर अनेक संयंत्रो को कार्यान्वित कर रही है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 3 परियोजनाओं की देखरेख करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक नये निगम की स्थापना का भी विचार है ।

कालीनदी जलविद्युत परियोजना में बिजली का उत्पादन

*90. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीनदीजल विद्युत परियोजनामें अन्ततोगत्वा कुल कितनी बिजली का उत्पादन होने लगेगा;

(ख) कर्नाटक द्वारा अनुपाततः कितनी बिजली का उपयोग किया जायेगा; और

(ग) किन-किन अन्य राज्यों को इसकी बिजली मिलेगी तथा उनको मिलने वाली बिजलीका अनुपात क्या होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) कालीनदी जल-विद्युत परियोजना के चरण-एक में अंत में कुल 4,112 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष और चरण-दो में 1121 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष बिजली उत्पन्न होगी। इनमें से, अभी तक केवल प्रथम यूनिट को अंतिम रूप दिया गया है तथा उसका कार्यान्वियन आरंभ किया गया है और उससे उत्पन्न समस्त ऊर्जा का कर्नाटक में उसको भार वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के द्वीतीय्र चरण के प्रस्तावों को अभी तक जांच की जा रही है और इनके लिए लागत तथा लाभों को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और महाराष्ट्र में विभाजित करने की संभाव्यता को भी जांच की जा रही है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

*91. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एम० शिवप्पा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने गत दिसम्बर को अपनी मांगों के और समर्थन में 'एकता दिवस' मनाते हुए कोई सांकेतिक हड़ताल की थीं।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने 3 दिसम्बर, 1973 को "तेल एवं प्राकृतिकगैस आयोग के अधिकारियों का पूर्ण एकता दिवस" के रूप में मनाया उन्होंने उस दिन हाथ में नीली पट्टी बांधी। उन्होने कोई सांकेतिक हड़ताल नहीं की।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रबन्धमण्डल अधिकारियों के प्रतिनिधियों को साथ विभिन्न मांगों पर विचारविमर्श कर रही है दो बैठक की गई है तथा और विचारविमर्श करने का विचार है। अधिकारियों नै सामान्य रुप में कार्य करना जारी रखा है।

भारत रक्षा अधिनियम के अधीन अनिर्णीत मामलों का वापस लिया जाना

*92. क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने लोको कर्मचारियों द्वारा हाल में किये गये आन्दोलनों के दौरान लागू किये गये भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत अनिर्णीत मामलो को वापस लिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए रेलवे प्रशासन के अधिकारियों की एक उप-समिति बनाई है ;

(ख) उस उप-समिति द्वारा एसे कितने मामलों की जांच की जायेगी; और

(ग) क्या इस उप-समिति में लोको कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहमद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेल मंत्री द्वारा तीन सदस्य की एक उप-समिति का गठन किया गया है जिससे में मुख्य आयुक्त के अलावा सरकार और कर्मचारियों का एक-एक सदस्य है। यह उप-समिति उन वैयक्तिक मामलों की जांच करेंगी जिन पर लोको रनिंग कर्मचारी संघ अनुसार रेल मंत्री द्वारा 13-8-73 को संसद में दिये गये बयान के अनुसार कारंवाई नहीं की गयी है।

इस जांच में भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तोड़-फोड़, हिंसा तथा रेल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने से सम्बधित मामलों को छोडकर बाकी माम ों कों वापस लेने के सम्बन्ध में रेल प्रशासन द्वारा की गयी कारवाई पर भी विचार किया जायेगा।

कर्मचारियों की ओर से अभी तक उन वैयक्तिक मामलों की सूची प्राप्त नहीं हुई है जिन पर उप-समिति ने विचार करना है।

"करप्शन इन कोर्टस् इन इंडिया" नामक पुस्तक

*93. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री "करप्शन इन कोर्टस् इन इण्डिया" नामक पुस्तक के बारे में 11 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त पुस्तक में उल्लिखित आरोपों की इस बीच जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) पुस्तक के लेखक के अनुसार न्यायालय के सभी स्तरों पर (अर्थात् निम्नतम से उच्चतम न्यायालय तक) व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण दो मामलों में उसके तथा उसके भाई के विरुद्ध निर्णय दिया गया। पुस्तक से पता चलता है कि प्रश्नगत मामलों का निपटारा लगभग 10 वर्ष पूर्व किया गया था और निर्णयों की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कर दी गई थी। तथाकथित भ्रष्टाचार के कोई विनिर्दिष्ट ब्यौरे नहीं दिए गए है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये आरोप निर्णयों से उत्पन्न वैयक्तिक असंतोष के कारण लगाए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन पर तेल संकट का प्रभाव

***94. श्री राज सिंह देव :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तेल संकट का हमारे नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन के वर्तमान न्यनतम स्तर को बनाए रखने के लिए यदि कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, उर्वरक उत्पादन के लिये अपेक्षित पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई बनाये रखने के लिये कोई कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। हमारे उर्वरक कार्यक्रम में इस समय कोई आयात किया जाना निहित नहीं है।

Proposal for Manufacturing of Doubledecker Coaches by R.D.S.O., Lucknow

***95. Dr. Lakminarayan Pandeya :**

Shri Madhu Dandavate :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in view of the overcrowding in trains, proposal for manufacturing double decker coaches is under the consideration of Railway Research and Standardisation Organisation;

(b) if so, the salient features thereof and when they will be put to use; and

(c) whether the said Research Organisation has also made a design for increasing the capacity of the present coaches?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The proposal has been under consideration of the Railway Board and a design for the Broad Gauge Double Decker III Class coach has been developed by the Research Designs and Standards Organisation.

3—2 LSS/74

(b) The salient features of the Broad Gauge III Class Double Decker Coach are as follows:

(i) The centre portion of the coach will be "dipped" in between the two bogies to carry passengers in two decks;

(ii) It will provide sitting accommodation for 146 passengers as against 80 in conventional III class coach;

(iii) It will have two wide doors on each side for entry and exit of passengers;

(iv) There will be four lavatories, two at either end; and

(v) Exhaust fans will also be provided to improve ventilation.

The length of the Double Decker Coach will be the same as that of conventional coach viz. 70/(21,337 mm). The tare weight of the coach will be about 45 tonnes as against 38 tonnes of the conventional coaches.

One proto-type coach is expected to be manufactured by the Integral Coach Factory, Perambur, Madras, during 1976-77 depending upon the availability of imported High Tensile steel. Thereafter Oscillation trials and strain-gauging tests is likely to take about a year. Hence the coach is likely to be available for service during 1977-78 to assess service performance and public reaction before series production of this type of coach is programmed for manufacture.

(c) The Research Designs and Standards Organisation has developed two types of Broad Gauge 1st Class Chair Cars, one to provide sitting accommodation for 48 passengers and the other for 60 passengers, in reclining chairs to be used on medium and short distance trains which do not involve night journey, as against the existing Broad Gauge 1st Class coaches which provide accommodation for 36 to sit during day or 24 to sleep at night.

As against 80 seats and 40 seats in existing Broad Gauge III class and III Luggage and Brake Vans, new desings have been developed with 90 and 50 seats respectively for use on short distance day trains.

रेलवे वैगनों की अत्यधिक कमी

*96. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वैगनों की कमी कितने समय से चल रही है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कमी के आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर मालडिब्बों की इस तरह की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन लदान के लिए मालडिब्बों की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम रही है और इस पर दुष्प्रभाव पड़ने के विभिन्न कारण रहे हैं जैसे नागरिक उपद्रव, बन्द, हड़तालों और कर्मचारियों के आन्दोलनों की भर-मार, कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का बिगड़ जाना, बिजली की कटौती के कारण गाड़ी संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ना, असाधारण बाढ़, पटरी की टूट-फूट आदि जिनसे मालडिब्बों की कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है।

गत तीन वर्षों के अन्तिम दिनों तक कुल जितने मालडिब्बों का लदान हुआ और जितनी मांगे बाकी रह गयीं उनका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लादे गये कुल मालडिब्बों की संख्या		अन्तिम दिन बकाया मांगों की संख्या	
	बड़ी लाइन	मी० ला०	बड़ी लाइन	मी० ला०
1970-71 .	6,799,678	2,146,091	79,774	24,451
1971-72 .	6,867,578	2,145,145	263,703	192,988
1972-73	7,074,307	2,072,187	161,504	118,076
1973-74 . (दिसम्बर, 73 तक)	4,959,768	1,302,565	158,301	161,009

केरल तट पर तट-दूर खुदाई के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव

*97. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री ए० के० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केरल सरकार ने केरल तट पर तट से दूर खुदाई के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) :(क) जी हां।

(ख) केरल सरकार का अनुरोध क्षेत्र की तेल संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए केरल तट पर तट से दूर विस्तृत सर्वेक्षण करने से संबंधित था।

(ग) केरल तट के भागों को शामिल करते हुए अरब सागर में महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में हाल ही में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है और इस के परिणामों की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जांच की जा रही है। भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के क्षेत्रों, जिन में केरल तट के निकट के क्षेत्र शामिल हैं, के अन्वेषण के लिये कुछ विदेशी पार्टियों की पेशकशें प्राप्त हुई हैं और इनकी जांच की जा रही है।

आल इंडिया रेलवे टैक्नीशियन स्टाफ द्वारा कार्यवाही आरम्भ करने की धमकी

*98. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवे टैक्नीशियन स्टाफ ने नियमानुसार काम करने की धमकी दी है;

(ख) उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) आन्दोलन से बचने के लिए सरकार का विचार उनकी मांगों को किस प्रकार पूरा करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । लेकिन भारतीय रेलों के तकनीकी पर्यवेक्षकों ने आन्दोलन करने की धमकी दी है ।

(ख) उनकी मांगे इस प्रकार है :—

1. रेल कर्मचारियों को औद्योगिक बोनस ।

2. मिस्त्रियों को 425-640 रु०, चार्जमन को 550-900 रु०, सहायक (शाप/शैड/चालू लाइन) अधीक्षक को 840-1040 रु० और शाप/शैड/चालू लाइन अधीक्षक को 840-1200 रु० का ग्रेड ।

3. भारतीय रेलों में तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए बेहतर पदोन्नति सरणि और सभी स्तरों पर सघन पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना ।

(i) वरिष्ठ चार्ज मैन के संवर्ग (यदि चार्ज मैनों को एक ग्रेड न दिया गया हो) में 80 प्रतिशत पदों का ग्रेड बढ़ाना ।

(ii) श्रेणी i राजपत्रित संवर्ग में पदोन्नति के लिए वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत और सेवारत इंजीनियरिंग स्नातकों में से 25 प्रतिशत पदों का आरक्षण ।

(iii) मध्यवर्ती पर्यवेक्षक ग्रेड में भर्ती रोकना ।

4. शेडों और शापों में चार्ज मैनों से बेतन बक्सों की ड्यूटी वापस लेना ।

5. पो० सी० कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता देना ।

6. सहायक फोरमैन का ग्रेड (335-425 रु० प्रा० वे०) बढ़ाकर सहायक शाप अधीक्षक का ग्रेड देना ।

7. (क) सभी कारखानों (डीजल, बिजली, भाप और कार) शैडों में मिस्त्रियों, चार्ज मैनों ए० एफ० और एफ० ओ० का ग्रेड बढ़ाने के लिए मियांभाय अधिकरण पंचाट का शीघ्र और समुचित क्रियान्वयन और पंचाट को बी० आई० ओ०, एम० आई० ओ०, एफ० ई० ओ० और ड्राफ्ट मैनों पर लागू करना ।

(ख) सभी कारखाना (डीजल, बिजली, भाप और कार) शैडों में मिस्त्रियों चार्जमैनों ए० एफ० और एफ० ओ० का ग्रेड बढ़ाने के लिए वांचू अधिकरण पंचाट का शीघ्र और समुचित क्रियान्वयन और पंचाट को वी० आई० ओ०, एम० आई० ओ०, एफ० ई० ओ० और ड्राफ्ट मैनों पर लागू करना ।

8. स्वतंत्र सहायक शाप अधीक्षक का शाप अधीक्षक के रूप में ग्रेड बढ़ाना ।

9. (i) वास्तविक अतिरिक्त घंटे कार्य के लिए सभी पर्यवेक्षकों को वेतन के $1\frac{1}{2}$ गुने समयोपरि का भुगतान ।

(ii) काय घंटा विनियमन के अन्तगत चाजमैनों का "निरंतर" के रूप में पुनवर्गीकरण और कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्य घंटा के लिए पर्यवेक्षकों को शामिल न किय जाने की प्रक्रिया को हटाना ।

10. शेड और चालू लाइन के तकनीकी पर्यवेक्षकों को श्रम साध्य ड्यूटी का भत्ता देना।

11. वर्तमान परिपाटी के अनुसार नये वेतन मानों के औसत पर प्रोत्साहन कार्य घंटे की दरों में संशोधन ।

12. आई० आर० टी० एस० ए० को मान्यता प्रदान करना।

(ग) इनमें से अधिकतर मांगों का सम्बन्ध वेतन मानों से है जिनकी सिफारिश वेतन आयोग द्वारा विस्तृत रूप से साक्ष्य लेने के बाद की गयी थी और सरकार द्वारा स्वीकार की गयी थी । इसलिए इन मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं है। अन्य मांगों के सम्बन्ध में जो वेतन मानों से सम्बन्धित नहीं हैं, इन पर भी समय-समय पर मान्यता प्राप्त संघों के साथ विचार विमर्श के दौरान विचार किया है और जो भी मांगे औचित्यपूर्ण थीं उन पर कायवाई की गयी । रेल कर्मचारियों को बोनस देने के सम्बन्ध में, बोनस अधिनियम सरकारी उपक्रमो पर लागू नहीं होता। कुछ कोटियों के वेतन मानों के सम्बन्ध में, मियां भाय अधिकरण पंचाट के परिणामस्वरूम इनमें हाल ही में सुधार किया गया है।

आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ द्वारा इलैक्ट्रानिक वारनिंग सिस्टम का विकास

*99. **श्री के० माल्लना :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसर्च डिजाइन्स एण्ड स्टैण्डर्ड आरगनाइजेशन, लखनऊ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलगाड़ी के ड्राइवर किसी स्टेशन सीमा में प्रदेश करते समय "रेड सिगनल" से आगे न जाए इलैक्ट्रानिक स्वचालित चेतावनी पद्धति (इलक्ट्रानिक आटोमैटिक वारनिंग सिस्टम) का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया है। इस समय इसका परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जब ड्राइवर सिगनल के पास पहुंचता है तो चालक प्रकोष्ठ में श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के संकेत मिलते हैं। यदि सामने वाला सिगनल किसी खतरे का संकेत दे रहा होता है तो ड्राइवर को श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के संकेतों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ती है और यदि 7 सेकन्ड के अन्दर वह ऐसा नहीं करता तो ब्रैकें अपने आप लग जाती है।

'चूल्हें' के लिये नए डिजाइन का विकास

*100. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान धनबाद के वैज्ञानिकों ने हाल ही में "चूल्हे" (कोयला वाला चूल्हा) का एक नया डिजाईन निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी

Godowns for Storing Fertilizers

801. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of godowns in Madhya Pradesh where fertilisers are stocked by the Central Government as well as the total number of such godowns;

(b) whether officers of the Fertiliser Corporation of India have stopped keeping the stocks of fertilisers in some of the godowns and if so, the number of such godowns and names of the places where they are located; and

(c) whether Madhya Pradesh Government have taken some initiative in this regard and if so, the facts thereof as well as the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

मंगलौर-पानाम्बूर रेलवे लाइन का प्रयोग

802. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य लाइन के मंगलौर और पानाम्बूर हाल्ट के बीच पूरी की गई लाइन का प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मंगलौर-पानाम्बूर रेलवे लाइन को 14-10-1972 से माल यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

कर्नाटक के पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की जल-विद्युत क्षमता के लिये सर्वेक्षण

803. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी समुद्रतटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों की जल विद्युत् क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले तथा किन नदियों में जल विद्युत् क्षमता उपलब्ध है; और

(ग) इस क्षमता का कब उपयोग किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रायल में उप-मंत्री (श्री सिदधेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय जा और विद्युत् आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार कर्नाटक में पश्चिमी घाट को पश्चिमी प्रवाही नदियों को जल-विद्युत् शक्यता 60% भार अनुपात पर 3244 मेगावाट है जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :

स्कीम का नाम	नदी का नाम	60% भारत अनुपात पर विद्युत् शक्यता (मेगावाट)
वराही	वराही	192
चक्रानदी	चक्रानदी	20
शरावती	शरावती	994
अगनाशीनी	अगनाशीनी	214
काली नदी	काली नदी	1300
सोंडा	सोंडा	132
बदती	बेदती	200
बारापोले	बारापोले	144
महादायी	महादायी	48
		3244

(ग) शरावती पर 835 मेगावाट विद्युत् शक्यता पहले ही विकसित की जा चकी है। लिंगनाम को बांध विद्युत् घर स्कीम (55 मेगावाट) तथा कालीनदी चरण-एक परियोजना (782 मेगावाट) निर्माणाधीन है और 837 मेगावाट शक्यता का और विकास हो जाएगा। धन तथा अन्य साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए शेष जल शक्यता को भी उचित समय पर विकसित कर लिया जाएगा।

'बाराही' जल विदयुत् परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये कर्नाटक सरकार का सहायता के लिये अनुरोध

804. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में "बाराही" जल विद्युत् परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये किसी सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

कोचीन, मद्रास और बम्बई तेल शोधक कारखानों से कर्नाटक को ढोये गये पैट्रोलियम उत्पाद

805. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में आज तक (1) कोचीन तेल शोधक कारखाने, (2) मद्रास तेल शोधक कारखाने, (3) बम्बई तेल शोधक कारखाने, तथा (4) अन्य तेल शोधक कारखानों से कर्नाटक राज्य को उत्पाद-बार कितने पैट्रोलियम उत्पादों को ले जाया गया;

(ख) उनके मूल्य और उनकी मात्रा कितनी-कितनी है; और

(ग) इन उत्पादों की कुल ढुलाई लागत क्या है तथा क्या इन उत्पादों की कर्नाटक को शीघ्र ढुलाई किये जाने में कोई कठिनाई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है अभी उसे यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

उर्वरकों और कोयले के परिवहन के लिये कर्नाटक राज्य की मांग को पूरा करने की कार्यवाही

806. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान (अद्यतन) कर्नाटक राज्य में रेल द्वारा कितने उर्वरकों तथा कोयले की ढुलाई की गई थी;

(ख) कर्नाटक में इस अवधि में इन वस्तुओं की ढुलाई की कितनी मांग थी; और

(ग) रेल द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिये माल डिब्बों को उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) उर्वरकों और कोयले के जितने माल डिब्बों का लदान किया गया उनकी संख्या मांगपत्रों/कार्यक्रम की तुलना में नीचे दी गयी है :—

उर्वरक

(माल डिब्बों की संख्या)

वर्ष	मांग पत्र		लदान	
	बडी लाइन	मीटर लाइन	बडी लाइन	मीटर लाइन
1972-73 .	10,110	4,387	10,099	4,338
1973-74 . (जनवरी 1974 तक)	9,109	4,004	9,096	4,004

	कार्यक्रम	लादे गये बड़ी लाइन वाले डिब्बों की संख्या
1972-73	53,547	35,035
1973-74 . (जनवरी 1974 तक)	44,567	30,070

(ग) गाड़ी परिचालन को प्रभावित करने वाले विपरित कारणों के बावजूद उर्वरकों का लदान सामान्य रूप से होता रहा। कर्नाटक को कोयले का परिवहन भी संतोषजनक स्तर पर बनाये रखा गया। कर्नाटक राज्य को आवश्यक सामान की सप्लाई सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

पेट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

807. **श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से इस समय विदेशों को कुल कितने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) क्या देश में कठिन स्थिति को देखते हुये निर्यात वायदों को पूर्ण किया जाना सम्भव होगा; और

(ग) क्या निर्यात में कोई कटौती किये जाने का विचार है; और यदि हां, तो कितनी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारत से अन्य देशों जिनमें नेपाल सम्मिलित नहीं है, को इस समय प्रति वर्ष 200,000 मी० टन पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है।

(ख) तथा (ग) देश की आवश्यकताओं की तुलना में पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बहुत ही नगण्य है। ये निर्यात एतिहासिक तथा परम्परागत कारणों से किए जाते हैं। परन्तु इन निर्यातों को कम से कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Proposed Over-Bridges to be constructed in Rajasthan

808. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of new over-bridges proposed to be constructed in Rajasthan during the financial year 1974-75.

(b) the number of over-bridges for construction of which the State Government have submitted proposals to the Central Government; and

(c) the expenditure to be incurred by Government on account of construction of new bridges and over-bridges in the State during the financial year 1974-75.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No new work of road over-bridge in place of existing level crossing in Rajasthan State has been included in the 1974-75 Budget. However, 3 road over-bridges in place of existing level crossings are under construction as throwforward works and will be in progress or completed during 1974-75.

(b) In addition to the works in progress mentioned in (a) above, there are 8 more proposals from the State Government for construction of road over/under-bridges. These are in various stages of preliminary investigations.

(c) Railways' share of expenditure on construction of road over-bridges in the Rajasthan State during 1974-75 is estimated at Rs. 5.5 lakh.

Irrigation and Power Projects in U.P.

809. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of various irrigation and power projects being run by the Central Government in Uttar Pradesh at present;

(b) the number of irrigation and power projects for U. P. under consideration of Central Government at present;

(c) the total amount of financial assistance given by the Central Government to the State Government during the last two years as against the amount sought by the State Government; and

(d) the total amount of financial assistance proposed to be given to the State Government during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There is no irrigation or power project in Uttar Pradesh which is being run by the Central Government.

(b) There is no proposal under the consideration of the Central Government for a Central irrigation or power project in Uttar Pradesh, apart from the Narora Atomic Power station.

(c) The Central assistance for State Plan schemes is given in the form of block loans and grants for the State as a whole and it is not relatable to any particular project or head of development. However, the Government of India have agreed to provide assistance upto Rs. 25.72 crores out side the Plan for certain irrigation schemes in Uttar Pradesh out of the provision made for "advance action for the Fifth Five Year Plan" in 1973-74.

(d) There is no proposal at present to provide assistance for the above purpose in 1974-75 to the State Government.

Confirmation of Temporary Employees of Southern Railway

810. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees on the Southern Railway who are still temporary after having put in more than five years service; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to confirm the temporary employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 2539.

(b) A special drive has been instituted for conversion of temporary posts into permanent ones wherever justified and for confirmation of the eligible staff against such posts.

Loss of Railway Property on North Eastern Railway due to strike

811. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be Pleased to state:

(a) the value of Railway property lost during the last two years in North-Eastern Railway as a result of strike by Railway employees and political agitation; and

(b) the Government's plan to save Railway property from damage?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) Ordinarily, the State Police deal with such agitations as maintenance of law and order is their responsibility. However, on such occasions the Railway Protection Force men are also deputed to assist the police and guard railway property.

In addition, sections 122 & 126 of the Indian Railways Act, 1890 have also been amended to provide for more deterrent punishment to offenders. Another section 126-A has been added therein to deal with acts pertaining to wanton destruction of railway track, bridges, station installations and such other railway property prescribing a punishment extending up to 10 years rigorous imprisonment.

Companies registered and liquidated in Madhya Pradesh

812. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of companies with capital of more than rupees 10 lakhs registered in Madhya Pradesh during 1973; and

(b) number of companies with capital of more than rupees 10 lakhs liquidated in that state during 1973?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) 15 companies limited by shares and each having an authorised capital of moer than Rs. 10 lakhs were registered under the Companies Act, 1956 in the State of Madhya Pradesh during the year 1973 (Jan. 1973 to Dec. 1973).

(b) No company with a paid-up capital of more than Rs. 10 lakhs went into liquidation or was struck off under Section 560(5) of the Companies Act, 1956 during the year 1973 (Jan. 1973 to Dec. 1973).

Setting up of a Fertilizer Plant in Madhya Pradesh

813. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether a decision has since been taken in regard to setting up of a fertilizer plant based on Naphtha or some other type of fertilizer plant in public sector in Madhya Pradesh; and

(b) if so, present position in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) Government have approved the establishment of a coal-based fertilizer plant at Korba in Madhya Pradesh for the production of 4,95,000 tonnes of urea per annum at an estimated cost of Rs. 118.25 crores. The work on the project has started.

Disruption in working of F. C. I.

814. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether there was any disruption in the working of the fertilizer Corporation of India during 1972-73 as compared to its working during the last few years and if so, the reasons therefor; and

(b) the extent of fall in the production of different units of the Corporation functioning during 1972-73 as a result of defects in the power supply, power failure, insufficient and irregular supply of raw materials and accidents?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) : The overall production of F. C. I. during 1972-73 was lower than that in 1971-72 and 1969-70 and the production shortfall was due to power and other constraints.

The unit-wise break-up of production shortfalls and the reasons therefor are as under :

NITROGEN

('000 tonnes)

	Power problems	Insufficient and irregular supply of required quality of raw materials	Mechanical breakdowns etc.
Nangal	26.0		
Trombay	8.9		
Namrup	0.2		..
Gorakhpur	10.7	..	1.8
Sindri	..	8.0	2.4
TOTAL	45.8	8.0	4.2

केरल में इदिक्की परियोजना का निर्माण-कार्य

815. **श्री वयालार रवि** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इदिक्की बिजली परियोजना कार्यक्रम के अनुसार चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण के विभिन्न क्षत्रों मे सम्पन्न हुए कार्य का ब्यौरा क्या है और अद्यतन अनुमानों के अनुसार इस परियोजना के विभिन्न चरणों के चालू किय जाने का क्या कार्यक्रम है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बार-बार श्रमिक अशांति के कारण इदिक्की विद्युत् परियोजना के कार्य में देरी हुई है । इदिक्की विद्युत परियोजना की पहली यूनिट अब जून, 1975 तक चालू होना अनुसूचित है तथा दूसरी और तीसरी यूनिट का क्रमश: सितम्बर और दिसम्बर, 1975 में चालू होना प्रत्याशित है । जनवरी, 1974 तक हुई विभिन्न कार्यों की प्रगति का विवरण सलग्न है ।

विवरण

कार्य का नाम	यूनिट	कुल मात्रा	कुल अद्यतन मात्रा
1. इद्दिकी बांध	लाख घन फुट	165.66	154.29
2. चेरूदोनी बांध	लाख घन फुट	600.00	400.30
3. कलामऊ बांध	लाख घन फुट	160.00	106.35
4. विद्युत् सुरंग (पार्श्व और मेहराब)	रनिंग एफ टी	6651.00	4535.00
5. प्रेशर शाफ्ट सं० 1 (लाइनर इरेक्शन)	नोस	201	10
6. विद्युत्घर कंक्रीट	घन मीटर	9400.00	8994.00
7. टेल रेस सुरंग			
(क) फर्श	रनिंग फीट	4000	पूर्ण
(ख) पार्श्व	रनिंग फीट	2×4000	2×64
(ग) मेहराब	रनिंग फीट	700	..
8. टेल रेस चैनल	घन मीटर	91610	74729
9. बाई-पास चैनल :			
(क) मिट्टी	घन मीटर	84000	6477
(ख) चट्टान	घन मीटर	44000	1324

केरल में वामनपुरम सिचाई परियोजना

816. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामनपुरम सिंचाई परियोजना को केरल की पांचवीं योजना में सम्मिलित कर लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने, इस योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केरल की पांचवीं योजना का अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) इस परियोजना में वलायकोमे वामनपुरम नदि पर एक बांध तथा 8000 हैक्टेयर पहली और दूसरी फसलों (धान को) तथा 4000 हैक्टेयर तीसरी फसल (धान को) की सिंचाई के लिए एक बाम तट नहर प्रणाली का निर्माण परिकल्पित है। परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुई थी और इसकी जांच की जा रही है।

अशोधित तेल का आयात तथा उस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

817. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, देश में कुल कितने अशोधित तेल का आयात किया गया तथा उन वर्षों में इसका विदेशी मुद्रा में कुल कितना मूल्य अदा किया गया ;

(ख) यदि हम उतने ही अशोधित तेल का आयात करें जितने का पिछले वर्षों करते रहे हैं तो अशोधित तेल के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के कारण अशोधित तेल के आयात पर हमें कितनी अधिक विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा; और

(ग) विदेशी मुद्रा के व्यय को कम करने में सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से कितनी सहायता मिली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा '000 मीटरी टनों में	मूल्य रुपये करोड़ में
1971 . . .	12,688	139.88
1972 . . .	12,310	144.25
1973* . . .	13,386	240.71

*अस्थाई

(ख) और (ग) अशोधित तेल के आयात के कारण विदेशी मुद्रा की भुगतान में वृद्धि की सूचना देना इस स्तर पर सम्भव नहीं है क्योंकि अशोधित तेल के मूल्यों में अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप उन्हीं कारणों से इतने शीघ्र विदेशी मुद्रा के बाहर जाने में बचत का शुद्ध मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

बम्बई और कोचीन के बीच सीधी रेल सेवा

818. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बम्बई और कोचीन के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ किये जाने का अनुरोध किया है जिससे इस क्षेत्र के बहुत से यात्रियों की असुविधाओं को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई और कोचीन के बीच सीधी रेल सेवा के प्रस्ताव की जांच की गयी है किन्तु, मार्ग के खण्डों पर लाइन क्षमता के अभाव तथा बम्बई वी०टी० पर जरुरी टर्मिनल सुविधाओं के न होने से, इसे शुरू करना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

Crimes on Western Railway during the last year

820. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of crimes registered on Western Railway during the last one year ;

(b) the number of persons arrested in this connection ;

(c) the number of persons prosecuted and punished ; and

(d) the action taken by Government for preventing incidents of crimes and the future plans of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d) A statement is attached. [*Placed in Library. See. No. L. T. 6231/74*]

The following measures are being taken to prevent crime against person and property of passengers and booked consignments :—

(1) Important night passenger trains are being escorted by armed police.

(2) Regular beat duties by Government Railway Police staff are arranged to keep surveillance over criminals and known bad characters.

(3) Plain clothed Police-men are deployed to collect information and to watch the activities of criminals.

(4) A working group consisting of senior Officers of State/Central Government (including Railways) has been formed to thoroughly examine the position and to suggest measures for effectively tackling the problem of crimes on Railways.

This group has so far held one meeting at which it was unanimously agreed that there is an urgent need to augment the strength of Government Railway Police. The State Governments, however, expressed their inability to meet this additional expenditure and desired that the Central Government should bear the cost of expenditure on this augmentation by giving grants-in-aid. Accordingly a memorandum was submitted to the Finance Commission.

(5) All important yards, goods sheds, transhipment/repacking points etc. are being guarded round the clock by R.P.F.

(6) Nominated goods trains, particularly those having wagons carrying high-rated commodities, are being escorted by the R.P.F. in vulnerable sections.

(7) Special drives are conducted against the receivers of stolen property and cases are prosecuted under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966.

(8) Plain clothed RPF staff are deployed to keep watch on the activities of criminals.

(9) Assistance and co-operation of the Railway Trade Unions has been sought for prevention and detection of crimes on Railways.

(10) Necessary co-ordination is maintained with the State Police authorities for keeping surveillance over bad characters operating on railways.

(11) Criminals and receivers of stolen property are detained under the Maintenance of Internal Security Act.

तेल स्थिति के बारे में वक्तव्य

821. श्री सरोज मुखर्जी :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 जनवरी, 1974 को कलकत्ता में पत्रकारों को बतलाया था कि सरकार तापीय बिजली सयन्त्रों में धीरे धीरे तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करना आरम्भ कर देगी ;

(ख) क्या उन्होंने आगे यह भी कहा था कि पेट्रोल के मूल्य में और वृद्धि की सम्भावना है तथा देश में पेट्रोल का राशन किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो तेल सम्बन्धी नीति के बारे में उनके वक्तव्य की अन्य मुख्य-मुख्य बातें क्या थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) जी हां। 12-1-74 को पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने कलकत्ता में पत्रकारों को बताया कि विश्व बाजार में अशोधित तेल तथा परिशोधित उत्पाद के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण मोटर गैसोलिन के राशन करने अथवा तेल उत्पाद के खपत में किसी प्रकार की प्रतिबन्ध लगाये जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे बताया कि तेल पर आधारित तापीय संयंत्रों में तेल के स्थान पर कोयले के प्रयोग के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है। यदि अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि होना जारी रहा तो देश में पेट्रोलियम उत्पादो के मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि की सम्भावनाओं के बारे में उपेक्षा नही की जा सकती।

रूस के तेल मंत्री का भारत के तेल क्षेत्रों का दौरा

822. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के तेल मंत्री श्री वी० डी० शासिन ने हाल ही में हमारे देश के तेल क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन तेल क्षेत्रों का दौरा किया था ; और

(ग) तेल क्षेत्रों में उत्पादन में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) श्री वी० डी० शाशिन, सोवियत तेल उद्योग मंत्री, ने इस देश की हाल ही में की गई यात्रा के दौरान, गलेकी, लकवा, दुलियाजान, अंकलेश्वर और नवागांव, आदि तेल क्षेत्रों/तेल प्रतिष्ठानों का दौरा किया।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारतीय तथा सोवियत दोनों दलों ने निम्नलिखित मामलों को प्रमुख कार्य मान कर विचार किया :—

(i) ज्ञात तेल क्षेत्रों का शीघ्रता से विकास ;

(ii) वर्तमान उत्पादक कूपों का अधिकतम उपयोग ;

(iii) आर्थिक एवं प्रभावशाली सहायक प्रतिप्राप्ति प्रणाली का विस्तारित उपयोग।

अनेक सहायक प्रतिप्राप्ति प्रणालियों के बारे में सोवियत दल में इस मामले में पानी की बाढ़, तथा कूपों की तलहटी को बिजली द्वारा गर्म करने तथा भाप द्वारा कूपों को गर्म करने जैसे विचार व्यक्त किए। ज्ञात तेल क्षेत्रों के शीघ्रता विकास तथा उत्पादक कूपों के अधिकतम उपयोग के बारे में, सोवियत दल ने, विशेषज्ञ देने के रूप में तथा भारतीय अन्वेषण प्रयास और तेल का व्यधन एवं उत्पादन कार्य, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाही की जा रही है, को बढ़ावा देने के लिए सोवियत सहायता अति शीघ्र देने पर सहमति प्रगट की।

Financial Assistance to Bihar for Protection of Mansi Railway Station and National Highway No. 31

823. Shri G.P.Yadav: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given financial assistance amounting to several crores of rupees to the Bihar Government for the protection of Mansi Railway station under Khagaria and the adjoining National Highway No. 31 ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) Protection measures against floods and erosion form part of the State plan for which assistance is provided by the Centre in the form of block loans and grants. However, at an inter-Ministerial meeting held in March, 1970 it was agreed that the cost of immediate repairs to be carried out before the monsoon of 1970, for the spurs constructed for protection against erosion of areas near Mansi, should be shared equally by the Ministry of Railways, Ministry of Transport and the State Government of Bihar. The total estimated cost of these works was Rs. 45 lakhs. In accordance with the debits received from the State Government of Bihar, the Ministry of Railways and the Ministry of Transport have paid an amount of Rs. 13.16 lakhs and Rs. 13.14 lakhs respectively to the State Government.

हिन्दुस्तान ऐल्यूमिनियम कम्पनी, मिर्जापुर द्वारा बिजली घर की स्थापना

824. श्री राम प्रकाश : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश को अपना बिजली घर स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य गैर-सरकारी फर्मों को भी ऐसी सुविधा उपलब्ध है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) साधारणतः समस्त नव विद्युत् उत्पादन सरकारी क्षेत्र में ही किया जाना होता है। बहरहाल उन विशेष मामलों पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है जहां प्राइवेट फर्मों द्वारा अपने प्रयोग के लिए विद्युत् उत्पादन करने की अनुमति मांगी जाती है।

अत्यावश्यक वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में वैगनों की कमी का प्रभाव

825. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों की कमी के कारण अत्यावश्यक वस्तुएं अभावग्रस्त क्षेत्रों में समय पर नहीं पहुंच पातीं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे को और अधिक वैन सप्लाई करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) रेलों द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, उर्वरक, और पेट्रोल से उत्पन्न माल के संचलन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इनका संचलन सन्तोषजनक है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले पर आधारित रसायनों का विकास

826. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल संकट से मुक्ति पाने के लिये पेट्रो-रसायन के विकल्प के रूप में कोयले पर आधारित रसायनों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी मूख्य बातें क्या हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

तलचेर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

827. **श्री गजाधर माझी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचेर (उड़ीसा) स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र को सीमेंट और इस्पात जैसी सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा खर्च वाली किन-किन वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी और सक्त संयंत्र के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) बतलाई गई सामग्रियों के सामान्य अभाव के कारण कुछ सीमा तक तालचर सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर कुप्रभाव पड़ा है । कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है । तालचर संयंत्र के जनवरी 1976 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है ।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड के अन्तर्गत केरल में औषध एकक स्थापित किया जाना

828. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के एक प्रस्तावित औषध एकक को स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया और कब लिया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल को और अधिक मात्रा में पैट्रोल और स्नेहक तेल की सप्लाई

829. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत सरकार से और अधिक मात्रा में पेट्रोल और स्नेहक तेल सप्लाई करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने उक्त अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि नेपाल की पी० ओ० एल० उत्पादों की अतिरिक्त आवश्यकताएं कम हैं इसलिए उनको पूरा करने का प्रस्ताव है ।

निर्यात से होने वाली आय को अशोधित तेल के आयात पर व्यय करना

830. **श्री समर मुखर्जी :**

श्री देवेंद्र सिंह गरचा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान अशोधित तेल के आयात का बिल 1000 करोड़ रुपये का होगा ; और

(ख) पांचवीं योजना में चौथी योजना के अनुपात में भारत को निर्यात से होने वाली आय का कितना भाग अशोधित तेल के आयात पर व्यय होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) अशोधित तेल मूल्यों की अनिश्चितता के कारण चौथी और पांचवीं योजना के बीच के आंकड़ों से तुलना करना या पांचवीं योजना के दौरान अशोधित तेल के कारण आयात बिल का मूल्य बतलाना इस समय सम्भव नहीं है समस्त स्थिति का पुनरिक्षण किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में अन्तिम अनुमानों को अन्तिम रूप से सम्मिलित किया जायगा ।

विदेशी नियंत्रण वाली औषध कम्पनियों की लाभों के बारे में लागत-लेखा समिति की सिफारिशें

831. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नियंत्रण वाली औषध कम्पनियों के लाभ के बारे में लागत-लेखा समिति की सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मोटी रुपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) इस प्रकार की समिति की स्थापना की गई । 24 प्रपुंज औषधों की लागत निर्माण का निरीक्षण करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्ययन की अध्यक्षता के अधीन गठित कार्यकारी दल की ओर इसका सम्भवतः निर्देश है । कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । तथापि इसका उल्लेख किया जा सकता है कि कार्यकारी ग्रुप का विशेष रूपसे विदेश निन्मत्रित औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम पर उसी रूप में रिपोर्ट देने का निरीक्षण करने के लिये नहीं कहा गया था ।

कोचीन स्थित फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड के संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना

832. श्री सी० जनार्दनन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड कोचीन कारखाने में मुख्य संयंत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) यह संयंत्र इस समय अपनी लगभग 60% की क्षमता पर काम कर रहा है । कुछ यान्त्रिक और परिचालन सम्बन्धी रुकावटों पर काबू पाने और उच्च स्तर पर उत्पादन को सुस्थिर करने के लिए कार्रवाई चालू है ।

खाद्यान्नों के राशन की मात्रा बढ़ाने के लिये नागपुर के रेल कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

833. श्री राम सहाय पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के रेलवे कर्मचारियों ने खाद्यानों के राशन की अधिक मात्रा के लिये आन्दोलन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके आन्दोलन का स्वरुप क्या था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 19 दिसम्बर से 28 दिसम्बर, 1973 की अवधि के दौरान , नागपुर में तैनात कर्मचारियों ने विभिन्न अवधियों में कार्य नहीं किया । उन्होंने केवल काम ही बन्द नहीं किया बल्कि मोर्चे और आन्दोलन भी किए और उस समय गाड़ियों के चलने में रुकावट पैदा की जबकि गाड़ियां आंशिक रूप से चल रही थी ।

Preparation of Draft Report on Irrigation and Power Projects in Madhya Pradesh Through Aerial Photographic Survey system

834. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a draft report on irrigation and power projects is proposed to be prepared for the first time in Madhya Pradesh through aerial photographic survey system ; and

(b) If so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise,

Changing Colours of Petrol and Diesel

835. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the colour of Petrol has been changed ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government have decided not to mix any colour in the diesel oil; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no change in the colour of diesel oil.

(d) Does not arise.

धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन

836. **श्री दशरथ देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन बनाए जाने की योजना पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि खर्च किये जानी की संभावना है ; और

(ग) वास्तविक कार्य कब आरम्भ होना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल गाडियों में चालकों के लिए सतकता युक्ति

837. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रंक लाइनों पर कितनी रेल गाड़ियों में चालकों के लिये सतर्कता युक्ति (ड्राइवर्स विजिलेंस डिवाईस) उपलब्ध करा दी गई है ; और

(ख) शेष रेलगाड़ियों में इस प्रकार की युक्ति उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ड्राइवर का सतर्कता नियंत्रण उपकरण गाड़ियों का संचलन करने वाले डीजल रेल इंजनों में लगा हुआ है। बड़ी लाइन के 930 और मीटर लाइन के 366 डीजल रेल इंजनों में से क्रमश: बडी लाइन के 367 और मीटर लाइन के 248 मुख्य लाइन के डीज़ल रेल इंजनों में ये उपकरण लगाये गये थे। अभी किसी बिजली रेल इंजन में ड्राइवर के सतर्कता नियंत्रण उपकरण नहीं लगे हैं।

(ख) सभी नये डीजल रेल इंजनों में ये उपकरण लगाये जा रहे हैं। दक्षिण रेलवे के पोदनूर कारखाने में 100 उपकरणों का निर्माण शुरु किया जायेगा। शुरु में ऐसे 20 उपकरण बनाने का आर्डर दिया गया है और जैसे ही पहले 20 उपकरण सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा करा लेंगे इस में 80 की और वृद्धि कर दी जायेगी। इस कारखाने को और आर्डर उस समय दिये जायेंगे जब यह 100 की पहली किश्त तैयार कर लेगा। डीज़ल और बिजली रेल इंजनों में उपयोग के लिए कुछ संख्या में इस उपकरण का आयात करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान के मरू क्षेत्र में तेल की खोज

838. श्री डी० डी० देसाई :

श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान की मरु क्षेत्र में तेल की खोज को पुन: आरम्भ करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने जैसलमेर जिले के सुमेरवारी वीखूराम नाई नामक क्षेत्र में गहन छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खा) : (क) जी, हां

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अज्ञात तल संसाधनो की खोज

839. श्री० डी० डी० देसाई :

श्री समर गुह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल के अज्ञात संसाधनों की खोज को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खा) : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए भूमि के साथ साथ महाद्वीपीय मग्न तट क्षेत्र में अपने अन्वेषण को गहन करने के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम तैयार किया है। योजना के उद्देश्य नीचे दिये गये हैं :

(i) 70 मिलियन मी० टन तेल के अतिरिक्त वसूली योग्य आरक्षण की स्थापना करना।

(ii) योजना अवधि के दौरान 34.12 मिलियन मी० टन के संचयी उत्पादन के साथ 1978-79 के दौरान 8.42 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन दर को प्राप्त करने के लिए अशोधित तेल की उत्पादन में वृद्धि करना।

(iii) योजना अवधि के दौरान 4902 मिलियन क्यूबिक मीटर के संचयी उत्पादन के साथ 1978-79 के अन्त तक प्रतिवर्ष लगभग 1150 मिलियन घन मीटर के गैस उत्पादन दर की स्थापना करना।

(iv) नये क्षेत्र में अन्वेषण कार्य को गहन करना जिससे इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन शक्ति के मुल्यांकन के लिए सूचना प्राप्त की जा सके।

(v) जहां कहीं आवश्यक हो आधुनिक उपकरणों तथा तकनीक के प्रयोग के बारे में दक्षता एवं की लागत को कम करने को अधिक करना ;

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग ने 1.47 मिलियन मीटरी टन की व्ययन करने की परिकल्पना की है तथा भूवैज्ञानिक कार्य हेतु 105 पार्टी वर्ष तथा भू भौतिकीय कार्य हेतु 150 पार्टी वर्ष लगे।

केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पेट्रोल की खपत

840. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय पेट्रोल की उपयोग में मितव्ययता उपायों के बावजूद प्रतिवर्ष इस ईंधन पर अधिकाधिक धन राशि खर्च कर रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज जा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

Ten Major Cities where Maximum Petrol Consumed

841. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of ten major cities in the country which consumed the maximum petrol last year ; and

(b) the broad features of petrol consumption in respect of each of the above cities for one year ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Ticketless Travelling during the Last Year

842. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of persons, State-wise apprehended for travelling without tickets during the last year and the total amount recovered from them by way of penalty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Statistics of number of persons apprehended for travelling without tickets are not maintained State-wise. However, the number of passengers detected travelling without tickets or with improper tickets and the amount realised from them towards fare and excess charges, during the year 1972-73, Railway-wise are given in the attached Statement.

Statement

Railway	Number of Persons detected travelling without tickets or with improper tickets	Amount realised from such passengers
		Rs.
Central	2,50,400	39,04,420
Eastern	3,28,478	31,55,315
Northern	1,92,328	25,35,831
North Eastern	1,42,603	15,42,431
North East Frontier	72,168	6,44,496
Southern	1,83,702	26,61,615
South Central	1,35,056	19,30,462
South Eastern	1,62,653	16,86,348
Western	2,72,156	31,51,116
TOTAL	17,39,544	2,12,12,034

Licences issued for Setting up of Fertilizer Plants in Private Sector

843. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the number of licences issued in the private sector for setting up fertiliser plants during the last one year alongwith the names of the firms and the date by which they are likely to start production ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : The required information is given below :

S. No.	Name of the firm	Date of issue of licence	Item of manufacture	Expected date of commissioning/ Remarks
1	M/s. Phosphate Co. Ltd. Rishra, Hooghly, West Bengal.	19-2-73	NPK granulated mixed fertilizers.	A carrying on Business licence was issued in accordance with the revised licensing policy requiring units under production to obtain such licences for NPK mixtures.
2	M/s. Adarsh Chemicals & Fertilizers Ltd., Udhna, Distt. Surat, Gujarat.	31-7-73	NPK granulated fertilizers.	End of July, 1974.

Scheme to give New Look to Patna Junction Railway Station

844. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the scheme to give a new look to the Patna Junction Railway Station ; and

(b) if so, the salient features of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The following works are being included in the Budget (1974-75) :

(i) Two washing lines with pits, raised platforms and washing and charging facilities at the site where the Governor's platform is located at present ;

(ii) A new Booking Office and circulating area on the south side of the station ;

(iii) A 16 ft. Foot-overbridge from the south side giving connection to all the existing platforms and also to the north side of the station ; and

(iv) Shifting of the offices in the existing station building to the first floor and extension of 3rd class waiting hall.

आल इण्डिया ट्रेन एक्सामिनर्स के आन्दोलन के कारण रेल गाडियों का रद्द किया जाना

845. **श्री एम० सुदर्शनम् :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेन एक्सामिनर्स के हाल के आन्दोलन के कारण कुछ रेल गाड़ियां रद्द की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 30-1-73 से 10-2-74 तक की अवधि में प्रतिदिन औसतन लगभग 11 जोड़ी गाड़िया रद्द की गई ; गाड़ियों के रद्द किये जाने की अवधियां 1 दिन से लेकर 12 दिन तक की थीं ।

राज्यों में हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण

846. **श्री एम० सुदर्शनम् :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजनाएं नहीं भेजी और विशेषकर जबकि बस्तियों के साथ लगने वाले गांवों में बिजली आ चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन राज्यों की हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पहले से विद्युतीकृत ग्रामों की सहवर्ती हरिजन बस्तियों को बिजली ते देने के संबंध में असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और मेघालय राज्यों से कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं हुए हैं । यह सूचित किया गया है कि इन राज्यों में कोई अलग हरिजन बस्तियां नहीं है ।

बिहार में 'सुपर' तापिय बिजली घर की स्थापना

847. श्री गजाधर मांझी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में 'सुपर' तापीय बिजली घर की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बाते क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों में बृहत् ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों के चयन के लिए एक समिति गठित की है । यह समिति बिहार सहित राज्यों में विभिन्न स्थलों का दौरा कर चुकी है तथा आशा है कि यह अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी ।

तटवर्ती नौवहन के लिए रियायती दरों पर इंधन तेल की सप्लाई

848. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तटवर्ती नौवहन के लिये रियायती दरों पर ईंधन तेल की सप्लाई करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य भागों में वास्तविक वर्तमान मूल्य और रियायती मूल्य के बीच क्या अनुपात है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख)

13-12-1973 से और तदनुसार 16-12-1973 से भारतीय पत्तनों पर बंकर ईंधन का मूल्य अत्यधिक बढ़ाना पड़ा था । तथापि निम्नलिखित श्रेणी के पोतों (जिसमें तट पोत सम्मिलित थे) को 2-1-1973 से इन वृद्धियों से छूट दी थी :—

(1) भारतीय नौसेना और पत्तन न्यासो से सम्बन्धित पोत ।

(2) मत्सय ग्रहण शिल्प ।

(3) (i) एकल या निरन्तर मात्रा चार्टर के आधार पर पोतों को छोड़ कर महानिदेशक (नौवहन) ने समस्त पोतों को तटीय माल और/या यात्रियों को ले जाने के लिए और तटीय यात्रा करने की अनुमति दे दी है ।

(ii) तट पोतों और अन्तंराष्ट्रीय पोतों से भारतीय तेल निगम लि० द्वारा बंकर ईंधन के लिए 2-1-74 से प्रभारित मूल्य निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े रुपयों/लिटरों में)

	23-1-74 से संग्रह स्थल पर मूल अधिकतम बिक्री मूल्य	तट पोत भट्टी का तेल	अन्तर्राष्ट्रीय पोत भट्टी का तेल
बम्बई . . .	511.60	299.17	1031.77
गोआ . . .	510.00	305.57	1070.21
कोचीन . . .	510.90	301.90	1048.18
मद्रास . . .	526.32	317.13	1139.57
विजाग . . .	517.93	319.48	1153.63
कलकत्ता . . .	525.35	326.19	1193.93

कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन का पूरा होना

849. **श्री विक्रम महाजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन को पुरा किये जाने का मूल लक्ष्य क्या है ; और

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उसके कब तक पूरे होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 30 जून, 1973 तक।

(ख) इस परियोजना पर अभी तक 41 प्रतिशत प्रगति हुई है। इस समय कार्य पूरे जोर से चल रहा है और यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये जा रहे है कि परियोजना 30 जून, 1975 तक चालू कर दी जाय।

Late arrival of Chetak Express at Delhi-Sarai Rohilla Station

850. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Chetak Express generally arrives behind schedule at Delhi-Sarai Rohilla station ever since its arrival time was changed ;

(b) if so, the actual arrival time of this train at Sarai Rohilla Station during the last four months; and

(c) the reasons for late arrival of the train ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) A statement on the punctuality performance of 216 Dn. Chetak Express during the period October '73 to January '74 is attached. The deterioration in running of this train from November onwards, when the Time Table was changed has been due largely to the general unsettled conditions brought about by various staff agitations on the Railways which had affected the train services all over the country and increased incidence of alarm chain pulling.

STATEMENT

Statement showing punctuality performance of 216 Dn. Chetak Express during October '73 to January 74.

Month	Right time	Upto 15" late	16 to 30" late	31 to 60" late	Over 60" late
October '73	24	..	..	2	5
November '73	9	2	8	5	6
December' 73 . . .	5	4	1	10	5
				(cancelled on 6 days)	
January '74 . . .	8	5	5	6	7

तटवर्ती जहाजी बेड़े के लिए "बैंकर आयल" के मूल्य

851. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **पेट्रोलियम ओर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 12 दिसम्बर, 1973, 13 दिसम्बर, 1973 तथा 11 जनवरी, 1974 के बाद तटवर्ती नौवहन के लिए बंकर आयल का मूल्य क्या था ?

पैट्रोलियम और रसानय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सभापटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है । [**ग्रंथालय मे रखा गया / देखिए संख्या एल० टी०** 6232/74]

एकाधिकार ग्रहों के प्रबन्धक बोर्डों में सरकारी निदेशकों को मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव

852. **श्री बी० डी० नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े एकाधिकार गृहों के प्रबंधक बोर्डों में सरकारी निदेशकों को मनोनीत किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रेल तथा तटवर्ती जहाजों द्वारा कोयला, नमक तथा सीमेंट की ढुलाई के लिये समन्वय निकाय

853. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण सडक परिवहन के बहुत महंगे हो जाने के कारण रेल तथा तटवर्ती जहाजों द्वारा कोयला, नमक तथा सीमेंट की ढुलाई को समन्वित करने के लिए समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समन्वय निकाय के गठन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) उपरोक्त माल के रेल तथा जल परिवहन के लिए कितनी-कितनी मात्रा निश्चित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सरकार (नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय) द्वारा तटीय नौवहन के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेल-सड़क-सागर-समन्वय के सामान्य प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन-दल की स्थापना की गयी है ।

अध्ययन दल का गठन निम्नप्रकार है :—

(i) महानिदेशक, नौवहन, बम्बई . . .	अध्यक्ष
(ii) निदेशक, यातायात (वाणिज्य) रेलवे बोर्ड . .	सदस्य
(iii) निदेशक, यातायात (परिवहन) रेलवे बोर्ड . .	सदस्य
(iv) उप सचिव (वाणिज्यिक-नौवहन) और परिवहन मंत्रालय .	सदस्य
(v) उप सचिव (पत्तन विकास), नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय .	सदस्य
(vi) अवर सचिव, सड़क परिवहन, नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय .	सदस्य
(vii) मुख्य अभियन्ता एवं प्रशासक, अन्तर्देशीय जल-परिवहन, नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय ।	सदस्य
(viii) वरिष्ठ उप महानिदेशक, नौवहन	संयोजक

अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है । कोयला, नमक और सीमेंट के रेल और समुद्री परिवहन के लिए कोई विशिष्ठ मात्रायें निर्धारित नहीं की गयी हैं ।

रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा में कमी

854. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने गत तीन वर्षों में (वर्ष वार) कितना कितना माल ढ़ोया ;

(ख) क्या इस समय ढोये जा रहे माल की मात्रा गत वर्ष तथा उससे पहले वर्ष की तुलना में बहुत कम है ; और

(ग) रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल की मात्रा में कमी आने के क्या कारण हैं ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा ढोया गया माल यातायात इस प्रकार है :

(हजार मीटरिक टनों में)

1970-71	196,456
1971-72	197,825
1972-73	201,300

(ख) जी, हां ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान रेलों दवारा ढोये जाने वाले माल यातायात में अनेक कारणों से जो अधिकतर रेलवे के नियंत्रण से बाहर थे, कमी हुई हैं । गर्मी के महीनों में बिजली में प्रायः कटौती हुई और भारतीय रेलों के व्यस्त विदयुतीकृत मार्गों पर बिजली बंद हो गयी जिससें रेल संचलनों पर गम्भीर रुप से प्रतिकुल प्रभाव पड़ा । देश में बिजली की आम कमी के कारण औदयोगिक उत्पादन भी प्रभावित हुआ । इसके बाद मानसून के दौरान बहुत से स्थानों पर लाइन टूट-फूट गयी और बाढ़े आई । रेल कर्मचारियों द्वारा अचानक हड़तालों और आन्दोलनों, लोको कर्मचारियों की हड़ताल, जन-आन्दोलनों और खाद्य पदार्थों के लिए दंगों, बंदों, नागरिक उपद्रवों, विभिन्न औदयोगिक स्थापनाओं में श्रमिक हडतालों और पर्यन्तों पर माल डिब्बों के अधिक समय तक रुके रहने आदि के फलस्वरूप रेलों पर यातायात संचलन बार-बार गम्भीर रुप से अस्त व्यस्त होता रहा ।

धांस बागमती नदी पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजना तथा मोहिनी नदी पर तटबंध बना के कार्य को अन्तिम रूप देना

855. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना की क्रियान्विति के लिए धांस बागमति नदी के सर्वेक्षण के बारे में 11 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4269 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धांस बागमती नदी पर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजना तथा मोहिनी नदी पर तटबंध बनाने के कार्य को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार ने इस स्कीम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्राक्कलनों को अन्तिम रूप देने के लिए अपेक्षित कुछ स्पष्टीकरण क्षेत्रीय संगठन से प्रतीक्षित है ।

बिहार में खिरोई नदी पर स्लूल फाटक एवं पूल बनाना

856. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री बिहार में खिरोई नदी पर स्लूल फाटक एवं पुल बनाने के बारे में 11 दिसम्बर, 1973 को अतारंकित प्रश्न संख्या 4270 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खिरोई नदी में किए गए जल विज्ञान संबंधी अध्ययन के सही सही निष्कर्ष क्या है ;

(ख) क्या हरिहरपुर और काली गांव के बीच तथा मुरठा में खिरोई नदी पर स्लूल फाटक एवं पुल बनाने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बिहार की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1970 से एकत्र किए गए जल-वैज्ञानिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि सिंचाई के लिए व्यपवर्तन स्कीम की सफलता हेतु हथिया

अवधि के दौरान (अक्तूबर के पहले 15 दिनों में) नदी में जल-निस्सरण पर्याप्त नहीं है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखे जाएं। ऐसे प्रक्षणों के परिणामों के उपयुक्त पाए जाने के पश्चात् ही यह स्कीम तैयार की जा सकती है।

Assistance to Madhya Pradesh for Irrigation Projects

857. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the financial assistance provided to Madhya Pradesh during the last three years or proposed to be provided in future by the Central Government for raising the percentage of land under irrigation and construction of irrigation projects there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Parasad) : Irrigation is a State subject and funds for major and medium irrigation projects are provided in the State Plans.

Central assistance is provided in the form of block loans and grants for the State Plans as a whole and is not related to any individual head of development or project. The total outlay of the Annual Plans of Madhya Pradesh from 1971-72 to 1973-74 was Rs. 345·8 crores, out of this central assistance was Rs. 160·67 crores.

मेरठ में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग

858. **श्री एस०एन० मिश्र :**

श्री बीरेंद्र सिंह राव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लोगों ने मांग की है कि निर्धन वाद-कारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उच्च न्यायालय की एक बैंच मेरठ में स्थापित की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) कतिपय संगठनों से सरकार को इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस प्रश्न पर कि क्या उच्च न्यायालय की बैंच प्रधान स्थान से भिन्न अन्य स्थान पर भी होनी चाहिए, प्रथमतः संबंधित राज्य सरकार के उच्च न्यायालय के परामर्श से विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय की एक बैंच मेरठ में स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मामले तथा न्यायाधीश के रिक्त स्थान

859. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 तथा 1973-74 में उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामले अनिर्णित थे ;

(ख) इस समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने स्थान रिक्त हैं और 1971-72 और 1972-73 में रिक्त स्थानों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) अनिर्णित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विवरण संलग्न है। [**गंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6233/74**]

(ख) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6233/74**] रिक्त स्थानों की संख्या सेवा-निवृत्त, आदि के कारण समय-समय पर भिन्न होती है। विवरण में दिए गए आंकड़े, वे रिक्त स्थान दर्शाते है, जो 1 जनवरी, 1971, 1972, 1973 को थे तथा जो इस समय हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।[**गंथालय मे रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6233/74**]

राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे के नियतन में कटौती

860. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के मिट्टी के तेल के कोटे के नियतन में कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) तथा (ख) जी, हां। मिट्टी तेल की अनुमानित खपत में जनवरी, 1974 में 15 प्रतिशत तथा फरवरी 1974 में 20 प्रतिशत कटौती की गई है। तदनुसार राज्यवार आबंटनों में भी कमी की गई है। उपर्युक्त कटौतियां इन बातों को ध्यान में रखते हुए की गई है--मिट्टी तेल तथा हाई स्पीड डीजल के मूल्यों को लगभग बराबर करने के बाद मिट्टी तेल में संभावित कमी तथा कुछ राज्यों में बिजली की कटौतियों के परिणामस्वरुप हाई स्पीड डीजल तथा एल०डी० ओ० की बढ़ी हुई मांगों तथा अन्य तथ्य/इन कटौतियों से बिजली, परिवहन उद्योग तथा कृषि के लिए अधिक आवश्यक आर्थिक निवेशों की उपलब्धि सुनिश्चित होगी।

त्रिवेंद्रम तथा कन्याकुमारी के बीच रेल संपर्क और एर्नाकुलम-त्रिवेंद्रम रेल लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना

861. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम तथा कन्याकुमारी के मध्य नये रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य इस समय किस भाग में है;

(ख) एर्नाकुलम तथा त्रिवेन्द्रम के बीच मीटर गेज लाईन को ब्राड गेज लाईन में बदलने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उपरोक्त कार्य अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहे है; और

(घ) इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) परियोजना के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। सभी पहुंच-मार्गों, पुलों और कर्मचारी क्वार्टरों के लिए मिट्टी का काम भी प्रगति पर है। जनवरी 1074 तक कुल मिलाकर 16 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) सभी पहुंच-मार्गों पर मिट्टी का काम गर्डर-पुलों को बड़ी लाइन के स्तर के अनुसार मजबूत करना, बड़े पुलों के लिए कुए गलाना और पायों का निर्माण, छोटे पुलों का विस्तार और उन्हें फिर से बनाना और ऊपरी सड़क पुलों ऊपरी पैदल पुलों को बड़ी लाइन के निकासी मार्गों के अनुरुप ऊंचा करने के काम प्रगति पर हैं। जनवर 1974 तक कुल मिलाकर 23 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ग) और (घ) जी हां, साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, ये कार्य अपने निर्धारित कार्यक्रम से कुछ पिछड़ गये है।

केरल में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

862. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोयले की कमी के कारण केरल में चल रही अनेक रेलगाडियों को रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या केरल राज्य में बिजली की प्रचुरता को देखते हुए समूची रेल प्रणाली के विद्यूतीकरण के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कुछ कम प्रयोग में आने-वाली सवारी गाड़ियां रद्द कर दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) किसी खण्ड के विद्यूतीकरण का निर्णय लेते समय जिन बहुत सी आवयकताओं को ध्यान में रखना होता है उनमें से विद्युतकर्षण के लिए सस्ती दर पर बिजली की उपलब्धता केवल एक है। यातायात की कमी और उस पर भारी पूंजी निवेश के कारण केरल राज्य में रेल प्रणाली के विद्युतीकरण का आर्थिक दृष्टि से औचित्य नहीं है कि उसे ट्रंक मार्गों पर वरीयता प्रदान की जाये।

कर्नाटक राज्य में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

863. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय की मोटी रुप रेखा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बहुतसी लाइनों का सर्वेक्षण हो गया है और कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो एसी लाइनों के सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यदि लाइन क्षमता में किसी अन्य कम खर्चीले ढंग से वृद्धि नहीं की जा सकती तो विशिष्ट खंडो को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

(ख) और (ग) कुछ प्रस्तावों के अनुसार सर्वेक्षण किये गये थे और उनकी स्थिति इस प्रकार है :

(i) बेंगलूर—मैसूर खंड का बड़ी लाइन में बदलाव—इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों की रिपोर्ट मिल गयी है और उनकी जांच की जा रही है। जांच के परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही अन्तिम विनिश्चय किया जा सकेगा।

(ii) सेलम—बेंगलूरु खंड का बड़ी लाइन में बदलाव—(अंशत: कर्नाटक राज्य में) रेल से यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गयी है और उसकी जांच की जा रही है जांच के परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिये की गई कार्यवाही

864. श्री एम० एस० पुरती :

श्री हुकुमचन्द कछवाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे को काफी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां तो कितना घाटा है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंशिक रुप से अथवा पूरे घाटे को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में स्थिति रेलवे बजट में बतायी जायेगी जो संसद् में 27-2-1974 को प्रस्तुत किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की लाइसन्स के बारे मे एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की शिफारिशों पर निर्णय

866. श्री मधु दन्डवते : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन से इतर मैल काटने वाली वस्तुओं के लिये अपेक्षित सोडियम ट्रिपोली फास्फेट के उत्पादन के लिये हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को दिये जाने वाले लाइसेंस के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सिफारिशों पर निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय हमारे देश में विदेशी एकाधिकार को बढ़ावा न दिये जाने की नीति के अनुरुप है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

कम मूल्य के बीजक बनाने और चोर बाजारी जैसी व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच करने का प्रस्ताव

867. श्री मधु दण्डवते : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम मूल्य के बीजक बनाने और चोर बाजारी जैसे व्यापार प्रक्रिया के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का जांच करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के क्षेत्राधिकार में सरकार ने वृद्धि कर दी है; और

(ग) यदि नहीं तो इन कदाचारों के बारे में जांच करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की वर्तमान योजना के अन्तर्गत कम मूल के बीजक बनाने और चोरबाजारी जैसे अपराधों की जांच करने के लिए आयोग समर्थकारी सिद्ध नहीं होगा अतः इस प्रकार की प्रथाएं, एकाधिकार या निर्बन्धानकारी व्यापार प्रथाओं की सीमा के अन्दर नहीं आयेगी । कम मूल्य के बीजक बनाने और चोर बाजारी जैसे अपराधों को कानून के अन्य उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता है और इस प्रकार ये एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की अधिकार सीमा में नहीं आएंगे ।

तेनुघाट में सुपर तापीय बिजलीघर की स्थापना

868. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बोकारो के निकट तेनुघाट में लगभग 200 मेगावाट की निर्धारित क्षमता वाले एक सुपर तापीय बिजली घर को स्थापना करने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्थापित करने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) **और (ख)** तेनुघाट में 193 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1300 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के एक ताप विद्युत् केन्द्र को स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई थी । योजना आयोग प्रथम चरण में तेनुघाट ताप विद्युत् केन्द्र में 2 × 200 मेगावाट के सेटों के प्रतिष्ठापन के लिए सैद्धान्तिक रुप से सहमत हो गया है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि परियोजना को कोयला स्रोत से सम्बन्ध करके कोयला परिवहन इत्यादि का प्रबंध करने तथा परियोजना से विद्युत् पारेषण के लिए अपेक्षित पारेषण लाइनों को सम्मिलित करने के उपरान्त एक संशोधित पिरियोजन रिपोर्ट तैयार की जाए ।

वर्ष 1973 में भारतीय उर्वरक निगम के लाभ के राशि में गिरावट

869. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में भारतीय उर्वरक निगम के शुद्ध लाभ की राशि में वर्ष 1972 की तुलना में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निगम ने वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 में कितना कितना शुद्ध लाभ कमाया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1970–71 से 1972–73 के दौरान निगम द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ निम्न रुप में है : —

(रुपये लाखो में)

1970–71	1971–72	1972–73
166.59	192.23	541.82

सरकारी कारों मे पेट्रोल की खपत

870. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1973 में सरकारी कारों ने अधिक पेट्रोल की खपत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी गाडियों में पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और रसानय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) माननीय सदस्य सम्भवत: केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कारों के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं। यह सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

सऊदी-फ्रांस तेल समझौते का भारत को की जाने वाली अशोधित तेल की सप्लाई पर प्रभाव

871. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सऊदी—फ्रांस तेल समझौते के समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका साऊदी अरब से आयात किए जाने वाले अशोधित तेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) सरकार ने इस कार्य के लिए प्रेस रिपोर्ट देख ली है ।

(ख) साऊदी अरब से अशोधित तेल के आयात पर इस करार से कोई प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है ।

ड्राइवरों द्वारा 10 घण्टे के कार्य के बाद छोड़ दी गई रेल गाड़ियां

872. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद, ड्राईवरों द्वारा अपने 10 घण्टे के कार्य के बाद अनेक रेल गाड़ियां छोड़ दी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी रेल गाड़ियां छोड़ ही गई और इसके फलस्वरुप रेलवे की कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी 1974 से 12 फरवरी, 1974 तक की अवधि में केवल दक्षिण-पूर्व रेलवे पर चालकों द्वारा 10 घण्टे की ड्यूटी देने के पश्चात 140 माल गाड़ियो और 6 कोचिंग गाड़ियों को छोड़ दिया गया था। इसके कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे को 5,86,534.00 रु० की हानि उठानि पड़ी ।

थीन बांध परियोजना का निर्माण न होने के कारण पंजाब को हुई हानि

873. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री देवेंद्र सिंह गरचा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध परियोजना का निर्माण न होने के कारण पंजाब को भारी हानि उठाने का समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस परियोजना को शीध्र पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिधधेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं। यद्यपि मानसून के दौरान रावी के फालतू बाढ़ जल के समुपयोजन से देश को निःस्संदेह लाभ होगा, तथापि इस कारण कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं के संबंध में सम्बद्ध राज्यों के बीच सहमति होने के बाद ही परियोजना को स्वीकृति दी जाएगी ।

दुर्गापुर परियोजना में आग

874. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पचिम बंगाल के लोगों को, पश्चिम बंगाल सरकार की बृहद् दुर्गापुर परियोजना में आग लग जाने के कारण गस और विद्युत् सप्लाई नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मरम्मत के लिए तथा पश्चिम बंगाल के लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विदयुत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिदधेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 12 जनवरी, 1974 को दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के विद्युत् केन्द्र में आग लगने के कारण विद्युत् जनन में बाधाएं आई परन्तु गॆस के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मरम्मंत कार्य/क्षतिग्रस्त उपस्कर खासकर केबलों को बदलने का कार्य तत्काल हाथ में ले लिया गया था और अनुरक्षण अधीन विद्युत् जनन यूनिटों को पुनः प्रचालन योग्य बनाया जा रहा है। आग लगने से पहले के लगभग 150 मेगावाट विद्युत् जनन के प्रति 100 मेगा-वाट तक विद्युत जनन पहले ही बहाल कर दिया गया है और इसके अप्रैल तक दुर्घटना से पहले की स्थिति में आ जाने की प्रत्याशा है ।

आरामबाग, हुगली के लोगों से लोअर दामोदर योजना के पुनर्विचार के बारे में अभ्यावेदन

875. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोअर दामोदर योजना के पुनर्विचार के लिये गत वर्ष आराम बाग, हुगली के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) ये सुझाव दिये गये थे कि जैसा कि स्कीम म प्रस्तावित है, दामोदर के समस्त निस्सार को मुण्डेश्वरी के जरिये ले जाने के स्थान पर उसके एक भाग को अमता चैनल के जरिये ले जाना चाहिये और पहले प्रस्तावित आठ जलाशयों में से शेष चार का भी निर्माण किया जाना चाहिये ।

लोअर दामोदर बेसिन में बाढ़ों और जल निस्सार की समस्या की जांच करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने 1971 में तकनीकी विशेषज्ञो की एक समिति का गठन किया था। सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करने के उपरांत इस समिति ने दामोदर के समस्त निस्सारण को समायोजित करने के लिए मुण्डेश्वरी पर तटबंधों के निर्माण तथा मुण्डेश्वरी के दक्षिण तट पर क्षेत्र के निस्सार के लिए अमता चैनल के उपयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित लोअर दामोदर स्कीम को सिफारिश की थी। समिति ने यह भी बताया था कि लोअर दामोदर स्कीम के कार्य-निष्पादन को देखने के उपरांत तथा उस समय की अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में अतिरिक्त बाढ़-संचयन बांधों की आवश्यकता का पुरीरीक्षण किया जाए। अमता चैनल के द्वारा निस्सार के एक भाग को व्यपवर्तन करने के सुझाव को राज्य सरकार ने और जांच की थी तथा इस निश्चय पर पहूंची थी कि अत्यधिक लागत के अतिरिक्त, इस स्कीम के सफल प्रचालन में कठिनाइयां भी है।

राज्यों में मिटटी के तेल की कमी

876. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री सेझियान :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 में मिट्टी के तेल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बढ़ौतरी के पश्चात उसका खुदरा मूल्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा विनिर्धारित मूल्य पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या सभी राज्यों में तेल की कमी अभी भी बनी हुई है; और

(घ) यदि हां, हो इस सम्बन्ध में यदि कोई उपाय किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसाय न मंत्रालय मं राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) मिट्टी के तेल का फुटकर मूल्य प्रत्येक राज्य में स्थानीय करों की प्रमात्रा के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। तथापि दिल्ली में यह 85 पैसे प्रति लिटर है ।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत राज्य सरकारों को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है जो अधिक मूल्य लेने के दोषी पाए जाते हैं।

(ग) तथा (घ) कुछ विगत महिनों में पेट्रोलियम पदार्थ के विश्व बाजार में अत्यधिक भाव बढ़ जाने तथा इस उत्पाद की आय कमी हो जाने के कारण देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर कुप्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरुप विद्युत् शक्ति, यातायात. औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शोधनशालाओं द्वारा मिट्टी के तेल का उत्पादन तुलनात्मक रुप में डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, घटाना पड़ा। इसलिए राज्य सरकारों को मिट्टी के तेल की सप्लाई के आबंटन में जनवरी, 1974 में 15% तथा फरवरी, 1974 में 20% की समान कटौती की गई।

सारे राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपलब्ध मात्रा का उचित वितरण करने की व्यवस्था करें तथा उस उत्पाद की जमाखोरी एवं चोर बाजारी करने के खिलाफ कदम उठायें।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का उस प्रणाली के बारेमें विरोध जिसनें कि उस मामले भेजे जाते हैं

877. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने केन्द्रीय सरकार के उस ढंग का विरोध किया है जिस ढग से उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिये पर्याप्त महत्व रखने वाले बहुत से बड़े-बड़े मामलो की जांच करने की आयोग की अनुमति नहीं दी ;

(ख) क्या आयोग ने आरोप लगाया है कि कभी-कभी छोटे-छोटे मुद्दो के मामले आयोग को भेजे जाते हैं जबकि बहुत ऐसे मामले जिनमें प्रथम दृश्या ही महत्वपूर्ण बातें अन्तर्गस्त होती है आयोग को नहीं भेजे जाते है; और

(ग) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमन् जी।

(ख) दिनांक 14-12-73 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई 31-12-72 की वर्ष समाप्ति की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में, आयोग ने एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के कार्यकलापों पर कुछ सामान्य अवलोकन किये है।

(ग) इन अवलोकनों पर सरकार के विचार, सदन के पटल पर दिनांक 14-12-73 को प्रस्तुत की गई, एकाधिकार एव निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनयिम, 1969 के कार्य एवं प्रशासन पर 31-12-72 की वर्ष समाप्ति की द्वितीय रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा 4 में उल्लिखित है।

पांचवीं योजना में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही

878. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पांचवी योजना के दौरान उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कारगर और विशिष्ट उपाय किये गये हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : उर्वरक उत्पादन बढाने के लिए की गई या की जाने वाली कार्रवाईयां मोटी तौर पर से प्रधानता दो श्रेणिया में आते हैं। (i) विद्यमान यूनिटो का आशा प्रद उत्पादन और मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की रचना ।

1. **आशाप्रद उत्पादन :** इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण उपाय निम्नप्रकार है :—

(i) सिंदरी फैक्टरी की युक्तिसंगत योजना के कार्यन्बयन और पुराने अनुभागो की मरम्मत और नवीनीकरण,

(ii) ट्राम्बे यूनिट के कुछ अनुभागों में अल्प परिवर्तन,

(iii) संश्लेषण गैस का उत्पादन करने के लिये अनुपूरक नेफ्था गैसीकरण सुविधाओं की स्थापना और राउरकेला उर्वरक सयंत्र को अधिक कोक ओवन गैस सम्लाई के लिए कार्रवाई की पहल करना,

(iv) नयबेली के अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के विविध अनुभागों में अल्प परिवर्तन करना,

(v) अलवाय यूनिट के कुछ अनुभागों की मरम्मत और नवीनिकरण ।

2. **अतिरिक्त क्षमता की रचना :** पांचवी योजना की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में पांच बृहत आकर के उर्वरक संयंत्रो की सिद्धांत के रुप में स्थापना करना सरकार ने मान लिया है। इन्हें मथुरा, पानीपत भटिण्डा, पारादीप और ट्राम्बे में लगाने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र में दोनों काकीनद के उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने और कोटा उर्वरक संयंत्र का और विस्तार करने के लिये एक आशय पत्र जारी कर दिया है । अतिरिक्त उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना करने के प्रस्ताव भी आ चुके हैं।

विदेशी औषधी फर्मों का भारत में बनी दवाइयों को अपने ब्रेंडों के नाम से बेचना

879. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम रसायन और** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन विदेशी फर्मों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जो कोई भी दवाई स्वयं नहीं बनाती और भारतीय फर्मों द्वारा, जिसमें सरकारी क्षेत्र की फर्में भी शामिल हैं, बनाई जाने वाली दवाइयों पर अपनी दवाइयों के बैंड़ों का नाम लगा कर बेच देती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष वार इन विदेशी नियंत्रित औषध फर्मों की प्रदत्त पूंजी उत्पादन और लाभ क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसी फर्मों की गति विधियों को रोकने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाजखां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

भट्टी के तल की कमी तथा इसक आयात के लिये किये गये प्रयत्न

880. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने तेल का उत्पादन करने वाले लगभग सभी पश्चिम एशियाई देशों का मिट्टी तेल के आयात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन मिट्टी तेल का आयात किया जाता है जब कि 47 लाख टन मिट्टी तेल की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या पर काबू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम तथा मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडलों ने भट्टी के तेल के आयात की संभावनाएं बनाने के लिये पश्चिमी एशिया के कुछ देशों तथा अन्य सप्लाई करने वाले अन्य देशों का अलग अलग तथा संयुक्त रूप से दौरा किया है। इस के परिणामस्वरुप कुछ तैयार माल निश्चित किया गया है जिस से भट्टी के तैल की सप्लाई में कम से कम कटौती किये जाने से इस की सप्लाई को बनाये रखा गया है।

(ग) और (घ) प्रत्येक पैट्रोलियम और उत्पादों की खपत तथा आयात के आंकड़ों को बताना जनहित में नहीं है। तथापि, इस समय भट्टी के तेल का 90% सप्लाई को पूरा किया जा रहा है, और जबकि स्थिति में सुधार करने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, इस उत्पाद की आम उपलब्धता में सुधार होने की आशा है।

नेपाल स्थित करनाली पन बिजली परियोजना से बिजली की खरीद

881. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार नेपाल को करनाली पन–बिजली परियोजना से बड़ी मात्रा में बिजली खरीदने का है ;

(ख) क्या इस संबंध में फरवरी, 1974 में कोई नेपाली प्रतिनिधि मंडल भारत आया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने इस परियोजना की स्थापना में सहायता देने का निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) करनाली जल विद्युत परियोजना के और अनुसंधान करने में भारतीय विशेषज्ञ भी सहयोजित किए जाएंगे। नेपाल भी करनाली क्रियान्वयन बोर्ड में एक सदस्य को मनोनीत करने हेतु भारत से अनुरोध कर रहा है। यदि नेपाल की महामहिम सरकार ऐसा चाहे तो इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करने के लिए भारत ने अपनी इच्छा व्यक्त की है।

भारत में तेल की खोज के लिये अमरीकी सहायता

882. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने हमारे देश में तेल की खोज के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या अमरीकी सहायता से बम्बई में नये स्थान पर अनेक असफलताओं के बाद, 3 फरवरी 1974 से छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ङ) क्या भारत ने तेल की खोज तथा छिद्रण कार्य के लिये अमरीका से और सहायता मांगी है ; और

(च) यदि हां तो इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। इस व्यधन से अमरीका सरकार का हाथ नहीं है। परन्तु वाणिज्यिक आधार पर जब भी आवश्यक होता है कुछ अमरीकी ठेकेदारों की सेवाएँ ले जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका द्वारा भारत को जलविद्युत की सप्लाई

883. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने फालतू जल विद्युत भारत को सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या भारत और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों की हाल ही में हुई बातचीत में इस विषय पर भी चर्चा हुई; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध मे किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

सिंचाई और विदयुत मंत्राल में उप मंत्री (श्री सिदधेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) श्रीलंका ने अभी तक भारत को फालतू जल विद्युत निर्यात करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

Experiments on giving Legal Aid to the Poor

884. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the salient features of the experiments made to make justice available free and at cheap cost to the poor in various States indicating the names of States;

(b) the number of persons benefited therefrom, State-wise; and

(c) the reaction of Government thereto and the steps being taken to make justice available in the same manner in the Supreme Court ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Conversion to Broad Gauge, Doubling, Restoration and Laying of new Railway Lines

885. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of (i) the metre gauge/narrow gauge Railway lines being converted into broad-gauge lines (ii) the lines that are being doubled (iii) the closed lines being restored and (iv) the new lines being laid ; and

(b) time by which each of these works will be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway, (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) . A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T.6234/74].

Foreign Companies Charged With the Monopoies and Restrictive Trade Practices

886. Shri Jagannathrao Joshi
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of foreign companies charged with Monopolies and Restrictive Trade Practices during the last three years and the action taken against them;

(b) whetner investigation have been completed in respect of all the foreign company in this regard; and

(c) if so, the outcome thereof and it not the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Law Justice Company Affairs: (Shri Bedabarata Barua) : (a) A list of foreign controlled undertakings or companies in which there is a high percentage of foreign equtity participation, in respect of which there are charges tnat they are indulging in restrictive trade practices, which are being enequired into, is placed on the Table of the House.

(b) & (c) In the case of Cadbury Fry Ltd. inspectors under section 44 of the M.R.T. P. Act were appointed who have submitted their report in January, 1974. The reports of investgation in respect of all the other undertakings are still awaited.

STATEMENT

List of Foreign Companies Charged with Monopolistic & Restrictive Trade Practices

1. The Cadbury Fry India Private Limited.
2. The Union Carbide of India Limited.
3. The Dunlop India Limited.
4. The Good Year India Limited.
5. The Firestone Tyre & Rubber Co. (India) Private Limited.
6. The Ceat Tyre of India Limited.
7. The India Tyre & Rubber Co. (India) Private Limited.
8. The Coca-Cola Export Corporation Limited.
9. The Gramophone Company of India Limited.
10. The Hindustan Pilkintton Glass Works Ltd.
11. Window Glass Limited.
12. Polydor of India Limited.
13. Ashok Leyland Limited.
14. Indian Oxygen Limited.
15. Ion Exchange India Limited.

गुजरात में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

887. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कौन-कौन सी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) इन परीयोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिदधेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने निम्नलिखित नई सिंचाई स्कीमों का प्रस्ताव किया है :--

बृहत्	1. सिपु
	2. करजन
मध्यम	1. वातरक
	2. कालिन्द्री
	3. धतारवाडी
	4. गोडेथाड़
	5. कासवती

6. अम्बाजल

7. चप्परवाडी (लुनिवाव स्थल)

8. रामी

9. सुखभद्र

10. हरनाव चरणन्दी

11. राजवल

12. अमिपुर

राज्य सरकार से वातरक, कालिन्द्री, धतरवाड़ी तथा गोडेथाड़ परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा किए गए संप्रक्षणों पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया, है जिनके प्राप्त होने पर इनको स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा। कसवती, अम्बाजल और चप्परवाड़ी (लुनीवाव स्थल) पर समिति के संप्रेक्षण आवश्यक कार्यवाही करने के लिए शीघ्र ही राज्य सरकार को भेज दिए जाऐंगे।

सुखभद्र परियोजना की जांच पूरी होने ही वाली है। हाल ही में प्राप्त राजवल तथा अमिपुर परियोजनाओं की जांच की जा रही है। कारजन, सिपु, रामी और हरनाव चरणन्दो परियोजनाओं में अन्तर्राज्यीय पहलु निहित है जिन्हें, इनपर आगे कार्यवाही करने से पूर्व हल करना आवश्यक है।

गुजरात में सोवियत संघ की सहायता से प्राकृतिक तेल तथा गैस आयोग द्वारा तेल की खोज

888. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकरिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक तैल तथा गैस आयोग ने गुजरात में सोवियत संघ की सहायता से तेल खुदाई कार्य को बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) तथा (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अनुसार आयोग गुजरात सहित अपने सभी क्षेत्रों में तेल की खोज तथा तेल उत्पादन के कार्य बढ़ाना चाहता है। इस कार्यक्रम में गुजरात में 1978-79 तक कच्चे तेल के उत्पादन को वर्तमान 37 लाख मी० टन प्रति वर्ष की दर से बढ़ाकर 54.5 लाख मी० टन प्रतिवर्ष करने और पंचवर्षीय अवधि में कुल 26.19 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पुरा करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नाजुक क्षेत्रों में विशेषज्ञों तथा उपकरणों, अतिरिक्त, पुर्जे आदि की सप्लाई के रूप में रुस की सहायता की अपेक्षा करता है।

गुजरात राज्य में नायलोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव

889. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य में एक नायलोन कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी हां। प्रतिवर्ष 2,100 मीटरी टन नायलोन फिलामैन्ट यार्न के उत्पादन के लिये गुजरात राज्य में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये गुजरात इंडस्ट्रीयल इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन लि० को 29 दिसम्बर, 1971 को एक आशय-पत्र दिया गया था ;

(ख) आशय-पत्र में निम्नलिखित शर्तें लगाई गई हैं :—

(1) सयंत्र तथा मशीनों के आयात के प्रबन्ध तथा विदेशी सयोग की शर्तें इस प्रकार तय की जाएंगी जिस से सरकार की तसल्ली हो जाये।

(2) परियोजना की वित्त संबंधी व्यवस्था करने के लिये यदि बाहरी पार्टियों को साम्य शेयरों की पेशकश की जाती है तो नायलन यार्न उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों को इन साम्य शेयरों में हिस्सा लेने में तरजीह दी जानी चाहिए।

(3) निगम के पास कम से कम 26% साम्य शेयर होने चाहिए और इसे सब से बड़ी एकाकी शेयरधारी होना चाहिए जिससे वित्तीय एवं प्रबन्धकीय नियंत्रण का रखा जाना सुनिश्चित हो जाए। इस परियोजना में प्राइवेट पार्टियों को सम्मिलित करने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव के लिये निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

(4) किसी थोक विक्रय एजेन्ट की नियुक्ति नहीं की जायेगी और तैयार उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बांटे जाएंगे।

(5) उपक्रम द्वारा अन्तिम उत्पाद के लिये लिया जाने वाला मूल्य इस तरह तय होना चाहिए जिससे पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक विकास मंत्रालय में सरकार की तसल्ली हो जाए।

बाढ़ों और हड़तालों से नष्ट हुई रेल संपत्ति की क्षतिपूर्ति और मरम्मत में हुआ व्यय

890. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ों और हड़तालों से, जोनवार, रेल सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई ; और

(ख) उक्त अवधि में जोनवार रेल सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति और मरम्मत पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सोन नदी के जल का वितरण

891. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सोन नदी के जल के वितरण से संबंधित विवाद को निपटाने के लिए बिहार सरकार ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश तथा बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच विचार-विमर्श के उपरांत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारो के बीच सितम्बर, 1973 में पहले ही सोन जल के उपयोग पर समझौता हो चुका है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

892. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **सिंचाई और विदयुत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हाल ही में स्वीकृति की गई, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनार्थी का विवरण क्या है ; और

(ख) देश के पिछड़े क्षेत्र में, विशेषतया मैसूर में, सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इनमें से कोन-सी योजनाएं बनायी गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिदधेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31-1-1974 तक) 71.18 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायतासे राज्य बिजली बोर्डो को 197 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के निकटवर्ती 1595 हरिजन बस्तियों को बिजली देने के लिए 80.945 लाख रुपये को ऋण सहायता से 24 स्कीमें भी स्वीकृत की है। राज्यवार ब्यौरों के विवरण उपाबन्ध-एक और दो के रूप में संलग्न हैं। **[ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6236/74]**

कर्नाटक के लिए कुल छ: स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इनमें पिछड़े क्षेत्रों के लिए दो स्कीमें शामिल हैं ।

2. निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमें मुख्यत: क्षेत्र के विकास की व्यवस्था करने के लिए बनाई जाती हैं। सभी स्कीमों की अभिकल्पना इस प्रकार से की जाती है कि इनके अंतर्गत लाभ उठाने वाले क्षेत्र को सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार हो सके ।

बंगलौर-मैसूर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

893. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-मैसूर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका सार क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) बेंगलू-मैसूर मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। रिपोर्टों की जांच हो जाने के बाद ही इस आमान परिवर्तन के बारे में कोई विनिश्चय किया जा सकेगा।

राक फोस्फेट क्षेत्रों के विकास के लिये समिति

894. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राक फोस्फेट क्षेत्रों के विकास के लिये तकनीकी पहलुओं की जांच हेतु एक समिति की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तों उसके निदेश पद क्या हैं और समिति अपना कार्य कब से चालू कर देगी ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनकी जांच की जाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ग) सरकार ने देश में राजस्थान क्षेत्र के झमारकोत्रा में केवल राक-फोसफोट क्षेत्रों के विकास के लिए तकनीकी तथा अन्य पहलुओं की जांच हेतु एक समिति का गठन किया है। कमेटी की शर्ते निम्न प्रकार है :—

(1) विदेशी परामर्श दात्री फर्मों द्वारा किये गये सम्भाव अध्ययनों का मूल्यांकन नीहित तकनीकी बातों का परीक्षण तथा झमारकोत्रा राक फोसफेट के भण्डारों के विकास को स्वीकृत तथा शीघ्र करने की आवश्यकता के लिए आवश्यक और उपायों को निर्धारित करना तथा निवेश के स्तर के नीहित तथा वित्तव्यवस्था की पद्धति को ध्यान में रखने के पश्चात् भण्डारों के विकास के सम्बन्ध में काफी उचित सम्मिलित संरचनाओं के बारे में सुझाव देना।

कमेटी के शीघ्र ही एक कार्यप्रारम्भ करने की आशा है।

वर्ष 1973 के दौरान घायल होने तथा मृत्यु होने के दौरान दिया गआ मुआवजा

895. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान मृत्यु होने तथा घायल होने के लिये कुल कितने व्यक्तियों को तथा कितनी राशि का मुआवजा दिया गया; और

(ख) मुआवजे की मात्रा का निश्चय करने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) 1973 में गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरने, समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लग जाने की कोटियों में गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये या घायल व्यक्तियों की कुल संख्या 828 है। अभी तक उन्हें क्षतिपूर्ति के रुप में 1,40,447 रुपये का भुगतान किया गया है।

(ख) गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण होने वाले क्षतिपूर्ति के दावों का निपटारा भारतीय रेल अधिनियम की धारा 82–ए से 82–जे तक के अन्तर्गत किया जाता है जिसमें इस प्रकार के दावे, दावा आयुक्त के पास जाते हैं जो उन पर निर्णय देता है ड्यूटी पर मारे गये या घायल रेल कर्मचारियों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमेय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

हावड़ा में इन्स्पेक्टर कार्यालय का तोड़ा फोड़ा जाना

896. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जनवरी, 1974 को दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा स्थित इंस्पक्टर के कार्यालय को यात्रियों द्वारा तोड़ा-फोड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकारी सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 11–1–1974 को हावड़ा में दो गाड़ियों के देर से पहुंचने के विरोध में।

(ग) टेलीफोन, फर्नीचर और प्रलेखों को क्षति पहुंची। क्षती का हिसाब रुपयों में नहीं लगाया गया है।

सियालदह साउथ रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा का अस्त-व्यस्त होना

897. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह साउथ रेलवे स्टेशन पर 7 जनवरी, 1974 को रेल-सेवा अस्त-व्यस्त हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक गाड़ी के यात्रियों द्वारा एक गार्ड के साथ हाथापाई किये जाने पर 7–1–1974 को गार्डों ने आन्दोलन कर दिया जिसके कारण सियालदह दक्षिण रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के कारण सेवायें अस्त-व्यस्त हो गई थीं। इन सेवाओं के अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण लगभग 12,832.00 रु० की हानि होने का अनुमान है।

मालदा से बलूरघाट बारास्ता गाजोल या अकलाकली से बलूरघाट रेल लाइन्स

898. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा से बलूरघाट वरास्ता गाजोल या अकलाकली से बलूरघाट बरास्ता बुनियादपुर-गंगारामपुर रेल लाइन बिछाने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गाजोल, बुनियादपुर और गंगारामपुर-होकर अकलाकली से बेलूरघाट तक एक बड़ी लाइन सम्पर्क के लिए यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इस की रिपोर्ट की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित रेलवे लाइन का निर्माण वस्तुतः कब शुरू किया जायेगा, इस सम्बन्ध में निर्णय सर्वेक्षण-रिपोर्ट की जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

पांचवी योजना में पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिये बिजली का मूल्यांकन

899. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा इस बारे में जो मूल्यांकन किया गया था कि पश्चिम बंगाल को सिंचाई के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, अवास्तविक था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में सिंचाई पर बिजली की खपत केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों के आधार पर अनुमानित की गई थी । बहरहाल इसके पश्चात्, विभिन्न कठिनाइयों के कारण, प्रस्तावों तथा बिजली भार मांग में कमी करनी पड़ी । इस संबंध में पांचवीं योजना के लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

योजना आयोग का अशोधित तेल का आयात कम करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना

900. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा की बचत करने के उद्देश्य से योजना आयोग का अशोधित तेल का आयात कम करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग तेल के आयात में कितनी कमी करने का सुझाव दिया था; और

(ग) प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) योजना आयोग द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बागमती परियोजना को पूरा करना

901. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीतामढ़ी जिले के संसद सदस्यों, विधायकों तथा अन्य लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बागमती परियोजना को जल्दी पूरा कराने के संबंध में कोई ज्ञापन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिधेश्वरद् प्रसाद): (क) से (ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि क्षेत्र के संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य बिहार के सिंचाई और विद्युत मंत्री से मिले थे और उनको एक ज्ञापन दिया था। वे चाहते थे कि बागमती परियोजना को क्रियान्वयन के लिए यथाशीघ्र हाथ में लिया जाए। उनको यह स्पष्ट कर दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार को स्कीम के बारे में कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 20 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है। योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने तथा अपेक्षित धनराशि के उपलब्ध हो जाने के पश्चात परियोजना को हाथ में लिया जाएगा ।

6—2 LSS/74

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

902. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1972–73 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस अवधि के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) ग्राम विद्युती कार्यक्रम में पम्पसेटों का ऊर्जन तथा ग्रामों का विद्युतीकरण निहित होता है। बिहार में वर्ष 1972–73 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में प्राप्त लक्ष्यों तथा प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	लक्ष्य	प्राप्ति
ग्राम	1750	902
	17000	14,275

लक्ष्यों में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) विद्युत सैक्टर में अपर्याप्त विकास;

(2) पर्याप्त पारेषण तथा वितरण प्रणाली का अभाव; और

(3) वित्तीय संसाधनों की तंगी।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ स्थिति में सुधार करने के लिए उपायों में ये शामिल है —

(1) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य बिजली बोर्ड को योगात्मक धन की व्यवस्था कर दी है। 25.03 करोड़ रुपयें को ऋण सहायता की 43 स्कीमें अब तक स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन स्कीमों में 4832 ग्रामों का विद्युतीकरण और 53,789 पम्पसेटों का ऊर्जन परिकल्पित है। इनमें से 3 स्कीमें उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों के विस्तार से संबंधित है। इन स्कीमों का 3–5 वष की अवधि में पूर्ण होने अनुसूचित है।

(2) बिहार समेत, पूर्वी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति का पुनरवलोकन करने के लिए और इस स्थिति में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत उपमंत्री की अध्यक्षता में संसद- सदस्यों की एक समिति गठित की गई है।

(3) पांचवीं योजना में "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है। इसमें राज्य के अन्दर 30–40% ग्राम्य जनता को बिजली देना परिकल्पित है।

उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में बिजली की कमी

903. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बिजली के अभाव को कम करने के लिए यदि कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है तो क्या;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग किए जाने की संभावना है; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस अभाव को दूर करने के लिए पड़ौसी राज्य कहां तक सहायता करेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति, उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के राज्यों को छोड़कर, साधारणतया संतोषप्रद है ।

इन राज्यों में विद्युत की कमी के कारण उद्योगों पर प्रतिबंधक विद्युत कटौतियां लगा दी गई हैं और उद्योगों को विद्युत उपलभ्यता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) कोयले और ईंधन तेल, फालतू पुर्जों आदि की सप्लाई तथा परिवहन के लिए प्रबंध तथा प्रबोधन करके वर्तमान विद्युत प्रतिष्ठानों के समुपयोजन को अधिकतम किया जा रहा है ।

(2) अंतर्राज्यीय लाइनों के निर्माण तथा भार प्रषण केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है ।

(3) विद्युत-उत्पादन यूनिटों के शीघ्र चालू करने को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है जो पूरी होने वाली है ।

(4) पड़ौसी राज्यों के बीच विद्युत के विनिमय को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि विद्युत उत्पादन क्षमता का इष्टतम समुपयोजन हो सके और आरक्षण की आवश्यकताओं को न्यूनतम किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश बदरपुर/भाखड़ा प्रबंध बोर्ड/मध्य प्रदेश और बिहार से लगभग 2.8 मिलियन यूनिट विद्युत प्रतिदिन राहत के रूप में प्राप्त कर रहा है । हरियाणा बदरपुर/भाखड़ा प्रबंध बोर्ड प्रणालियों से 0.5 से 0.7 मिलियन यूनिट विद्युत प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है । तमिलनाडु केरल से लगभग 1.3 मिलियन यूनिट विद्युत प्रतिदिन और कर्नाटक से 0.3 मिलियन यूनिट विद्युत प्रतिदिन राहत के रूप में प्राप्त कर रहा है । आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से 0.3 मिलियन यूनिट तक विद्युत राहत के रूप में प्राप्त कर रहा है ।

कुप्रबन्ध के कारण फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, त्रावनकोर को घाटा

904. श्री वयालार रवि :
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर के कुप्रबन्ध के कारण उर्वरक उत्पादन रुक गया है जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये का घाटा हुआ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) सरकार ने इस बारे में कुछ रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) उद्योगमंडल सयंत्र के अनेक खण्ड पुराने हो रहे हैं और इन से आधुनिक सयंत्र के कार्यनिष्पादन का स्तर प्राप्त किये जाने की आशा नहीं की जा सकती । उत्पादन को अधिकतम करने के लिए इसकी मरम्मत करने तथा अन्य बाधाएं दूर करने संबंधी कई कार्यक्रम हाथ में लिए गए ह । जहां तक कोचीन

सयंत्र का संबंध है, यह इस समय क्षमता के लगभग 60% पर कार्य कर रहा है। उच्चतम उत्पादन स्तर पर प्राप्त करने के लिए कुछ यांत्रिक तथा अन्य परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

चार रेलवे जोनों में चालू की गई और की जाने वाली रेल सेवाएं

905. **श्री फतहसिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे में कितनी नई गाड़ियां चलाई गई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी और नई गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कौन सी लाइनें बनाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पिछले वर्ष (1973) के दौरान दक्षिण रेलवे पर 8, उत्तर रेलवे पर 14, पूर्व रेलवे पर 8 और पश्चिम रेलवे पर 2 अनुपनगरीय नवी गाड़ियां चलायी गयीं या उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया।

(ख) उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर नयी दिल्ली और न्यु बोंगाईगांव/गुवाहाटी के बीच 26–1–74 से सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जोड़ी डाक गाड़ियां चलायी गयी हैं। इसी तारीख से पूर्व रेलवे पर डेरी-आन-सौन-गया के बीच चलने वाली एक जोड़ी सवारी गाड़ियों को भी पटना तक बढ़ा दिया गया है। इस समय और अनुपनगरीय गाड़ियां चलाये जाने का कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जिन गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है उनके लिए लाइन क्षमता मौजूद हैं।

कोचीन जाने वाली जयंती जनता एक्सप्रेस गाड़ी का रद्द किया जाना

906. **श्री फतहसिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन जानेवाली जयंती-जनता एक्सप्रेस गाड़ी को गत दिसम्बर/जनवरी के दौरान लगभग एक महीने तक रद्द किए जाने के क्या कारण थे जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी;

(ख) क्या समस्तीपुर जाने वाली जयंती जनता एक्सप्रेस गाड़ी को रद्द नहीं किया गया था; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लोको कर्मचारी हड़ताल के कारण 19–12–73 से 20–1–74 तक 131 डाउन/132 अप मंगलूर/कोचिन नयी दिल्ली जयन्ती एक्सप्रेस सवारी का चलना रद्द कर दिया गया था।

(ख) लोको कर्मचारी आन्दोलन के कारण 20–12–73 से 27–12–73 तक नयी दिल्ली और समस्तीपुर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली 153 अप/154 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी का चलना भी रद्द कर दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल-लाइनों का विद्युतीकरण

907. श्री फतहसिंह राव गायकवाड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कितने किलोमीटर रेल-लाइनों का विद्युतीकरण किया गया ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी नई लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहंमद शफी कुरेशी) : (क) 1973 के दौरान 123 मार्ग किलोमीटर।

(ख) चालू वर्ष के दौरान पश्चिम रेलवे के मिलगाम-विरार खण्ड (मार्ग कि० मी० 314) और दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंचकुरा-अल्दिया खंड (मार्ग कि० मी० 69) पर बिजली की गाड़ियां चलाए जाने की आशा है ।

विभिन्न यूनियनों के लिये संचार साधनों की व्यवस्था करना

908. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी-वार विभिन्न यूनियनों के लिए संचार साधनों की व्यवस्था करने हेतु आगे क्या कार्यवाई की गई है ;

(ख) क्या बातचीत के लिए किसी फोरम का न होना विभिन्न हड़तालों का एक कारण है; और

(ग) यदि हां, तो संचार साधनों की व्यवस्था करने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एकात्मक संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त संघों द्वारा कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इन मान्यता प्राप्त संघों और उनके माध्यम से सभी श्रेणियों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हैं और इन शिकायतों को रेलों में विभिन्न स्तरों पर क्रियाशील वार्ता तंत्र के माध्यम से दूर किया जाता है। रेलों पर ऐसी 700 से अधिक श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्रेणी का एक पृथक सम्पर्क सरणि प्रदान करना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से रेलों का कार्य संचलन पूर्ण रूप से अस्तव्यस्त हो जायेगा । फिर भी यदि किसी श्रेणी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो उस पर भी विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आल इंडिया ट्रेन एग्जामिनर्ज एसोसियेशन द्वारा 'नियमानुसार कार्य' करने का आह्वान

909. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल एंडिया ट्रेन एग्जामिनर्ज एसोसियेशन ने 30 जनवरी, 1974 को अर्ध-रात्रि से अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिए नियमानुसार कार्य करना आरम्भ किर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने रेल प्रशासन को अपना 8-सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया है; और यदि हां, तो उस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या कोई बातचीत उनसे चल रही है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 8-सूत्री मांग-पत्र प्राप्त हो गया है । ऐसे मामलों को मान्यता-प्राप्त श्रम संगठनों द्वारा समय समय पर उठाया जाता है और इन्हें विभिन्न स्तरों पर स्थायी वार्ता तंत्र तथा संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में विचार-विमर्श करके निपटाया जाता है । इसके अतिरिक्त गैर-मान्यता-प्राप्त संगठनों सहित किसी अन्य साधनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी उचित विचार किया जाता है और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । प्रशासन द्वारा जो भी मांग प्राप्त होती है, उस पर वित्तीय साधनों नियमों-विनियमों के स्वरूप, मांग स्वीकार करने का औचित्य और उसकी स्वीकृति से उठने वाले परिणामों जसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उन पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है ।

(ग) अखिल भारतीय गाड़ी-परीक्षक संघ से कोई सीधी वार्ता नहीं की जा रही है, क्योंकि गैर-मान्यता प्राप्त कोटि-वार संघों से इस प्रकार की वार्ता नहीं की जा सकती ।

पैट्रोल, गैस और मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था में सुधार के लिये उपाय

910. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोल, गैस और मिट्टी के तेल की वर्तमान वितरण व्यवस्था में सुधार की काफी आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या सुधार करने का है, और कब तक इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) पूर्णत: विचार करने पर तेल उत्पाद के वितरण के सम्बन्ध में वतमान मशीनरी जिसमें कुकिंग गैस एवं मिटटी का तेल सम्मिलित है, पर्याप्त समझा गया है । जब कभी स्थानीय अथवा अस्थाई कमी होती है तो राज्य सरकारों/संघ शास्ति क्षेत्रों को सूचित किया जाता है जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम के व्यवस्थाओं के अनुसार उनमें निहित की गई संविधिक शक्तियों के अन्तर्गत वे उत्पाद के उचित वितरण को सुनिश्चित कर सकें । तथापि राज्य सरकारों/संघ शास्ति क्षेत्रों से कहा गया है कि उपलब्ध सप्लाई के उचित वितरण पर सभी सम्भाव्य उपाय अपनाय । जल्दी प्रभावित होने वाली वस्तुओं जसी मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में मासिक आधार पर उपलब्ध होने वाली मात्राओं के बारे में भी राज्य सरकारों/संघ शास्ति क्षेत्रों को सूचित किया गया है । इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल के कुल वितरण में वृद्धि करने के लिए हाल ही में तेल कम्पनियों ने अपने वर्तमान मोटर गैसोलीन तथा डीजल आयल के फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से ग्राहकों को सीध मिट्टी का तेल बेचना प्रारम्भ कर दिया है । इस सुविधा को बढाने में प्रगति प्राप्त की जा रही है ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड के कर्मचारियों की मांग पर समझौता

911. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों की कुछ मांगे बातचीत द्वारा समझौते करने के लिए विचाराधीन पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही है, और यदि हां, तो इस क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रबन्ध मण्डल जो कि कुछ मामलों पर यूनियन के साथ भी बातचीत कर रहा है, के परामर्श से ये विचाराधीन है ।

पैट्रोल का राशन करने के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ मतभेद

912. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल के राशन को लागू करने की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ): (क) जी, नहीं। पेट्रोल के राशन को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है अथवा इस मामले पर कोई अन्तिम विचार नहीं किया है। दोनों मंत्रालयों के बीच विचार और/या दृष्टिकोण में कोई मतभेद नहीं है।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औषध अकाल की संभावना

913. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में देश में औषधी के लगभग अकाल की कोई संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान प्रादेशिक सेना को तैनात किया जाना

914. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोको संचल कर्मचरियों के नवम्बर-दिसम्बर, 1973 के आन्दोलन के दौरान भारतीय रेलवे में प्रादेशिक सेना की कितनी यूनिटें तैनात की गई थी ;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों द्वारा संचालित रेलगाड़ियों अथवा इंजनों के साथ कुछ रेल दुर्घटनायें हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं के कारण कुल कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) 9 रेलवे प्रादेशिक सेना दल (निर्माण एवं अनुरक्षण कम्पनियों को एवं एक मामले में वर्कशाप कम्पनी को भी छोड़ कर)।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मियांभाई न्यायाधिकरण की सिफारिशों के परिणामस्वरूप नैमितिक कर्मचारियों के अधिकृत वेतन

915. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मियां भाई न्यायाधिकरण की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और सभी भारतीय रेलवे में क्रियान्वित कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां तो (एक) उनके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में ऐसे कितने नैमित्तिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनके लिए अधिकृत वेतनमान स्वीकार कर लिए गए हैं ; (दो) ऐसे नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें चार महीने की सेवा के पश्चात अधिकृत वेतन मंजूर किए गये हैं ; (तीन) प्रत्येक रेलवे में अभी तक कितने नैमित्तिक कर्मचारियों को स्थानीय दरों पर ही वेतन मिलता है और सिफारिशों के अनुकूल उनके वेतन में सुधार क्यों नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी के सम्बन्ध में रेल श्रम अधिकरण, 1969 की मुख्य सिफारिशों और उन पर की गयी कार्रवाई का एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6237/74]** रेलों पर क्रियान्वित के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और शीघ्र निर्णय और क्रियान्वयन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

तापीय बिजली घरों में कोयले का प्रयोग

916. **श्री शशि भूषण :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस लाख टन भट्टी के तेल से भी अधिक तेल की प्रतिवर्ष बचत की जा सकती है यदि ट्राम्बे, अहमदाबाद, धुवरन और बरौनी के चारों जनित्र एकक भट्टी तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करना शुरू कर दें ;

(ख) क्या इन बिजली घरों के बायलरों में कोयले का प्रयोग करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इन बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और कब तक इन प्रस्तावों के क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इन विद्युत केन्द्रों में स्टीम रेजिंग उपस्कर को कोयले से जलने वाले उपस्कर में परिवर्तित करके ईंधन तेलों जैसे एल० एस० एच० एस०, एच० एच० एस० और आर० एफ० ओ० (परन्तु भट्टी में उपयुक्त होने वाला तेल नहीं) की खपत में लगभग एक मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बचत की जा सकती है। (ये केन्द्र फर्नेस तेल का उपयोग नहीं करते हैं)।

(ख) और (ग) जहां भी संभव है, इन केन्द्रों में तेल से जलने वाले उपस्करों को कोयले से चलने वाले उपस्करों में परिवर्तित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। विद्युत केन्द्र प्राधिकरणों से इस प्रकार के परिवर्तन करने की दिशा में आवश्यक उपाय शुरू करने के लिए कहा गया है। इस परिवर्तन के अंतर्गत बायलरों और आनुषंगिकों में कुछ अदला-बदली तथा अतिरिक्त आनुषंगिक संयंत्रों जैसे

राख तथा कोयला संभालने वाले संयंत्रों का प्रतिष्ठापन शामिल है। परिवर्तन के कार्यक्रम बनाते समय परिवर्तन की अवधि के दौरान होने वाली विद्युत उत्पादन में कमी को ध्यान में रखना होगा और इनकी प्रणाली की स्थिति एवं प्रचालन के उपयुक्त बनाना होगा। इन विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की पर्याप्त सप्लाई और परिवहन हेतु आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं तथा कोयले का भण्डार बनाना पड़ेगा।

Irrigation Facilities in Adivasi areas during Fifth Plan

917. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the irrigation schemes formulated by Government for being implemented in the Adivasi areas during the Fifth Plan period;

(b) whether the progress in providing irrigation facilities in the Adivasi areas has so far been negligible ;

(c) if so, the steps being taken by Government to improve the situation; and

(d) the total amount proposed to be spent for providing facilities to these Adivasi areas during the Fiftn Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) to (d) An Expert Committee on Tribal development in the Department of Social Walfare has estimated that irrigation facilities in the tribal (Adivasi) areas is less than 1% of the cultivated area as against all-India average of about 21%. In order to provide irrigation facilities quickly to a maximum number of tribals, a selective approach has been suggested. For this purpose, the tribal blocks in the country are being identified in order to ensure that the development of these blocks is taken up. It has been proposed to draw out a plan in consultation with the States for major and medium irrigation projects in the tribal areas for a possible outlay of Rs. 30 crores in the Central sector of the Fifth Five Year Plan.

Electrification of Tribal Areas in M.P.

918. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number and names of the tribal areas in Madhya Pradesh which are proposed to be electrified during the next two to three years;

(b) whether any suggestions have been received from the Madhya Pradesh Government in this regard; and

(c) the percentage of expenditure to be borne by the Central Government and the Government of Madhya Pradesh, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) to (c) The programme of rural electrification is formulated and executed by the State Electricity Boards. However, additive finances are provided to State Electricity Boards by the Rural Electrification Corporation for implementation of their schemes. The Madhya Pradesh State Electricity Board contemplates to electrify the tribal areas of Konta and Dantewara. The scheme is estimated to cost Rs. 79.26 lakhs for electrification of 39 villages and energisation of 450 pumpsets. The State Electricity Board proposes to seek loan assistance to the extent of Rs. 26·55 (i.e. 33% of the cost) lakhs from the Rural Electrification Corporation for the implementation of the above scheme. This is scheduled for completion in a period of 5 years.

सहिबगंज रेलवे कार्यालय की अल्मारी से 1,25,000 रुपये लापता होना

919. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1974 को साहिबगंज रेलवे कार्यालय (पूर्व रेलवे) की अलमारी से 1,25,000 रुपये लापता पाये गये थे;

(ख) इस बारे में की गई जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या इसमें कुछ रेल कर्मचारियों का हाथ पाया गया है और यदि हां,तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्र (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। 14-1-1974 को वेतन कार्यालय, साहिबगंज (पूर्व रेलवे) की तिजोरी से 1,25,000 रुपये की रकम कम पायी गयी।

(ख) और (ग) सरकारी रेलवे पुलिस, साहिबागंज ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने साहिबगंज वेतन कार्यालय के तीन वरिष्ठ वेतन क्लर्कों और एक रोकड़-खलासी को गिरफ्तार किया है। रेल प्रशासन द्वारा उन्हें निलम्बित भी कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जांच जारी है।

रुमानिया के सहयोग से तेल की खुदाई करने वाले एक एकक की स्थापना

920. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं योजना में रुमानिया के सहयोग से समुद्र तट से दूर तेल के लिये खुदाई सम्बन्धी एक एकक को स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह एकक किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और इस एकक की लागत क्या होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

असम सरकार दवारा अशोधित तेल पर रायल्टी की वृद्धि की मांग

921. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

श्री बी० मायावन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में उत्पादित अशोधित तेल पर रायल्टी बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा मांगी गई वृद्धि का मुख्य ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय किया गया; और

(ग) रायल्टी में इस प्रकार की वृद्धि के मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल तथा अन्य सह-उत्पादों के उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में 'तैयार' भोजन देने की योजना को लागू करना

922. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री नरेंद्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी वाली सभी महत्वपूर्ण गाडियों में यात्रियों को तैयार भोजन सप्लाई करने की योजना लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मूख्य बातें क्या हैं; और

(ग) मेल गाड़ियों तथा अन्य लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में वर्तमान खान-पान सेवाओं की तुलना में इस प्रकार की योजना कितनी अधिक लाभकारी तथा प्रभावी सिद्ध होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) "परोसने के लिए तैयार" भोजन की योजना निम्नलिखित गाड़ियों में पहिले से ही लागू की जा चूकी है :—

(i) नयी दिल्ली-बम्बई सेन्ट्रल के बीच 3/4 फ्रन्टियर डाक और 25/26 वातानुकूल/पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियां

(ii) मद्रास सेन्ट्रल और नयी दिल्ली के बीच 15/16 ग्रैन्ड ट्रक/वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां।

(iii) मुगलसराय और दिल्ली के बीच 1/2 डाकगाड़ियों।

(iv) समस्तीपुर-नयी दिल्ली के बीच 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियां।

(v) दिल्ली और अहमदाबाद के बीच 31/32 जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियां।

इस योजना को धीरे धीरे दूसरी महत्वपूर्ण लम्बी दूरी वाली गाड़िवों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत स्थायी खानपान इकाइयों के आधुनिकीकृत भोजनालयों में तैयार भोजन ले लिया जाता है और उसे गाड़ियों में यात्रियों को परोसे जाने के लिए पैंट्री कार के गर्म डिब्बों में रखा जाता है। इस योजना से निम्नलिखित लाभ हैं :—

(क) भोजन अधिक साफ-सुथरी हालत में तैयार किया जाता है और गर्म रखा जाता है।

(ख) बैरे, रसोइये आदि जैसे खान-पान के कर्मचारी साफ वर्दी में रहते हैं।

(ग) बर्तनों की धुलाई पैंट्री कार में न करके उन्हें मूल रसोईघरों को भेज दिया जाता है।

विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर रेलगाड़ियों को रोका जाना

923. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य उच्च सरकारी अधिकारियों के अनुरोध पर कुल कितनी बार रेलगाड़ियों को रोका गया और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अगस्त, 73 से जनवरी, 74 के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों आदि के गाड़ी में सवार होने/उतरने के लिए निम्न यात्री गाड़ियों को अनिर्धारित रूप में रोका गया :—

दक्षिण रेलवे	114 बार
उत्तर रेलवे	3 बार
पूर्व रेलवे	1 बार
अन्य रेलवे	कुछ नहीं

रेल-प्रशासनों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के दिये जाए अनुदेशों को पुन: दुहरा गया कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए गाड़ियों न रोकी जाए ।

थोन बांध परियोजना का पांचवीं योजना में सम्मिलित किया जाना

924. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोन बांध परियोजना को पांचवीं योजना में सम्मिलित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के शुरू होने से उसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की तथा उसपर कुल कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):(क) से (ग) थोन बांध परियोजना को 1968 को दरों पर अनुमानित लागत लगभग 89 करोड़ रुपये थी। संशोधित लागत का 146 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। क्योंकि कुछ अन्तर्राज्यीय पहलुओं के संबंध में राज्यों संबद्ध के बीच अब तक मतैक्य नहीं हो पाया है इसलिए इस परियोजना को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। पंजाब राज्य को वार्षिक योजना 1974-75 में 5 करोड़ रुपये का मामूली सा प्रावधान स्पष्ट रुप में इस शर्त पर किया गया है कि इस परियोजना पर व्यय परियोजना को हर प्रकार से स्वीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा। परियोजना कार्य को पूरा करने में, इसको आरंभ करने के बाद, लगभग 7-8 वर्ष लग जाएंगे।

उर्वरकों में नेफथा का विकल्प

925. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक एककों में नेफथा का कोई विकल्प ढूंढने का प्रयास कर ही है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या इस दिशा में कुछ अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग) वर्तमान नेफथा पर आधारित उर्वरक संयंत्र में नेफ्था के प्रतिस्थापना की कोई योजना नहीं है। सरकार की नीति है कि स्थानीय उपबन्धता, प्रौद्योगिकी सम्बन्धी दृष्टिकोण, समग्र अर्थव्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए उर्वरक कार्यक्रम के विविधीकृत फीडस्टाक पर आधारित किया जाय।

पोचमपड्ड श्रीसेलम तथा नागार्जुन सागर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

926. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोचमपड्डु, श्रीसेलम तथा नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार का विचार कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नागार्जुनसागर परियोजना पर बांध का निर्माण पूरा हो गया है। दक्षिण तट नहर पर प्रथम 91.2 किलोमीटर पर और वाम तट नहर पर प्रथम 115 किलोमीटर पर कार्य पूर्ण हो गया है तथा सिंचाई के लिए पानी छोड़ दिया गया है। अन्य रीचों में कार्य किया जा रहा है। परियोजना की कुल 8.32 लाख हैक्टेयर शक्यता में से 4.13 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता का अब तक निर्माण किया जा चुका है।

2.3 लाख हैक्टेयर की सिंचाई करने के लिए बनाई गई पोचमपाद परियोजना का चरणों में कार्यान्वियन किया जा रहा है। 1.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए प्रथम चरण में बांध का आंशिक ऊंचाई तक तथा दक्षिण तट नहर का 113 किलोमीटर की लम्बाई तक निर्माण किया जाएगा। अब तक बांध के प्रथम चरण पर लगभग 90 प्रतिशत कार्य हो चुका है और नहर को 68 किलोमीटर तक खोद दिया गया है शेष भाग में खुदाई कार्य किया जा रहा है। मार्च 1974 के अन्त तक 53000 हैक्टयर की सिंचाई शक्यता का निर्माण हो जाने की संभावना है।

श्रीसेलम परियोजना पर गहरे चेनल भाग में बांध को गहनतम नींव स्तर से 170 मीटर के औसत स्तर तक उंचा उठा दिया गया है। ब्लाक 6 से 11 और 16 से 17 में चिनायी कार्य प्रगति पर है। विद्युत् सुरंग पर कार्य पूर्ण होने वाला है और बिजली घर के लिए खुदाई कार्य आरंभ कर दिया गया है। विद्युत्-उत्पादन उपस्कर की सप्लाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ये परियोजनाएं राज्य योजना का अंग हैं। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रुप में दी जाती है और यह किसी विशेष सैक्टर अथवा परियोजना से सम्बन्ध नहीं होती। आन्ध्र प्रदेश के पांचवीं योजना कार्यक्रमो में इन परियोजनाओं के लिए अधिकतम संभव प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है और यह संभावना है कि नागार्जुनसागर परियोजना तथा पोचम्पाद परियोजना का प्रथम चरण पांचवीं योजना में काफी हद तक पूर्ण हो जाएगा। श्रीसेलम परियोजना के छठी योजना के आरंभ में पूरी हो जाने की सम्भावना है।

अशोधित तेल के आयात में कमी

927. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अशोधित तेल के आयात में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा मुख्य बात क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में ग्रामों के विद्युतीकरण का उपबंध

928. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय 48 करोड़ रुपये है। इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 27 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के अधीन स्थापित किए जाने वाले दो औषध कारखानों का स्थान

929. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के अधीन पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित दो औषध-कारखानों के स्थान के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या एक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जायगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल के लिये सिंचाई योजना

930. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल राज्य की किस मुख्य सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है; और

(ख) कौन-कौन सी ऐसी वर्तमान परियोजनाएं हैं जिन्हें पांचवीं योजना में भी शामिल किये जाने की संभावना है और नवीनतम मूल्यांकनों के अनुसार उनके निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी पांचवीं योजना में निम्नलिखित छः बृहत् और 19 मध्य सिंचाई स्कीमों के प्रस्ताव रखे हैं :—

बृहत् स्कीमे

1. तीस्ता बराज
2. मयूराक्षी नहर का पलस्तर करना
3. अपर कंसवती
4. द्वारकेश्वर
5. गजोल लिफ्ट सिंचाई
6. डोलांग

मध्यम स्कीमे

1. बाराभूम
2. तारागोनिया
3. पार्गा
4. मोटरजोरे
5. साल्दा
6. वेको
7. पटलोई
8. हनुमट

9. टाटको

10. बन्धु का विस्तार

11. रामचन्द्रपुर

12. साली

13. रेलिखोला

14. जार्दा

15. हालांग वेलाकोलिया

16. अमोदर ताराजुली

17. लिपंदा जोरी-पारा

18. गोलखारोजोरे

19. नारायणपुर-सोन नदी

(ख) मयूराक्षी, दामोदर घाटी निगम और कंसवती नामक तीन बृहत् स्कीमों तथा हिंगलों और सहराजोरे नामक मध्यम स्कीमों पर कार्य पांचवीं योजना में चालू रखा जाएगा। उनकी वर्तमान निर्माण स्थिति इस प्रकार है :

मयराक्षी परियोजना

परियोजना काफी हद तक पूर्ण हो चुकी है। वितरण प्रणाली पर कार्य हो रहा है। इसके 1976 तक पूर्ण होने की संभावना है।

दामोदर घाटी निगम सिंचाई कार्य

जल मार्गों जैसे छोटे-छोटे कार्यों के निर्माण को छोड़कर सभी कार्य प्रायः पूर्ण हो चुके हैं।

कंसवती परियोजना

परियोजना काफी हद तक पूर्ण हो चुकी है। नहर प्रणाली पर कार्य हो रहा है। परियोजना के 1978-79 तक पूर्ण होने की संभावना है।

हिंगलों और सहाराजोरे परियोजना

कार्य के 1974-75 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में पैट्रो-रसायन उद्योग

931. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पेट्रो-रसायन उद्योगों की रुप रेखा क्या है जो पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई हैं अथवा जिन्हें स्थापित करने का विचार है।

(ख) इन में से कितनी चल रही है और कितनी विचाराधीन है ; और

(ग) हल्दिया केमिकल्स के विशेष संदर्भ में वे कारण क्या है जो रास्ते में रुकावट सिद्ध हो रहे है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ग) इस समय पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम सम्भरण माल पर आधारित कोई पेट्रो-रसायन यूनिटें अर्थात् रसायन यूनिटें कार्यान्वित नहीं है। मैसर्स भारतीय उर्वरक निगम पेट्रो-कच्चे माल पर आधारित 100 की० टन प्रतिदिन क्षमता वाले मेथानोल परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना की 1976-77 में प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

पांचवी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में पेट्रो-रसायन के सम्बन्ध में कार्यक्रम को गुजरात में बडौदा में नफथा क्रैकर तथा डाउनस्ट्रीम यूनिटों तथा असम में बोगर्ड भाव परिष्करण शाला/पेट्रो-रसायन उद्योग समुह के पूरे होने तक ढीला किया जा रहा है। पांचवी योजना के दौरान हल्दिया अथवा कहीं अन्य स्थानों पर पेट्रो-रसायन के लिए चालू वर्ष में किसी बड़े प्रायोजना की स्थापना का विचार नहीं है।

पैट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन द्वारा भारत के साथ विशिष्ट व्यवहार करने के लिये भारत द्वारा अनुरोध

932. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अशोधित तेल की सप्लाई के लिये पेट्रोलियम का निर्मात करने वाले देशों के संगठन को भारत के साथ विशिष्ट व्यवहार करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ): (क) और (ख) अशोधित तेल की सप्लाई के प्रश्न इसके मूल्य में अत्याधिक वृद्धि तथा स्थिति पर काबू पाने के लिए सम्भाव्य तरीको के सम्बन्ध में अशोधित तेल की सप्लाई के लिए पेट्रालियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन के महासचिव के साथ तथा औपचारिक अथवा अनौपचारिक रुप में यथासम्भव ओ पी ई सी देशो के अनेक सदस्यों सरकारों के साथ बातचीत हुई। इस सम्बन्ध में ओ पी ई सी द्वारा कोई अतिन्म निर्णय नहीं किया गया है।

पैट्रोल के स्थान पर डीजल का प्रयोग करने की विधि

933. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पालमपुर कस्बे में एक आटोमोबाइल मकैनिक ने भारी वाहनों को चलाने के लिये पैट्रोल के स्थान पर डीजल का प्रयोग करने की विधि का विकास किया है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय को पालमपुर नगर के किसी आटोमोबाइल मिस्त्री की विशेष युक्ति की सूचना नहीं मिली है। मोटर वाहन सामन्यतया मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल तेल से चलाये जाते हैं। जहां मोटर स्प्रिट सामान्यतया मोटर कारों तथा स्कुटरों आदि में प्रयुक्त किया जाता है वहां भारी वाहन, जैसे ट्रक तथा बसें साधारणतया हाई स्पीड डीजल तेल से चलाई जाती है परन्तु इन्जन तथा अन्य सम्बन्धित पुर्जों में यथावश्यक परिवर्तन करके मोटर-स्प्रिट से चलने वाले मोटर वाहनों को हाई स्पीड डीजल आयल से चलाया जा सकता है।

सिंचाई कुएं तेल की प्राप्ति के बारे में किसानों का दावा

934. श्री **पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी तिजोर जिले में स्थित 1200 फुट गहरे सिंचाई कुंए में से कुछ किसानों को तेल मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हां। एक बोर होल में, जिसे जल के लिए लगभग 600 फीट की गहराई तक खोदा गया था, द्रव्य के रूप में कच्चा तेल दिखालाई दिया था।

(ख) सम्बन्धित द्रव्य के नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है और अतिरिक्त आंकड़े एकत्र करने के लिए जांच की जा रही है।

उर्वरक उद्योग में पुंजी निवेश पर लाभप्रदत्ता को बढ़ाने के उपाय

935. श्री **महेंद्र सिंग गिल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ ऐसे उपाय करने के बारे में विचार कर रहे रही है जिनसे निकट भविष्य में उर्वरक उद्योग में पुंजी निवेश की लाभप्रदत्ता को सुनिश्चित किया जा सके तथा बढ़ाया जा सके ; और

(ख) वर्तमान तेल संकट को देखते हुये कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के प्रोद्योगिकी सम्बन्धी मूल्यांकन के बारे में प्रयास करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) उर्वरक उद्योग में नये निवेशों को बढ़ाने के लिए समुचित प्रोत्साहन देने सम्बन्धी सामान्य प्रश्न विचाराधीन है। इसमें उर्वरक फीडस्टाक के चयन के सम्बन्ध में सरकारी नीति को भी ध्यान में रखा जा रहा है, इससे कई ऐसे मामले सम्बद्ध है ; जिनको संमेकित रूप से निपटाने की आवश्यकता है। इस बीच सरकार ने उर्वरक उत्पादन में फीड स्टाक के रूप में इंधन तेल का उपयोग किए जाने पर उसके लिए उत्पादन शुल्क की छूट देने का निर्णय किया है।

(ख) तलचर, रामागुण्डम तथा कोरवा में कोयले पर आधारित तीन नए बड़े उर्वरक संयंत्रों का कार्यान्वियन किया जा रहा है। अन्य स्थानो में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए सम्भाव्यता अध्ययन भी किए जा रहे है।

बदरपुर तापीय बिजलीघर से पंजाब को बिजली की सप्लाई

936. श्री **महेंद्र सिंह गिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को बदरपुर तापीय बिजली घर से तभी से बिजली का अपना भाग नही मिल रहा है जब से इसने बिजली पैदा करना आरंभ किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) बदरपुर ताप-विद्युत् केन्द्र का केवल एक यूनिट ही वाणिज्यिक उत्पादन के लिए चालू किया गया है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को सापेक्ष कमियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उससे विद्युत् का वितरण, कर रही है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कार्यो में कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अधीन निरीक्षण

937. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अधीन हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कार्यों के बारे में जिस निरीक्षण का आदेश दिया गया था, वह पूरा हो चुका है; और

(ख) क्या सरकार ने निरीक्षण के काम में, कम्पनी के कार्यों की अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले किन्हीं निष्पक्ष व्यक्तियों को सम्बध्द किया है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) यह निरीक्षण, अधिनियम की धारा 209 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (2), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को, कम्पनियों की लेखा-वहियों तथा अन्य अभिलेखों के निरीक्षण करने की आवश्यक शक्तियां दी गई हैं, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।

हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड के भारतीयकरण के लिये कार्यवाही

938. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जो की लन्दन स्थित युनीलीवर की एक सहायक विदेशी फर्म है और जिसमें 85 प्रतिशत विदेशी और केवल 15 प्रतिशत भारतीय इक्विटी पुंजी है, देश में पूरी तरह से लो-टैक्नोलोजी-हाई-प्राफिट उपभोक्ता क्षेत्र में कार्य करती है जिससे हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कम्पनी के भारतीयकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि इस प्रक्रिया को खत्म किया जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनीकार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) यह मेसर्स यूनीलीवर लिमिटेड, ब्रिटेन, की सहायक कम्पनी है । इसके उत्पादन की मुख्य भूमिका साबुन, कृत्रिम शोधक, तैयार किया हुआ भोजन, मिश्रित पशुचारा आदि है । सौन्दर्य प्रसाधन इनकी सम्पूर्ण गतिविधि के अल्प भाग की रचना करता है । विदेशी मुद्रा आरक्षणों का धन-प्रेषण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुमोदन से, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में किया जाता है ।

(ख) जैसे और जब भी एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21 और 22 आदि के अन्तर्गत प्रसार हेतु, कम्पनी का कोई प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है तो यह शर्त होगी कि कम्पनी अपनी विदेशी साम्यता की विशिष्ट प्रतिशत द्वारा सम करेगी जिससे क्रमिक रूप से विदेशी साम्य योगदान जो अनुबद्ध हो रहा है, नीचे आ जाएगा ।

पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पेनल का बनाया जाना

939. **श्री राम प्रकाश** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के अध्ययन के लिए सरकार ने कोई पेनल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो पेनल के मुख्य कृत्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) पूर्वी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति का पुनरवलोकन करने के लिए जनवरी, 1974 में एक समिति बनायी गई है । समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(1) असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण में की गई प्रगति का पुनर्वलोकन करना ;

(2) इन राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की धीमी प्रगति के कारणों को ढूंढना और प्रगति में तेजी लाने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही की सिफारिश करना ;

(3) ग्राम विद्युतीकरण के लिए इन राज्यों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं में किए गए प्रावधानों की और संस्थानों से उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों की पर्याप्तता की जांच करना और आवश्यक सुझाव देना ।

हरिजन बस्तीयों के विद्युतीकरण के लिए बिजली बोर्डों द्वारा धन का उपयोग न किया जाना

940. श्री राम प्रकाश : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत धन का उपयोग राज्यों में कुछ बिजली बोर्डों ने नहीं किया है

(ख) क्या राज्य सरकारों ने धन का उपयोग न करने के कारण बतायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्राल में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने पहले से विद्युतीकृत ग्रामों को सहवर्ती हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को 61 स्कीमें स्वीकृत की हैं । इन स्कीमों में 280.31 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है । इसमें से राज्य बोर्डों द्वारा 226.83 लाख रुपये ले लिए गए हैं । आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु के राज्य बिजली बोर्डों ने अभी तक पूरी राशि नहीं ली है । प्रगति में तेजी लाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाया गया है ।

Linking of Bulandshahr with Dibai

941. Shri Chandra Bhal Mani Tewari : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether major towns such as Jahangirabad, Anup Shahr and Dibai of Bulandshahr District of Uttar Pradesh are lagging behind in development due to the absence of rail links; and

(b) if so, whether Government propose to take any action in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Railways are not aware that the development of these places has been hampered due to the absence of rail links.

(b) Does not arise.

Supply of Oil by Arab Countries to Affluent Countries at Reduced Prices

942. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether certain Arab Countries have agreed to supply oil to affluent countries after effecting heavy reduction in the price of oil;

(b) whether the per barrel price of oil offerred to those countries is half the price offered to India; and

(c) if so, Government of India's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) Government are not aware of any direct sale arrangements for the supply of oil by Arab countries to affluent countries at reduced rates.

Brick batting by excited crowd at Meerut Station on 22nd January, 1974

943. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the crowd at Meerut Railway Station got excited and resorted to brick batting after a leg of a passenger was amputated on the 22nd January, 1974 and consequently the movement of trains was hampered;

(b) if so, loss suffered by the Railways as a result thereof;

(c) Whether other causes of the incident have also been enquired into; and

(d) the condition of the injured person and whether any compensation has been given to him?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) The Mob damaged 3 telephones and Window panes of Enquiry office and ASM Office, Meerut City.

(c) Being a Law and Order problem, the case is being investigated by GRP/Meerut City who have registered a case vide Crime No. 14 dated 22-1-1974 u/s 147/332-267 IPC and 120 & 121 Indian Railways Act.

(d) The injured person Shri Bali Ram S/O Shri Kale Ram is reported to be progressing satisfactorily in Pyare Lal Hospital, Meerut City and a sum of Rs. 300 has been paid to the victim by the Railway as Ex-gratia payment.

तेल का उत्पादन करने वाले देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के पश्चात इसके आयात पर खर्च की गई धनराशि

944. **श्री वेकारिया :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल का उत्पादन करने वाले देशों द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के पश्चात इसके आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(ख) उसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) 16 अक्तूबर, 1973 से अबतक कच्चे तेल के आयात के लिए 185 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जारी की गई है।

(ख) पूरे विषय का विस्तार से पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस अवस्था में देश की अर्थ-व्यवस्था में कच्चे तेल के मूल्यों की वृद्धियों के समग्र प्रभावों का स्पष्ट रूप से पाना सम्भव नहीं है। इस तथ्य से स्थिति और उलझनपूर्ण हो गई है कि इस समय कच्चे तेल के मूल्य अन्तिम है और वे अभी स्थिर नहीं हो पाये हैं।

Allotment of Quarters to drivers belonging to Scheduled Castes in Kota Workshop

945. Shri Onkarlal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Drivers in Kota Workshop and the number among them who have been allotted residential quarters;

(b) the number of Scheduled Caste Drivers who joined in 1968 but have not been provided with residential accomomdation;

(c) whether any Drivers who joined in 1969 and 1970 have been provided with residential accommodation; and

(d) whether there are any Drivers belonging to Scheduled Caste who joined in 1968 but have not been allotted residential accommodation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Moh. Shafi Qureshi) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Payment to Railway Loco Employees for strike period

946. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Mohammed Koya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Loco running staff has not so far been paid their pay for the strike period; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) Yes.

(b) It has been decided that the principle of "No work-No pay" will be followed for such periods of absence on illegal strike and this has been applied to the Loco running staff who went on strike during November-December, 1973.

पांचवीं योजना में उड़ीसा को स्वर्णरेखा परियोजना का शामिल किया जाना

947. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने स्वर्णरेखा संबंधी विशेषज्ञ समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो इसे पांचवां पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) उड़ीसा को राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे सुवर्णरेखा समिति की सिफारिशों की जांच कर रहे हैं। बहरहाल, राज्य सरकार ने सुवर्णरेखा स्कीम को, जिसमें उड़ीसा को निम्न पहुंचों में तटबंधों और जल-निकाय में सुधार शामिल है, अपनी पांचवी योजना में अस्थायी रूप से शामिल कर लिया है।

ईरान द्वारा विदेशों की तुलना में भारत से अशोधित तेल की वसूली की जाने वाली दर

948. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि अमरीका ने ईरान के साथ एक समझोता किया है जिसके अनुसार अशोधित तेल की निर्धारित की गयी दर उस दर से लगभग आधी है जिसे ईराक भारत से वसूल करने के लिये सहमत हुआ है ?

(ख) क्या उन्हीं शर्तों को ब्रिटन और यूरोपीय साझा बाजार के कुछ अन्य देशों पर भी लागू किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समझोते से लाभ प्राप्त करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) तथा (ख) कच्चे तेल की इस प्रकार की सीधी बिक्री के बारे में सरकार के पास जानकारी नही है।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

रूपसा तथा बांगरीपोश लाइन को बड़ी लाइन (दक्षिण) पूर्व रेलवे में बदलने के बारे में सर्वेक्षण

949. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे की रूपसा तथा बांगरीपोश लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में ओर कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के आधारपर रूपसा-बांगरीपोश-तालबंद के छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बोर्ड द्वारा रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद इस पर निर्णय किया जायेगा।

रेलवे खान-पान सम्बन्धी समिति का भंग किया जाना

950. **श्री श्यामसुंदर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे की रेलवे खान-पान सम्बन्धी समिति को भंग कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं, दक्षिण - पूर्व रेलवे पर खान-पान पर्यवेक्षण समिति की वर्तमान अवधि 31-3-74 को समाप्त होगी।

लेकिन यह विनिश्चय किया गया है कि प्रत्येक रेलवे पर खान-पान पर्यवेक्षण समिति के कार्यों को क्षेत्रीय रेलवे, उपयोगकर्ता सलाहकार समिति में एकीकरण कर दिया जाये । अत: एक अप्रैल 1974 से बनायी जानेवाली क्षेत्रीय, रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समितियां अधिक व्यापक आधार पर होंगी, और ये खान-पान सम्बन्धी मामलों को भी निपटाया करेंगी । परिणाम स्वरूप वर्तमान खान-पान पर्यवेक्षण समितियों का उनकी वर्तमान अवधि समाप्त होने के बाद पुनर्गठन नहीं किया जायेगा।

बांकुरा दामोदर सैक्शनों में यात्री गाड़ियां

951. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में बांकुरा दामोदर सैक्शनों की सभी यात्री गाड़ियां नियमित रूप से चलती रही थीं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। दिसम्बर, 1973 में 9–12–73 और 10–12–73 को इंजनों में हुई खराबी के फलस्वरूप इंजनों की कमी के कारण बांकुरा-दामोदर खण्ड की केवल दो गाड़ियों 5 अप और 2 डाउन को रद्द किया गया। लेकिन जनवरी 1974 में, इस खण्ड की यात्री-गाड़ियों को छोटी लाइन के इंजनों में अधिक खराबी के कारण, कई बार रद्द करना पड़ा।

(ख) छोटी लाइन के भाप-चालित इंजनों में अधिक खराबी होने के कारण यात्री गाड़ियों को रद्द किया गया। बांकुरा-दामोदर छोटी लाइन खण्ड बांकुरा से शुरू होता है। आद्रा मंडल पर यह छोटी लाइन का इकहरी लाइन वाला खण्ड है। इस लाईन को मैसर्स मैक्लोडा एण्ड कम्पनी लिमिटेड से लिया गया था। छोटी लाइन के चार बागनाल भाप इंजन तो 60 साल से भी पुराने और गैर-मानक स्तर के इंजन हैं। इन इंजनों में विशेष यांत्रिक खराबी पैदा हो गयी थी और उसे दूर करने के लिए विशेष पुर्जों के निर्माण के उद्देश्य से इन्हें रोके रखना पड़ा। दक्षिण-पूर्व रेलवे के सतपुडा क्षेत्र के छोटी लाइन के इंजनों को इसलिए प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि ये इंजन भारी एक्सलों वाले होने के कारण बांकुरा दामोदर खण्ड के रेल-पथ के लिए अनुपयुक्त हैं और मैसर्स मैक्लौड एण्ड कम्पनी से लिए गये गैर-मानक इंजनों की तुलना में इन इंजनों की गति-सीमा भी काफी कम है।

यात्रियों तथा वर्दवान रेलवे अधिकारियों के बीच झगड़ा

952. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जनवरी, 1974 को साहेबगंज लूप लाइन, वर्दवान के दैनिक यात्रियों तथा वर्दवान रेलवे प्राधिकारियों के बीच झगड़ा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस झगड़े के क्या कारण थे ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) डाउन कोल-फील्ड एक्सप्रैस वर्दवान पर निश्चित समय से एक घंटा देर से पहुंची। इसलिए यात्रियों ने राजधानी एक्सप्रैस को वहां रोकना चाहा। किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि राजधानी एक्सप्रैस का मार्ग वर्दवान से दूसरी लाइन पर बदल दिया गया था।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षात्मक उपायों के तौर पर रेलवे सुरक्षा दल और राजकीय रेलवे पुलिस को 7 दिन के लिए संयुक्त रुप से गश्त लगाने का आदेश दे दिया था। रेल प्रशासन द्वारा हर प्रकार से रेलगाड़ियों को समय पर चलाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र का पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य चलाना

953. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र आरम्भ से पूरी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ): (क) और (ख) यह संयंत्र इस समय 50 से 60 प्रतिशत की अपनी क्षमता के बीच काम कर रहा है और इस संयंत्र की शक्ति निरन्तर बढ़ रही है। अपव्ययी ऊष्मा वसूली प्रणाली की रुकावटो और अन्य यान्त्रिक समस्याओं पर काबू पाने तथा उच्चतर पर उत्पादन सुस्थिर करने के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे है।

गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

954. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालु वित्त वर्ष के दौरान गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अतंर्गत कितने गांव पहले ही आ चुके हैं ; और

(ख) गुजरात में कितने गांव अभी तक बिजली के बिना है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चालू वित्तीयवर्ष के दौरान दिसम्बर, 1973 तक गुजरात में 279 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) गुजरात में 18,584 ग्राम हैं। इनमें से 31-12-1973 तक 5,539 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और 13,045 ग्रामों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है। पांचवी योजना के दौरान 1,030 और ग्रामों का विद्युतीकरण करना आयोजित है।

लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले को दी जाने वाली अग्रिम आरक्षण सुविधाओं तथा सेवाओं में सुधार

955. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रथम तथा तृतीय श्रेणी में, विशेषकर, लम्बी दूरी की यात्रा करने वालों को पर्याप्त अग्रिम आरक्षण सुविधाएं तथा सेवाए उपलब्ध नहीं कराई जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में स्थिति सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गाड़ियों की सभी श्रेणियों में स्थान का आरक्षण "पहले आवे सो पहले पावे" के आधार पर निम्नलिखित सीमाओं के भीतर किया जाता है :—

(1) 640 कि० मी० से अधिक दूरी की यात्रा के लिए वातानुकूल प्रथम श्रेणी .	30 दिन
(2) 640 कि० मी० तक की दूरी की यात्रा के लिए वातानुकूल प्रथम श्रेणी	20 दिन
(3) प्रथम श्रेणी	20 दिन
(4) दूसरी और तीसरी श्रेणी (बैठने की जगह और शायिका तथा वातानुकूल कुर्सी यान में बैठने का स्थान)	10 दिन

(ख) आरक्षण और बुकिंग समिति ने अक्तूबर, 1973 में जो अपनी पहली रिपोर्ट पेश की है, उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, स्थान के आरक्षण और टिकटों की बिक्री की सुविधाओं में सुधार लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टालों की संख्या में वृद्धि

956. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे बुक-स्टालों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या ऐसे बुक-स्टालों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और क्या ये स्टाल देश के शिक्षित बेरोजगार युवकों को सौंपे जायेंगे ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) इस समय जिन स्टेशनों पर बुक-स्टाल नहीं है लेकिन वहां बुक स्टाल जरूरी समझे गए हैं, तथा भविष्य में खुलने वाले नये स्टेशनों पर बुक स्टालों की 18 से 30 वर्ष की उम्र के ऐसे बेरोजगार स्नातकों को आवंटित करने का प्रस्ताव है जो या तो स्वयं अपनी सहकारी संस्था बनाले या जहां राज्य सरकार द्वारा अनुमति हो, वहां ऐसी संस्था बनाये जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, या जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारों में कार्य करें ।

विवरण

रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध बूक स्टालों की राज्यानुसार संख्या

असम	21
नागालैंड	1
पश्चिम बंगाल	60
बिहार	82
उत्तर प्रदेश	114
महाराष्ट्र	127
मध्य प्रदेश	54
हरियाणा	12
आन्ध्र प्रदेश	56
कर्नाटक	28
गोवा	2
उड़ीसा	14
तमिलनाडु	33
केरल	19
गुजरात	44
राजस्थान	47
पंजाब	14
हिमाचल प्रदेश	1
दिल्ली	12
चंडीगढ़	1

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये सहायता

957. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात को सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण तथा राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई वित्तीय सहायता देगी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन का प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी समग्र विकासात्मक योजनाओं में से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता राज्यों को योजनाओं को वित्तीय व्यवस्था करने के लिए दी जाती है परन्तु यह ब्लॉक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में होती है और किसी विशेष विकास क्षेत्र अथवा परियोजनाओं से सम्बद्ध नहीं होती।

बहरहाल, 1973-74 के दौरान भारत सरकार द्वारा गुजरात सरकार को 3.5 करोड़ रुपये को एक विशेष गैर-योजना सहायता कडाना परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी गई थी।

अहमदाबाद से वाराणसी तक सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिये किया गया अभ्यावेदन

959. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे व्यक्तियों से, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं परन्तु अब गुजरात में अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर रहते हैं, अहमदाबाद से बरास्ता कानपुर और लखनऊ वाराणसी तक सीधी रेल गाड़ी चलाने के लिये कोई और अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) मार्ग में लाइन क्षमता पर भारी दवाव और वाराणसी में पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण प्रस्तावित गाड़ी चालू करना परिचालन की दृष्टि से सम्भव नहीं है।

विदेशी औषध कम्पनियों के बारे में कार्यकारी दल

959. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही विदेशी औषध कम्पनियों अत्याधिक खपत वाली उन औषधियों के अधिक मूल्य वसूल करके भारी मुनाफा कमा रही है जिनके मूल्य उन मूल्यों से अधिक है जो ये कम्पनियां अपने देश से वसूल कर रही है;

(ख) क्या इस समूचे मामले की जांच करने और सरकार को अपने सुझाव देने के लिये सरकार ने एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी; और

(ग) यह कार्यकारी दल कब नियुक्त किया गया और इसके सदस्य कौन कौन थे तथा यदि इस दल के विचार सरकार के पास उपलब्ध हैं तो उनकी रुपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) टैरिफ आयोग ने 17 प्रपुंज औषधियों का मूल्य निर्धारण किया था और जिन उचित विक्रय मूल्यों की इस ने सिफारिश की थी, उन्हें औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत सांविधिक तौर पर

निर्धारित किया गया था। देश में उत्पादित किये जाने वाले सभी अन्य प्रपुंज औषधियों के मूल्य उस स्तर पर रोक दिये गये थे जो 15 मई, 1970 अर्थात् औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के लागू होने से पहले, प्रचलित थे।

कुछ प्रपुंज औषधियां राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जा रही है। इन प्रपुंज औषधियों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते है। यह अनुमान है कि 1973-74 के दौरान राज्य व्यापार निगम 17.73 करोड़ रुपये के मूल्य की प्रपुंज औषधियां का आयात करेगा।

और बातों के साथ साथ 24 प्रपुंज औषधियों के लागत ढांचे का अध्ययन करने के लिये औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में 11 सितम्बर, 1970 को सरकार ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी। प्रपुंज औषधियों पर विदेशी औषध कम्पनी की लाभ-प्रदता का प्रश्न कार्यकारी दल को विशेष रुप से नहीं भेजा गया था।

कार्यकारी दल का गठन इस प्रकार है:—

1. श्री एन० एन० वांछू	चेयरमैन
2. श्री जी० के० अभ्यंकर	सदस्य
3. श्री आर० जयराम	सदस्य
4. औषध नियन्त्रक (i) (डी. जी. एच. एस) . . .	सदस्य
5. डा० ए० सीतारमैया, सीनियर आई० ए० डी० जी० टी० डी०	सदस्य
5.-क, डा० बी० शाह, औद्योगिक सलाहकार, डी० जी० टी० डी० डा० ए० सीतारमैया के वैकल्पिक	सदस्य
6. मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय या उनके मनोनीत .	सदस्य
7. औद्योगिक विकास मंत्रालय, आई० टी० एण्ड सी० ए० आर्थिक सलाहकार	सदस्य
8. निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान	सदस्य
9. श्री मनमोहन सिंह, प्रो० आफ इंटरनैशनल ट्रेड, दिल्ली स्कूल आफ एकानोमिक्स, दिल्ली विश्व-विद्यालय . . .	सदस्य
10. सलाहकार (डी) पैट्रोलियम और रसायन विभाग सदस्य .	सचिव

कार्यकारीदल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

नेफ्था आदि आधारित परियोजनाओं का उत्पादन कार्यक्रम

960. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चालू वर्ष के दौरान अलवार, मद्रास, गोरखपुर, और ट्राम्बे स्थित देश में चार नेफ्था आधारित उर्वरक परियोजनाओं के उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और यदि हां, तो प्रत्येक परियोजनाओं में कितना उत्पादन होने का अनुमान है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : 1973-74 के दौरान नेफ्था की कमी से इन चार संयंत्र के उत्पादन पर कोई असर पड़ने की सम्भावना नहीं है। तथापि बिजली और अन्य प्रतिबन्धों के कारण वास्तविक उत्पादन में उस उत्पादन में कमी हो सकती है

जिसका पहले अनुमान किया था। अप्रैल, 1973 से जनवरी 1974 के दौरान उत्पादन का प्राप्य लक्ष्य निम्न प्रकार है:—

(1,000 मीटरी टन)

	एन	पी$_2$ ओ5
अलवास	33	19
मद्रास .	101	44
गोरखपुर	56	..
ट्राम्बे	47	26

राज्य में सिंचाई दरों तथा बिजली प्रशुल्कों में वृद्धी

961. **श्री रामकंवर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा के लिए राज्यों को सिंचाई दरों तथा बिजली प्रशुल्क का पुनरीक्षण करने को कहा है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अनुरोध के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में सिंचाई में दरों तथा बिजली प्रशुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि होने को संभावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा कितना अतिरिक्त राजस्व एकत्र किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर हुए व्यय से वित्तीय लाभ में वृद्धि करने तथा योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से सिंचाई दरों और बिजली टैरिफ में उपयुक्त संशोधन करने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार करने का समय–समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। इस बात पर छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट में तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् को दिसम्बर, 1973 में हुई बैठक में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में भी जोर दिया गया है।

(ख) और (ग) इन मद्दों पर कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है। इस समय उनके बारे में ब्यौरा देना संभव नहीं है।

गुजरात को बिजली की सप्लाई

962. **श्री रामकंवर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात के लिए बिजली की सप्लाई में भारी रुकावट हुई है;

(ख) क्या इसका कृषि और उद्योग पर उलटा प्रभाव पड़ा है ;

(ग) गुजरात के विभिन्न कृषि तथा औद्योगिक वर्गों को कितनी हानि हुई; और

(घ) इस राज्य को बिजली को पर्याप्त सप्लाई करने के लिए यदि कोई प्रयत्न किए जा रहे है तो वे क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 26 जनवरी से 7 फरवरी, 1974 तक धुवरण ताप विद्युत् केन्द्र में एक बायलर के फोर्ड आउटेजेस और 1 फरवरी से 8 फरवरी, 1974 तक तारापुर परमाणुकेन्द्र में एक यूनिट के बन्द होने के कारण इस अवधि के दौरान गुजरात में विद्युत् की आपूर्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। 8 फरवरी, 1974 से राज्य में विद्युत् सप्लाई की स्थिति सामान्य होने की सूचना मिली है।

(ख) बिजली की सप्लाई में कमी कर देने के कारण औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को उत्पादन में कुछ हानि के साथ-साथ असुविधा भी हुई।

(ग) केवल बिजली की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई हानि का मूल्यांकन इसमें निहित तथ्यों के बाहुल्य के कारण नहीं किया जा सकता।

(घ) राज्य में अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन शक्यता को चालू करने में शीघ्रता की जा रही है। उकाई जल विद्युत् केन्द्र में 75–75 मैगावाट के दो यूनिटों के अप्रैल और जून, 1974 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश द्वारा अन्तर्राज्यीय नदीघाटी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना

963. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विदयुत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों राज्यों के अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं को शीघ्रता और सचारू रूप से तथा कार्यकुशलता से निष्पादित करने के लिए एक कन्ट्रोल बोर्ड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहमत हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विदयुत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश ने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना संबंधी संकल्प के प्रारूप पर अपनी सहमति भेज दी है। मध्य प्रदेश के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

964. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या सिंचाई और विदयुत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1973 के दौरान ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न राज्यों को राज्यवार, कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी;

(ख) प्रत्येक राज्य ने इस राशि का कितना प्रतिशत भाग उन गांवों के विद्युतीकरण पर खर्च किया जिनमें पूर्णतः हरिजन ही रहते हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसे राज्य भी है जिन्होंने स्वीकृत राशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया और इस राशि को व्यपगत होने दिया ; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या है ?

सिंचाई और विदयुत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1973 के वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की 236 स्कीमें स्वीकृत की है। स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा उपाबंध–1 में विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6238/74]**

(ख) से (घ) 31-1-1974 तक विद्युतीकृत ग्रामों की सहवर्ती हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के संबंध में स्वीकृत राशि और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ली गई राशियों का विवरण उपाबंध 11 में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6238/74]**

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजराथ, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों ने पूरी धनराशियां नहीं ली है। निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों को रद्द होने नहीं दिया जाएगा और जब भी व्यय के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों से ऋण के अनुरोध प्राप्त होनेपर उन्हे दे दिया जाता है।

नई सिंचाई परियोजना के लिये केरल सरकार का प्रस्ताव

965. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने किसी नयी सिंचाई परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) नई सिंचाई स्कीमों, जिनकी रिपोर्ट केरल सरकार से अब तक प्राप्त हुई है, की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:——

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राक्कलित लागत (लाख रु०)	लाभ (हजार एकड़)
1.	बानसुरसागर . . .	1,137.10	23.87
2.	तिरुनेली	650.00	8.90
3.	केरल भवानी टेल-रेस	805.00	32.30
4.	वामनपुरम . .	747.28	20.00
5.	करापुभा	389.00	9.37
6.	अट्टापदी	476.00	7.28
7.	नूलापुभा .	290.00	8.50
8.	मंजत . .	318.00	4.86
9.	थोन्डर	299.00	6.07

Location of Places by Geologist for Oil and Gas exploration

966. **Shri Chandu Lal Chandrakar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of places about which geologists have given information to Government during the last six months regarding the possibility of oil and gas being available there;

(b) the number of places out of them about which Government have taken any action so far ;

(c) the total expenditure incurred so far on the digging operations at those places; and

(d) the number of operations proved successful or are likely to prove successful?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Raid on passenger train by Railway Police on 22nd January, 1974

967. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on the 22nd January, 1974 the Railway Police conducted a raid on a passenger train and recovered from various compartments food-grains being smnggled into Delhi from Uttar Pradesh;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether Government propose to take more stringent measures in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :(a) and (b) Yes. The Government Railway Police conducted a raid at Ghaziabad on 21st January, 1974 and not on 22nd January, 1974, at 03·45 hrs. on 1 AJD passenger train on its arrival at Ghaziabad from Aligarh and recovered 18 bags of unclaimed maize weighing 1,530 kgs. and 7 bags of Bajra weighing 490 kgs. from various compartments.

(c) Such raids will continue to be conducted to stop smuggling.

Presence of Oil in Coal Quarries in Kalol region of Khambat

968. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports regarding the availability of sufficient quantity of oil in coal quarries in the Kalol region of Khambat in the north of Ahmedabad;

(b) whether the pressure of oil at that place is very high;

(c) if so, the action taken so far in this connection; and

(d) other features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Government are aware of the availability of oil in limited quantities from rock strata consisting of coal and siltstone horizons occuring at a depth of about 1450 metres from the ground surface in the Kalol area north of Ahmedabad.

(b) Oil contained in the above mentioned rock strata was initially under very high pressure. Since the commencement of oil production, the pressure has been declining.

(c) and (d) An oilfield has been developed in the Kalol area and the field is already on commercial production. Oil produced from this field is being transported by pipeline and supplied to Gujarat Refinery at Baroda.

Trains for Office coming people in Delhi

969. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether government propose to start more trains for office coming people in Delhi;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the expected income to Railways as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :(a) There is no proposal at present.

(b) & (c) Do not arise.

बाढ नियंत्रण और जलसाधनों के विकास हेतु भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग द्वारा दिया गया सुझाव

971. **डा० रानेन सेन :**

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग ने बाढ़ नियंत्रण तथा संबधित क्षेत्रों में जल साधनों के विकास हेतु दोनों देशों को योजनाओं में तालमेल लाने के बारे में सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) संबंधित सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) भारत और बंगला देश के बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन विकास संबंधी योजनाओं का समन्वय करने का काम भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग को सौपे गए कार्यो में सम्मिलित है ।

भारत और बंगला देश दोनों ने इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण की विभिन्न स्कीमें प्रस्तावित की हैं । संयुक्त अध्ययन दलों के जरिए आयोग उन स्कीमों, जिनमें समन्वित आयोजनकी आवश्यकता है का पता लगाने और दोनों देशों को इष्टतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपायों को सिफारिश करने में प्रयत्नशील है ।

दोनों सरकारें इन प्रयत्नों के महत्व तथा उपयोगिता को मान्यता देती है ।

तेल शोधक कारखानों में बचे हुए भारी ईंधन तेल का पुनः परिष्करण

972. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शेल और एसो नामक दो विदेशी तेल शोधक कारखानों को छोड़ कर देश के अन्य तेल शोधक कारखानों में बचे हुये भारी इंधन तेल का पुनः परिष्करण करने के लिए सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) क्या तेल शोधक कारखानों द्वारा कच्चे तेल के पहले परिष्करण में छोड़े गये 40 सें 50 प्रतिशत तक बचे हुए भारी तेल से कटेलिस्टिक क्रेकिंग अथवा हाईड्रोक्रेकिंग द्वारा देश 25 प्रतिशत अधिक पेट्रोल मिट्टी तेल तथा डीजल तेल प्राप्त कर सकेगा;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ): (क) कोयाली,कोचीन तथा मद्रास की परिष्करणशालाओं को छोड़कर अन्य सभी परिष्करणशालाओं के पास अवशिष्ट इंधन तेल की अनुषंगी प्रोसेसिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध है । जहां बर्मा शैल, कालटैक्स तथा एस्सो परिष्करण-शालाओं की कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिटें है वहां डिग्बोई, गौहाटी तथा बरौनी परिष्कणशालाओं की कोकिंग यूनिट है जो अवशिष्ट ईंधन तेल को हल्के तथा मध्यम आंसुतों में परिवर्तित करती है ।

(ख) तथा (ग) हाइड्रो क्रैकिंग तथा कैटेलिटिक क्रैकिंग सुविधाओं की व्यवस्थासे हल्के तथा मध्यम आसुतों का अधिक उत्पादन होगा परन्तु मद्रास, बरौनी तथा डिग्बोई परिष्करणश ालाओं में इस प्रकार

की, सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्भव न होगा। इन परिष्करण शालाओं के पास स्नेहक तेलों वैक्सेस की रिकवरी की सुविधाएं है। देश में इनकी भी अतिआवश्यकता है। अन्य तथ्य जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है इस प्रकार है :—ईंधन तेल के उत्पादन की आवश्यकता, क्योंकि देश में काफी अधिक ईंधन तेल की भी आवश्यकता है, क्रैकिंग आदि के बाद बचने वाली सामग्री के निपटान की समस्याएं। परन्तु जहां भी सम्भव हो अनुषंगी प्रोसेसिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जायेंगे। कोयाली में एक क्रैकिंग अथवा कोकिंग यूनिट तथा बोंगाई गांव में एक कोकिंग यूनिट की स्थापना की सम्भाव्यता का अध्ययन किया जा रहा है। निर्माणाधीन मथुरा परिष्करण शाला में दस लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक कैटेलिटिक क्रैकर सम्मिलित किया गया है।

सोनीपत/पानीपत और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करना

973. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री सोनीपत/पानीपत और दिल्ली के बीच वाली रेलवे लाईन को दोहरा करने के बारे में 28 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हा, तो कार्य कब तक शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) सब्जीमण्डी और गनौर के बीच 56.35 किलोमीटर पर दोहरी लाइन बिछाने का काम 1974–75 के बजट में शामिल किया जा रहा है।

पालामऊ तथा रांची को नई रेलवे लाइन से मिलाना

974. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाचवीं पंचवर्षीय योजना में पालामाऊ तथा रांची को नई रेलवे लाइन से मिलाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में पालामऊ-रांची रेल सम्पर्क का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। पाचवीं योजना के उत्तरवर्ती वर्षों में निर्माण के लिए नयी योजना शुरू करने के सम्बन्ध में यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बी० डी०, जी० डी० तथा सी० जी० लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों की बिगड़ती स्थिति

975. **कुमारी कमला कमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बी० डी०, जी० डी० तथा सी० जी० लाइनों के बीच चलने वाली गाडियों की बिगड़ती स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गाड़ियों की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कायवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बरवाडीह-डेहरी-आन-सोन, गढ़वा रोड़-डेहरी-आन-सोन और पोपन-गढ़वा रोड़ खण्डों पर गाड़ियों के संचलन पर हाल में कर्मचारी

8—2 LSS/74

आंदोलनों, कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति, खतरे की जंजीर का खींचा जाना दोहरी लाइन बिछाये जाने से सम्बन्धित निर्माणकार्यों जैसी विभिन्न बातों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी इन खंडों पर गाड़ियों के संचलन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों के परिहार्य अवरोधों के मामलों पर कार्रवाई की जाती है, तथा अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किये जाते है।

Replacement of Diesel Engines by Steam Engines due to Shortage of Diesel

976. Shri Mahadeepak Singh Shakya :
Shri V. Mayavan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether diesel engines are again being replaced by steam engines due to diesel oil shortage; and

(b) if so, the number of engines so replaced and its likely effect on the Railway transport?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Modh. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

रेलवे के विद्युतीकरण क लिये केरल सरकार का अनुरोध

978. श्री सी० जनार्दनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में रेलवे का विद्युतीकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध किया है; और

(ख) क्या तेल के वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए इस राज्य में रेलवे का विद्युतीकरण करने के लिये सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। राज्य में पड़ने वाले खडों पर यातायात का घनत्व कम होने तथा विद्युतीकरण के लिए भारी पूंजी निवेश अपेक्षित होने के कारण ट्रंक मार्गों के मुकाबले उनके विद्युतीकरण को तरजीह देने का आर्थिक दृष्टि से औचित्य नहीं समझा जाता।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज

979. श्री नरेंद्र सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने देश को तेल के मामले में आत्म निर्भर बनने में सहायता देने हेतु तेल के तटदूर खोज कार्य को तेज करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) आयल इंडिया लिमिटेड ने अपने अन्वेषण संबंधी कार्य तेज कर दिये है और देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक सात वर्षीय कार्यक्रम (1978–79) बनाया है। इसके एक भाग के रूप में, यह 192,500 फुट (जो लगभग 58,712 मीटरों के बराबर है) की कुल गहराई से असम के [illegible]दम क्षेत्र में और अरुणाचल के निंगरू क्षेत्र में आने वाले वर्षों में 16 कुंएं खोदेगी।

केरल बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए कावेरी जल का मार्ग परिवर्तन

980. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए कावेरी बेसिन जल के कुछ भाग का मार्ग परिवर्तन करने संबंधी निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केरल सरकार ने बेसिन के बाहर विद्युत जनन और सिंचाई के लिए कावेरी के पानी को पश्चिम की और व्यपवर्तित करने के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किये है । इन पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कावेरी के बारे में विभिन्न मामले तय नहीं हो जाते।

Dismissal of a Delhi Magistrate by the High Court of Delhi

981. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi High Court passed orders in January, 1974 for the dismissal from service of a Delhi Magistrate, Shri P.C. Agarwal, on the charge of professional misconduct and if so, the reasons therefor;

(b) whether High Courts have the powers to dismiss their junior officers immediately after the charge of professional misconduct has been established without charge-sheeting them; and

(c) if so, the names of the High courts which took such action during the last three years and the number of Junior officers removed from service without charge-sheeting them?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b) Shri P. C. Agarwal was not dismissed from service. Shri Agarwal was appointed on probation in February 1973 and his services were terminated by the Administrator under Rule 22 of the Delhi Judicial Service Rules, 1970. Under the said Rule, the Administrator has the power to terminate the services of a person appointed on probation without assigning any reason.

(c) Does not arise.

Supply of Narmada Water to Rajasthan

982. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state whether the water of Narmada is proposed to be supplied to District Barmer in Rajasthan and if so, when?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : It has been agreed amongst the States that Rajasthan would get 0.5 m.a. ft. of Narmada waters. The details of the areas where this water will be utilised etc. will have to be worked out by the Government of Rajasthan after a settlement is reached on other connected issues.

Irrigation Schemes in Rajasthan

983. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the irrigation schemes of Rajasthan which are awaiting sanction of the Central Government at present;

(b) whether the Central Government have returned any irrigation schemes to the Rajasthan Government for review; and

(c) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The only new scheme proposed by the Government of Rajasthan and pending clearance is the Wagli medium irrigation project. This scheme is estimated to cost Rs. 95.27 lakhs and would provide irrigation to about 2570 hectares in Chittorgarh District. The scheme is at present under technical examination in the Central Water and Power Commission. They are awaiting State Government's replies to the comments sent on the proposals.

Withdrawal of Shuttle Train Running between Pali and Jodhpur

984. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the shuttle train running between Pali to Jodhpur has been withdrawn;

(b) the reasons therefor; and

(c) the reasons for which no action has been taken so far for restoring the train?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. 1JJM/2JJM trains have been temporarily cancelled between Pali Marwar and Jodhpur with effect from 7-10-73.

(b) & (c) Due to the difficult coal position.

मोरारका समूह द्वारा 1962 से चलाई जा रही फर्में

987. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोरारका समूह द्वारा 1962 से स्वयं, अथवा अन्य लोगों की भागीदारी में चलाई जा रही फर्मों के नाम क्या है;

(ख) इनमें से कितनी फर्में परिसमाप्त हो गई है अथवा उनको या तो राज्य सरकार ने अथवा केन्द्रीय सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है;

(ग) कौन-कोन सी फर्में अभी भी उनके नियंत्रण में है;

(घ) क्या उक्त फर्मों में कुप्रबन्ध होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो वे क्या है, और कर्मचारियों और अंशधारियों की शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) यह निदश श्री गोकुल चन्द द्वारका दास मुरारका एवं उनके परिवार की कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रतीत होता है । दिनांक 22 जुलाई, 1969 को उत्तर दिये गये, लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को परिपूर्ण करते हुये, 1971 में यह पहले ही बता दिया गया है कि 1969 में, अनुलग्नक में दी गई 16 कम्पनियों मुरारका समूह से सम्बन्धित थीं। इसके पश्चात इन कम्पनियों में से एक, यथा बेलापुर कम्पनी लिमिटेड, इस समूह की एक अन्य कम्पनी, गंगापुर शुगर मिल्स लिमिटेड के साथ समामिलित हो गई थी एवं इसके पश्चात पिछली कम्पनी का नाम, 'बेलापुर शुगर एण्ड इलाईड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड' हो गया।

(ख) अपोलो मिल्स लिमिटेड, "रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1972, दिनांक 31 अक्टूबर, 1972 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार, द्वारा अपने प्रभार में ले लिया गया है । श्री चांगदेव शुगर मिल्स लिमिटेड, के विषय में इसके व्यापार की देख-भाल करने के लिये आयकर विभाग द्वारा एक आदाता नियुक्त कर दिया गया है ।

(घ) तथा (ङ) कुप्रबन्ध की बाबत शिकायतों के परिणाम स्वरूप इस समूह की कतिपय कम्पनियों की, लेखा बहियों को कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण, किये गये थे। इन निरीक्षण रिपोर्टों की परीक्षा करने के पश्चात कम्पनी विधि बोर्ड ने निम्नांकित कम्पनियों में से, प्रत्येक के निदेशक मंडल में, कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत दो निदेशक नियुक्त कर दिये गये है :-

1. बेलापुर शुगर एंड इलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2. डब्ल्यू० एच० ब्राडी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
3. नासिक देवलाली इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड
4. पूना इलैक्ट्रीकल एण्ड इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड
5. श्री चांगदेव शुगर मिल्स लिमिटेड

कम्पनी विधि बोर्ड ने, बेलापुर शुगर एण्ड इलाईड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के कार्य कलापों, की कम्पनी अधिनियम की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत जांच पडताल करने के लिये भी आदेश दिये है ।

विवरण

1969 में जी० डी० मोरारका समूह की कम्पनियों के नाम बताते हुए विवरण-पत्र

1. अपोलो मिल्स लिमिटेड
2. आर्मस्ट्रांग स्मिथ लिमिटेड
3. बेलापुर कम्पनी लिमिटेड
4. ब्राडी एण्ड मारिस इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
5. भडोच इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड डेवलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
6. कपीश ट्रान्सपोर्ट एण्ड फाइनेंस कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड
7. मध्य भारत ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
8. महादेव कर्माशियल ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
9. नासिक देवलाली ,इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड
10. पूना इलैक्ट्रीकल एण्ड इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड
11. राजपूताना टैक्सटाईल एजेन्सिज (प्रा०) लिमिटेड
12. सरस्वती कर्माशियल ट्रेडिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड
13. शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड
14. श्री चांगदेव शुगर मिल्स लिमिटेड
15. डब्ल्यू० एच० ब्राडी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
16. गंगापुर शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसका नाम अब "बेलापूर शुगर एण्ड इलाईड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड" हो गया है ।

उर्वरकों के निर्माण के लिये आधार

988. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के निर्माण के लिये विभिन्न आधार क्या हैं ;

(ख) उनकी तुलनात्मक लागत क्या है;

(ग) भारत में उपलब्ध कच्चे माल से मुख्यतया उर्वरक के निर्माण के लिये क्या प्रयास किये गये है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) प्राकृतिक गैस, नैप्था, कोक/कोक ओवन गैस, बिजली, इंधन तेल/हैवी पेट्रोलियम फैक्शन और कोल जैसे विविधीकृत फीड स्टाकों को उपयोग हो रहा है या नाइट्रोजिनस उर्वरकों के उत्पादन करने के लिए उनका उपयोग किया जायेगा।

(ख) प्राकृतिक गैस और नैफ्था पर आधारित इधन तेल की कोल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा उनकी पूंजी और परिचालन लागत अधिक होगी जो कि अत्याधिक वरीय फीड स्टाक माना जाता है । प्रायोजना की स्थिति उपलब्धि गुण की प्रायोजना स्थलपर निवेशों की लागत जैसे तथ्योपर भी तुलनात्मक लागत निर्भर होगी।

(ग) और (घ) उर्वरकों फीडस्टाक में अधिकतम आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए योजना के एक भाग के रूप में तीन बृहत आकार के कोल आधारित उर्वरक संयंत्रों को कार्य रूप दिया जा रहा है ।

विदेशी सहयोग के साथ तेल की खोज

990. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हम कहां और किस के सहयोग से तेल की खोज कर रहे हैं; और

(ख) उक्त खोज का क्या परिणाम रहा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपर असम घाटी में, कैम्बे खाडी के बेसिन (भूमि तथा अपतट दोनों में), त्रिपुरा, नागालैण्ड, राजस्थान तथा कावेरी बेसिन में व्यधन कार्य कर रहा है । इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न क्षेत्रों के तलछटी बेसिनों में भूगर्भीय एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण कार्य भी किये जा रहे है। इन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य में किसी प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं लिया गया। तथापि हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया प्राइवेट लि० जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सहायक कम्पनी है, खाडी के पर्शियन वाटर में अन्वेषण कर रही है जिसमें इटली के ए० जी० आई० की तथा यू० एस० ए० की फिलिप्स कंपनी साझेदार है ।

(ख) गुजरात एवं असम बेसिनों में तेल एवं गैस भण्डार खोजे गये है । नागालैण्ड में खोदे गये कुंओं में से एक कुंए में तेल पाया गया है तथा त्रिपुरा में कुछ गैस भी पाया गया है । फारस की खाडी में अपतटीय संरचना में तेल पाया गया है तथा हाल ही में बाम्बे हाई के अपतटीय संरचना में भी तेल पाया गया है । कावेरी बेसिन के सम्बन्ध में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है ।

फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा योजना का विविधीकरण

991. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, त्रावनकोर की विविधिकरण योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) इस समय विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत मेथनोल और सोडा ऐश के उद्योग मण्डल यूनिट में उत्पादन की परिकल्पना है ।

अनुमति पत्रों के अन्तर्गत निर्धारित क्षमताओं के अतिरिक्त मिश्रित उत्पाद बनाना

992. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमति/अनापत्ति पत्र के अन्तर्गत निर्धारित क्षमताओं से बनाये जाने वाले मिश्रित उत्पाद लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक बनाये जाते है;

(ख) क्या मिश्रित उत्पादों के लिए दिये गये अनुमति पत्रों से विदेशी फर्मों को भारतीय सेक्टर को दबा देने की पर्याप्त सुविधा मिल गई है; और

(ग) क्या अनुमति पत्रों तथा अनापत्ति पत्रों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं तथा एककों की उपयोग क्षमता में वृद्धि हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ग) सामान्यतया निम्नलिखित शर्तों पर औषध विनिर्माणक फर्मों को अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र जारी किये जाते थे :--

(i) कार्य के लिये कोई अतिरिक्त प्लाट एवं मशीनरी अपेक्षित नहीं होगी;

(ii) कोई रायल्टी (राज सहायता) देय नहीं होगी;

(iii) इस समय प्रयोग में रही ट्रेड मार्क के अन्तर्गत उत्पाद का विपणन किया जायेगा;

(iv) समय समय पर लागू जनरल इम्पोर्ट पालिसी (सामान्य आयात नीति) में उद्धृत रियायत में मूल कच्चे माल तथा सामग्री में कोई विशेष छूट नहीं दी जायेगी।

औषध उत्पादन अथवा भारतीय क्षेत्र पर उत्पाद मिश्रण के प्रभाव के अंकन के बारे में बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अनुज्ञापत्रों/अनापत्ति पत्रों में से अनेक पत्रों में ऐसे मदों के सम्बन्ध में क्षमता नहीं बताई गई । औषध निर्माणकर्ताओं फर्मों को तकनीकी प्राधिकारियों तथा आयात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा आपूरण आधार पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति दी गई है तथा उन विनिर्माण एककों जिनमें आयातित कच्चे माल की समस्या निहित है के उत्पादन से विदेशी मुद्रा का बाहर जाना सीधे सम्बन्धित है । अनुज्ञा/अनापत्ति पत्रों पर आधारित विनिर्माण एककों द्वारा लिए गए औषध उत्पादन के आधार पर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

भारतीय औषध उद्योग का भारतीयकरण करने के बारे में आई० डी० एम० ए० का ज्ञापन

993. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध उद्योग का भारतीयकरण करने के बारे में आई० डी० एम० ए० ने उनके मंत्रालय को 16 सूत्री ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सरकार के विचाराधीन है ।

Scheme for Development of Irrigation and Power in Bihar

994. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government has submitted any scheme for the development of irrigation and power in Bihar ;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) A statement showing the new major and medium irrigation schemes and power schemes received from the Government of Bihar and under examination in the Central Government is at Annexure I & II. [*Placed in Library See No. L.T.* 6239/74].

(c) The schemes included in the Fifth Plan and approved by the Planning Commission should be taken up by the State Government in the Plan period.

राजस्थान में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

995. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के अनुरोध के बारे में 28 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उर्वरक सार्थ-समूह स्थापित करने के बारे में इस बीच निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) पाइराइटस तथा राक फास्फेट आदि मूल कच्चे माल के और अन्य आवश्यक सुविधाओं के कम खर्च पर उपलब्ध होने से संबंधित निश्चित ब्यौरों के प्राप्त हो जाने पर राजस्थान में एक उर्वरक उद्योग-समूह स्थापित किये जाने के बारे में निर्णय लिया जायेगा । सालादीपुरा पाइराइटस भंडारों पर मैसर्स आर० टी० जैड० द्वारा तैयार की गई संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त

हो गई है। विश्व बैंक के कहने पर मैसर्स पारसन्स द्वारा तैयार की गई संभाव्यता रिपोर्ट के संदर्भ में राजस्थान के झामरकोठरा क्षेत्र में राक-फास्फेट की खानों के विकास के तकनीकी तथा अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में खान-पान कर्मचारी विभाग

996. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में खान-पान कर्मचारी विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या का स्टेशन वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में उपर्युक्त विभाग के लिए नियमों के अधीन अपेक्षित छुट्टी रिजर्व और विश्राम-प्रदायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या नियमों के अनुसार किसी भी छुट्टी रिजर्व और विश्राम-प्रदायी कर्मचारी की सेवाओं का कभी भी उपयोग किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

	स्टेशन	खान-पान कर्मचारियों की संख्या
(क)	1. कटिहार और न्यू जलपाई-गुडी	28+5 छुट्टी रिजर्व+5 विश्रामदाता = 38
	2. गुवाहटी	32+3 छुट्टी रिजर्व+3 विश्रामदाता = 38
	3. तिनसुखिया . .	11+1 छुट्टी रिजर्व+2 विश्रामदाता = 14
(ख)	1. कटिहार और न्यू जलपाई-गुडी	5 छुट्टी रिजर्व +5 विश्रामदाता
	2. गुवाहटी	3 छुट्टी रिजर्व + 3 विश्रामदाता
	3. तिनसुखिया . .	1 छुट्टी रिजर्व + 2 विश्रामदाता

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षण

997. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई के तकनीकी संस्थानों में रेलवे के खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने संबंधी कोई योजना रेलवे के विचाराधीन है, और यदि हां

तो प्रत्येक रेलवे खान-पान विभाग में उपलब्ध प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और और इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए अधिक खान-पान कर्मचारी भेजने के भावी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कटिहार में अब तक विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां । रेलवे के जो खान-पान कर्मचारी खान-पान संस्थानों में प्रवेश पाने के पात्र है उन्हें उपयुक्त दलों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है । इस समय क्षेत्रीय रेलों पर इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गयी है :–

रेलवे	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
पश्चिम	29
पूर्व	44
उत्तर	4
पूर्वोत्तर	25
पूर्वोत्तर सीमा	38
दक्षिण	70
दक्षिण मध्य	9
दक्षिण पूर्व	5
मध्य	91

(ख) कटिहार स्टेशन पर आंशिक रूप से विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू कर दी गयी है । इस स्टेशन पर और यूनिटों में विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू करने के प्रश्न पर आगे कार्रवाई की जा रही हैं ।

रेलवे खान-पान तथा यात्री सुविधा संबंधी समिति का प्रतिवेनदन, 1967

998. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेलवे खान-पान और यात्री सुविधाओं सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन 1967 को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष कर पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में सभी मामलों में सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ग) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों ने अपनी खान-पान सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार तथा विस्तार करने का कोई प्रयत्न किया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति, 1967 की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी है सिवाय धुलाई योग्य की लागत को किसी दूसरे शीर्षक में प्रभारित करने से सम्बन्धित सिफारिश के जिसे स्वीकार नहीं किया गया था तथा दूसरी खान-पान कर्मचारियों की श्रेणी ii में पदोन्नति के अवसरों के सम्बन्ध में की गयी सिफारिश है जिसके बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया गया था। इस सिफारिश पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) इन सिफारिशों को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे सहित सभी क्षेत्रीय रेलों पर लागू किया जा रहा है।

(ग) 1967 से पहले पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुडी और कटिहार स्टेशनों पर तीन विभागीय खान पान यूनिट थे। दो और यूनिट, एक लोअर हाफ्लांग में नवम्बर, 1970 में और दूसरे तिनसुखिया में मार्च 1971 में खोले गये थे लेकिन लोअर हाफ्लांग वाले यूनिट को हानि होने के कारण दिसम्बर 1973 में बंद कर देना पड़ा। 23—1—1974 से जालुकावाड़ी में एक बार विभागीय अल्पाहार गृह खोला गया है। कटिहार में विभागीय खान पान व्यवस्था का विस्तार करने के प्रश्न पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ रेलवे खान पान और यात्री सुविधा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर खान पान के स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।

बंगाल की खाड़ी में एक विदेशी कंपनी द्वारा तेल के बड़े भंडारों का पाया जाना

999. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदशी कम्पनी ने इस बात का पता लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के नीचे और पश्चिम बंगाल की सुन्दरबन पहाड़ियों सहित अन्य पास के स्थानों में तेल के वृहद भण्डार है।

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी द्वारा दी गई रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस तेल सम्पदा को निकालने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) सरकार को इस प्रकार की किसी खोज की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का बंगाल की खाड़ी में समन्वेषण कार्य आरम्भ करने का अभी कोई विचार नहीं है। परन्तु जब (भूकम्पी) जहाज आ जायेगा तब तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस क्षेत्र में समन्वेषण का काम आरम्भ कर देगा। जहाज के लिए अमेरिका को आर्डर दिया गया है। जहाज को 1975 के प्रथम चौमाही में सुपुर्द किए जाने की आशा है।

चुनाव होने वाले राज्यों को तेल की सप्लाई

1000. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल के संकट के कारण वे राज्य तेल की नियमित सप्लाई से प्रभावित हुए है जिनमें हाल ही में चुनाव हुए थे;

(ख) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के आश्वासन के बावजूद भी इन राज्यों को चुनावों तक तेल की पूरी सप्लाई नहीं की गई थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक राज्य को दिसम्बर, 1973 और जनवरी और फरवरी 1974 में कुल कितनी मात्रा में तेल का आबंटन किया गया;

(घ) क्या अधिकांश उम्मीदवारों ने अपन वाहनों के लिये पर्याप्त तेल न मिलने की शिकायत की है, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या तथ्य है और चुनाव आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ङ) चुनाव अभियान के लिए मुख्य रूप से जिन तेल उत्पादों की आवश्यकता होती है वे है :— मोटर गैसोलीन (पैट्रोल) तथा हाई स्पीड डीजल तेल। केवल परिवहन सम्बन्धी बाधाओं के परिमाण स्वरूप होने वाली स्थानीय कमियों को छोडकर मोटर गैसोलीन की किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है परिवहन की बाधाएं रेलवे आदि के कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं के कारण आयी है । जहां तक हाई स्पीड डीजल तेल का सम्बन्ध है इसकी मांग में, अन्य बातों के साथ साथ, कुछ राज्यों में बिजली की कटौतियों और शीतकालीन वर्षा की कमी के कारण अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन तथ्यों के परिणाम स्वरूप हाई स्पीड डीजल तेल के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता हुई है । इस उत्पादक की बढी मांगों तथा परिवहन सम्बन्धी बाधाओं के कारण इसमें उत्पाद की सामान्यत: कमी हो गई है उन राज्यों में भी वही स्थिति है जहां चुनाव अभियान जारी है । यह समस्या इस तथ्य के कारण और भी जटिल हो गई है कि बजट से पूर्व तेल उत्पादों की मांग सामान्यत: बढ गई है । राज्य सरकारों को इस बात के लिए सचेत कर दिया गया है और उनसे अनुरोध भी किया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार उत्पादों समान वितरण के लिए सभी सम्भव उपाय करे और चोर बाजारी तथा जमाखोरी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। साथ ही चुनाव अभियान वाले राज्यों को यथा सम्भव सप्लाई, विशेषकर चुनाव के लिए अपेक्षित दो तेल उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक विशेष संगठन की भी स्थापना की गई है ।

पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल तेल का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता न ही इन दोनों उत्पादों के राज्यवार खपत सम्बन्धी आंकड़े संकलित किए जाते है ।

आसाम और गुजरात में तेल क्षेत्रों में गैस की बरबादी

1001. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और गुजरात के तेल क्षेत्रों में भारी मात्रा में गैस जलती रहती है;

(ख) क्या इस प्रकार बरबाद होने वाली गैस का कोई अनुमान लगाया गया है,

(ग) इतनी मूल्यवान हाइड्रो कार्बन गैस बेकार समझ कर जलाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिजली की कमी तथा उर्वरक के उत्पादन के लिये कच्चे माल की कमी को ध्यान में रखत हुए सरकार इन गैसों के उपयोग के लिये योजना बनायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या योजना बनाई गई है अथवा बनाई जायेगी;

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी नहीं। तथापि असम एवं गुजरात क्षेत्र के तेल क्षेत्रों में कुछ मात्रा गैस की जलती रहती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) गैस की कुछ मात्रा जो इसके अशोधित तेल से अलग करके उत्पादित की जाती है, को या तो गैस को बहुत कम दाब के कारण और जिसका परिवहन नहीं किया जा सकता है, के कारण अथवा अनेक परीक्षणाधीन पृथक पृथक तेल क्षेत्र से बहुत कम रूप में उत्पादित उत्पादन होने के कारण जलना पडता है । उपभोक्ता मांग में प्रतिदिन उत्तार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप कभी कभी गैस को जलना पडता है ।

(घ) और (ङ) उर्वरक के उत्पादन के सम्बन्ध में उर्वरक संयंत्र तथा विद्युत के उत्पादन हेतु तापीय विद्युत घरों के सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में उपलब्ध गैस की सप्लाई की जा रही है । इसके अतिरिक्त गैस औदयोगिक ईंधन के रूप में कुछ गैस उद्योगों को दी जा रही है । आशा है कि इस वर्ष के अप्रेल माह तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उत्तरी गुजरात में कलोल में इण्डियन फार्मस फर्टिलाइजर्स को आपरेटिव्ह कम्पनी की उर्वरकों के उत्पादन के लिए तथा भाभा आटोमिक रिसर्च सेन्टर के बडोदा में हैवी वाटर प्लान्ट को हैवी बाटर के उत्पादन के लिए गैस की सप्लाई करना आरम्भ करेगा । इन नये एककों को गैस की सप्लाई आरम्भ करने के साथ गुजरात में गैस का जलना नगण्य होगा। असम में उपलब्ध गैस का जहां तक सम्बन्ध है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग रसायन आदि के उत्पादन के लिए इस गस के उपयोग की सम्भाव्यता का सक्रिय रूप में अन्वेषण कर रहा है। इस समय असम के समीप लकवा के दो चाय बगानों में कुछ गैस की सप्लाई की जा रही है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधि आयोग का 55 वां तथा 57 वां प्रतिवेदन और उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में विधान सभा की चुनावक्षेत्रों के बारे में परिसीमन आयोग के कतिपय आदेश ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 और 35 के अन्तर्गत डिक्री के बाद की अवधि के लिये ब्याज दर तथा लागत पर ब्याज संबंधी विधि आयोग के 55 वें प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6225/174]**

(2) 'बेनामी सौदों' संबंधी विधि आयोग के 57 वें प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6226/74]**

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :–

(एक) सां० आ० 795 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 'मैसूर' राज्य का नाम बदल कर 'कर्नाटक' किये जाने के परिणाम स्वरूप संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय संशोधन किये गये है ।

(दो) सां० आ० 37 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य के बारे में संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 की सप्तम अनुसूची के भाग (ख) में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6227/74]

(4) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 8 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 764 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उडीसा राज्य के संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 9, जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 801 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धिपत्र जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6228/74]

इंडियन एयर लाइन्स, भारतीय तेल निगम तथा फिल्म वित्त निगम लिमिटेड के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं श्री के० आर० गणेश की और से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1969–70 के प्रतिवेदन – संघ सरकार (वाणिज्यिक) के निम्नलिखित भागों (हिन्दी संस्करण) की एक एक प्रति :—

भाग 8 : — इण्डियन एयरलाइंस

भाग 11 :—भारतीय तेल निगम लिमिटेड (पाइप लाइन अनुभाग को छोडकर शोधन शाला प्रभाग)

(6) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1970–71 के प्रतिवेदन – संघ सरकार (वाणिज्यिक) – चल चित्र वित्त निगम लिमिटेड का कार्यकरण – (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति-

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6229/74]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : मैं राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :—

"कि राज्य सभा ने 19 फरवरी, 1974 की अपनी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1974 पास कर दिया है।"

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक
RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में

महा सचिव : मैं भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1974 राज्य सभा द्वारा पास कि गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

एशियन केबल्स कारपोरेशन के बारे में 21-12-1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर के संबंध में सदस्य द्वारा वक्तव्य
STATEMENT BY MEMBER Re. ANSWER TO S. Q. NO. 591 DATED 21-12-73 ON ASIAN CABLES CORPORATION

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इस संबंध में बम्बई की एक प्रमुख तथा अत्याधिक अपराधी फर्म दि एशियन केबल्स कारपोरेशन जिसने अनेक ऊंचे लोगों के रिश्तेदारों, मित्रों तथा बच्चों को रोजगार दिया है, जिसका विवरण मैं अगले पत्र में किसी दिन दूंगा के बारे में क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि 25 टन पोलीथीन का आयात यहां देश में पहुंचने पर, 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर में किया गया था और काला बाजार में 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया और इस प्रकार 88 लाख रुपये का मुनाफा कमाया गया । क्या मंत्री महोदय हमें यह भी बतायेंगे कि लायसेंसों के पिछली ओर कितनी मात्रा की मोहर लगी हुई है और सीमा शुल्क विभाग की दैनिक तथा साप्ताहिक सूत्रों के अनुसार उसके आंकडें क्या हैं, प्रयुक्त लायसेंसों का मूल्य तथा एक अन्य प्रतियोगी यूनियन कार्बाईड द्वारा किये गये आयात का मूल्य कितना है ? दूसरे, इस फर्मों में निदेशकों की सूची में मुझे मैसर्ज एशियन केबल्स कार्पोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गिरधारीलाल, श्री पोपटलाल आदि के नाम दिखाई देते है । परन्तु हमें वास्तविक अपराधी डंकन ब्रदर्स कं० आर० पी० गोइन्का का नाम नहीं दिखाई दिया । इसका कारण क्या यही है कि वह सत्तारुढ दल के बहुत निकट है । इसका क्या कारण है कि इस मामले में इतने अन्तर्गस्त व्यक्ति आर० पी० गोइन्का का नाम नहीं है ? उन्होनें केद्रीय जांच ब्यूरों के कागजों में हेर फेर करके किसी प्रकार अपना नाम हटवा लिया यह सूची में है ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : एशियन केबल्स के विरुद्ध 80,56,500 रुपये की राशि के घोटाले संबंधी आरोप थे। उनके विरुद्ध में पहले ही दो मुकदमें चलाये जा चुके है । तीसरे आरोप के बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरों को जांच के लिये कहा गया है और यह ब्यूरो महान्याभिकत्वो के साथ सम्पर्क बनाये हुए है । दोनों के बीच चर्चा चल रही है । हम अपनी और से इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरों को सोंप चुके है, जो इस बारे में जांच करेगा और आवश्यक हुआ तो उनके विरुद्ध मुकदमा चलायेगा उन नामों में श्री गोइनका का नाम केवल इस लिए नहीं है क्योंकि उस समय वह एशियन केबल्स के मालिक नहीं थे । शायद उन्होनें इसको बाद में स्वामित्व लिया। इस नाम के न होने का यही कारण है ।"

श्रीमन्, मैंने निम्न लिखित दस्तावेजों का जिक्र किया है और उनमें मुझे जो कुछ मिला है उसका वर्णन मैं नीचे कर रहा हूं :—

वर्ष 1966–67 के लिये औद्योगिक नीति जांच समिति के प्रतिवेदन का परिशिष्ट अंक ii – जुलाई 69 (ii–20) गोइन्का शीर्ष के नीचे मद संख्या 3 में लिखा है "एशियन केबल कारपोरेशन लिमिटेड "

एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 67–68 के लिये निर्देशकों का प्रतिवेदन तथा लेखों का विवरण; निदेशक शीर्षक के नीचे श्री के० पी० गोयन्का (श्री आर० पी० गोयन्का के पिता) अध्यक्ष (2) श्री आर० पी० गोइन्का निदेशक (श्री के० पी० गोइन्का के पुत्र) एशियन केबल्स कारपोरेशन के वर्ष 68–69 के लिये निदेशकों को प्रतिवेदन तथा लखे के विवरण में अध्यक्ष और निदेशक वही व्यक्ति रहे, वर्ष 1970 के लिये निदेशकों के प्रतिवेदन तथा लेखों के विवरण में अध्यक्ष तथा निदेशक के स्थान पर फिर उन्हीं व्यक्तियों के नाम है । वर्ष 1971 में श्री आर० पी० गोइन्का, सुपुत्र श्री के० पी० गोइन्का निदेशक मंडल के अध्यक्ष बनाये इस लिये उपरोक्त कागजातों के अनुसार सर्वश्री के० पी० गोइन्का तथा आर० पी० गोइन्का कम से कम वर्ष 1966 से इस कम्पनी को नियंत्रित करते रहे है और मेरी जानकारी की अनुसार ये अपराध उन्ही वर्षों के कार्यकरण के दौरान हुए।

इसके अतिरिक्त इस कंपनी को पूरी तरह अपने अधिकार में लेने से पूर्व इन दोनो गोइन्का व्यक्तियों ने तीन विभिन्न नामों से इस कंपनी का प्रभावी स्वामित्व प्राप्त कर रखा था ।

मुझे विश्वास है कि मैं यह सिद्ध करने के लिये काफी प्रमाण दे चुका हूं कि मंत्री ने सभा को गुमराह किया था और सरकार ने जान बूझकर वास्तविक मालिकों को उस दण्ड से बचाय रखा जो कि वह अब देने का विचार कर रहे हैं ।

श्री गोखले के उत्तर में बताया गया है कि श्री के० पी० गोयन्का की डंकन ब्रदर्स तथा दो अन्य कम्पनियों में हिस्से 1966 से पूर्व भी थे । पहले यह हिस्से 49 प्रतिशत थे परन्तु 1966 में उनका पूर्ण स्वामित्व हो गया।

यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिये उपयुक्त मामला है । उन्होनें कई मंत्रियों के लडकों को नियुक्त किया है । श्री गोयन्का शासक दल को वित्तीय सहायता देने वालों में प्रमुख हैं।

Shri Shankar Dayal Singh (Chalia) : The ruling party should not be brought in every matter.

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा कहना है कि मंत्री महोदय ने सभा को गुमराह किया है। यदि आप मामले को विशेषधिकार समिति को नहीं सोंपते तो हम यही मानेंगे कि आप शासक दल का पक्ष ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ के प्रति ऐसी बाते नहीं कहनी चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Have you constituted a committee to find out whether these matters came under Direction 115 or 224. In the affairs of Asian cables, I had sent the balance sheet to the then Industry Minister Shri F. A. Ahmed, The feelings are being denied deliberately.

Mr. Speaker : The Minister has a right to reply.

Shri Atal Behari Vajpayee : Your office too has became a post office.

अध्यक्ष महोदय : नियम इसे पोस्ट आफिस बनाते हैं।

Shri Atal Behari Vajpayee : Deliberate misleading should be treated separately.

Mr. Speaker : The Minister has a right to reply.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यह मामला सदस्य द्वारा बहुत समय से सभा में उठाया जा रहा है। सदस्यों को इस बारे में भ्रष्टाचार का सन्देह है। इस मामले में जान बूझ कर तथ्य दिखाये गये हैं।

Mr. Speaker : Let the Hon. Minister give a reply.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : महोदय, मैंने माननीय सदस्य, श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दिया गया वक्तव्य ध्यानपूर्वक सुना है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :–

मैसर्स एशियन केबल्स द्वारा आयातित कच्चे माल के दुरुपयोग से संबंधित तीन मामले है। ये तीन मामले ये हैं :

(1) तांबे का दुरुपयोग, जिसमें लाइसेंस नवम्बर, 1962 से अक्तूबर 1964 की अवधि के दौरान प्राप्त कर लिए गए थे, और अपराध अप्रैल 1963 से मार्च 1966 की अवधि के दौरान किया गया जब कि फर्म का प्रबंध कोटक ग्रुप के हाथों में था और गोयन्का समूह निदेशक बोर्ड में नहीं थे।

(2) एल्युमिनियम का दुरुपयोग, जिसमें लाइसेंस जनवरी 1962 से अप्रैल 1963 की अवधि के दौरान प्राप्त कर लिए गए थे और अपराध फरवरी, 1964 से जनवरी 1965 की अवधि के दौरान किया गया था। तब भी प्रबंध कोटक ग्रुप के हाथों में था और गोयन्का निदेशक बोर्ड में नहीं थे। वास्तव में 14 मार्च 1966 का अंतिम संकल्प जिसमें एल्यूमिनियम की बिक्री विनियमित की गई थी उस समय पारित किया गया था जब कोटक फर्म की प्रबंध व्यवस्था में थे।

(3) लो डेन्सिटी पालिथिलीन पाउडर का दुरुपयोग जिसमें लाइसेंस 1967 में प्राप्त कर लिए गए थे और आपात तथा दुरुपयोग इसके बाद किया गया था।

एशियन केबल्स का प्रबंध अप्रैल 1966 में कोटक ग्रुप से डन्कन ब्रदर्स के हाथों में आ गया, और इसीलिए गोयन्का, श्री आर० पी० गोयन्का सहित, उस अवधि के संबंध में एशियन केबल्स के निदशक बोर्ड में थे जिसके दौरान लो डेन्सिटी पोलिथिलीन पाऊडर का दुरुपयोग किया गया था।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

श्री ज्योतिर्मय बसु के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में कुछ भ्रम प्रतीत होता है, जिसमें मैंने कहा था कि श्री गोयन्का का नाम उसमें नहीं है क्योंकि उस समय गोयन्का एशियन केबल्स के स्वामी नहीं थे। जब मैंने यह कहा था, तब मैं एल्यूमीनियम तथा तांबे के सौदों के संबंध में गोयन्का समूह के रोल के बारें में बता रहा था, जिन के सम्बन्ध में शिकायतें की गई थीं।

वास्तव में, 21-12-1973 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 591 के उत्तर में उसके साथ संलग्न विवरण के क्रमांक 9 पर, मने, आयात लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध आयातित एल्यमीनियम की बिक्री किये जाने के संबंध में एशियन केबल्स कारपोरेशन, बम्बई के निदेशकों के नामों का उल्लेख किया था। मैंने इसे श्री ज्योतिर्मय बसु के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में निम्नलिखित शब्दों में पुनः दोहराया था :

"एशियन केबल्स के विरुद्ध आरोप थे जिनमें 80,56,500 रु० की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। उनके विरुद्ध दो मामले पहले ही न्यायालय में फाइल किये जा चुके हैं। तीसरा आरोप भी केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेजा जा चुका है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो महा-न्यायाभिकर्ता से संपर्क में है। वे परस्पर मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हमने जांच के लिए और आवश्यक होने पर उनके विरुद्ध मुकदमा चलान के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों को मामला सौंप दिया है। श्री गोयन्का का नाम केवल इसी लिए शामिल नहीं है क्योंकि उस समय एशियन केबल्स के स्वामी गोयन्का नहीं थे। वे संभवतः बाद में इस के स्वामी बने। इससे श्री गोयन्का का नाम न होने का कारण स्पष्ट हो जाता है।"

अत: यह बिल्कुल स्पष्ट होगा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में और साथ ही अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में भी एल्यूमीनियम तथा तांबे के सौदों के संबंध में गोयन्का समूह के रोल का उल्लख किया था। जहां तक श्री ज्योतिर्मय बसु के अनुपूरक प्रश्नों का लो डेन्सिटी पोलिथिलीन पाउडर से सम्बन्ध है, यह दुरूपयोग तो उस अवधि से सम्बन्धित अवश्य है जबकि प्रबंध गोयन्का समूह के हाथ में था और श्री आर० पी० गोयन्का निदेशक बोर्ड में थे। मैं यहां यह भी उल्लेख कर दूं कि उसी तारांकित प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के दौरान मैंने यह कहा था;

"मैंने केवल इतना ही कहा था कि दोषी व्यक्तियों के ये नाम वहां है। मुझे ज्ञात नहीं है कि श्री गोयन्का ने किस तारीख से काम संभाला था। मैंने केवल इतना ही कहा था।"

अत:, महोदय जैसा मैंने स्पष्ट किया है यह कहना सही नहीं है कि मैंने सदन को गुमराह किया है। जहां तक, तांबे तथा एल्यूमिनियम सम्बन्धी मामलों के बारे में दंडात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध है, शिकायतें न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है। लो डेन्सिटी फेलिथिलीन माउल्डिग पाउडर के मामले के सम्बंन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों विधि मंत्रालय की राय पर विचार कर रहा है और हम केन्द्रीय जांच ब्यूरों से परामर्श की प्रतीक्षा कर रहे है। पोलिथिलीन मार्डल्डिग पाउडर के कथित दुरुपयोग के बारे में और उस कथित दुरुपयोग में श्री आर० पी० गोयन्का के सम्बन्धित होने के बारे में कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं लिया गया है। मैं इस सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि देश के कानून का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेवार पाई जाने वाली फर्मों अथवा व्यक्तियों को संरक्षण देने अथवा बचाने का हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, और न ही मेरा इस महान सभा को किसी भी तरह गुमराह करने का लेख मात्र भी इरादा है।

Shri Atal Behari Vajpayee : This is a deleberate attempt to mislead the house.

श्री एम० एन० पटेल (ढंढुका) : उपरिलिखत अनुपूरकों में तीन आरोप लगाये गये है। पहले दो आरोप तांबा और अल्यूमिनियम के बारे में है । उस समय गोयन्का निदेशक नहीं थे । तीसरा आरोप केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेजा गया था । तीसरा आरोप पौलिथीन के बारे में था। उक्त आरोप में गोयन्का का नाम नहीं था। शायद उस समय उनके पास स्वामीत्व नहीं था । मंत्री महोदय को भ्रम हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों वक्तव्य देखकर स्थिति स्पष्ट करूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि जांच ब्यूरों को गोयन्का के विरुद्ध मामला नहीं भेजा गया था। इस प्रकार केन्द्रीय जांच ब्यूरों एवं सभा दोनों को गुमराह किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दोनो वक्तव्य है । मैं उन्हें देखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशिष्ट आरोप लगाया था । उन्होने विशेषाधिकार के प्रश्न से इनकार कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह विशेषाधिकार का मामला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री आर० पी० गोयन्का, श्री उमा शंकर दीक्षित के पास रहते है जो पार्टी के लिये धन एकत्र करते है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दोनों वक्तव्य हैं । मैं इसी समय निदेश नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके पास मेरा तथा मंत्री महोदय का वक्तव्य भी है । ये दोनों आपके पास काफी समय से थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह आज ही प्राप्त हुए हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Your decision regarding Direction 115 and 224 should also the clarified.

Mr. Speaker : Direction 115 applies where the statement of the Minister is incorrect.

Shri Madhu Limaye : There is a ruling from the Chair of 1966 that if a statement is made delebarately it is matter of privilege.

Mr. Speaker : We shall do as the provision might be.

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

पटना और दानापुर (बिहार) में राशन की दुकानों में राशन उपलब्ध न होंना

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I have visited these days different areas of Patna & Danapur. There is no ration in the shops. The quantity for fifteen days was 1300 grams has been reduced to 450 grams. The students of Patna University have decided to agitate against the difficulty of getting rations. Taking in view the happenings of Gujarat, the Government should give immediate attention towards this problem.

[Shri Ramavatar Shastri]

The Bihar Government has repeatedly drawn the attention of the Centre towards this problem. You provide 20,000 tons of foodgrains against a demand of 1 lakh tons. The hon. Minister may please state as to what they intend to do to solve the problem of Bihar and Patna.

Shri Atal Behari Bajpayee (Gwalior) : Sir, yesterday you had told us that the Agriculture Minister would make a statement tomorrow on food situation in Maharashtra.

Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour) : What about the situation of elections in West Bengal.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये मैं ने कल ध्यानकर्षक प्रस्ताव स्वीकार किया है । यदि वक्तव्य नही आता तो मैं स्वीकृति दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS—Contd.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुजरात के बारे में और विशेषकर अहमदाबाद के बारे में जो उल्लेख किया गया है, वह अपर्याप्त है । वहां पर पहले ही जान व माल की काफी हानि हो चुकी है और वहां की जनता अब और हानि सहन नहीं कर सकती । पुलिस के अत्याचारों के परिणाम स्वरूप वहां पर 100 से अधिक व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पडा है । मै उन नव युवकों के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करता हूं जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हुए और अधिक खाद्यान्न संबंधी उचित अधिकार को प्राप्त करने के लिये अपने प्राण गवाये हैं । मैं एक 21 वर्षीय नवयुवक की फोटो *सभा पटल पर रखना चाहता हूं जिसे बडी बेशर्मी और बेरहमी से पुलिस की गाडी के नीचे कुचल दिया गया था । पिछले महीने की 27 तारीख को एक अन्य 17 वर्षीय लडके की हत्या कर दी गयी थी । मैं उसका फोटो भी सभा पटल पर रखना चाहता हूं * । मैं गोली कांड की प्रत्येक घटना की न्यायिक जांच करवाने की मांग करता हूं । न्यायिक विशेषज्ञों का एक न्यायाधिकरण गठित किया जाना चाहिये जो पुलिस के सभी प्रकार के अत्याचारों की और शासक दल पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे । गुजरात विधान सभा के विघटन की मांग सब और से की जा रही है और वह वास्तविक भी है । हम चाहते है कि इस लोक तंत्र में वहां की जनता को इस बात का अवसर मिले की वह भ्रष्ट व्यक्तियों को निकाल बाहर करे और अच्छे और ईमानदार व्यक्तियों को चुन सकें ।

यह कहना अनुचित है कि गुजरात में धनवान लोगों ने आन्दोलन चला रखा है या वे इसके पीछे है । यह बात हास्यास्पद है । वस्तुतः दुःखी लोग ही आन्दोलन कर रहे है ।

---

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण कागजात/दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया ।

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the Paper/Document was not treated as Paper laid on the Table.

गृह मंत्री ने गत दो महीनों में एक बार भी गुजरात का दौरा नहीं किया है । श्री कृष्ण चन्द्र पन्त और श्री गोखले भी वहां पर गये थे और उसके बाद राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया । क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात की उपेक्षा करती रहेगी ? नर्मदा जल विवाद के बारे में भी हमारे साथ न्याय नहीं किया गया। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वह सारे देश के लिये एक सबक है । भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जायेगा चाहे वह गुजरात में हो या देश किसी अन्य भाग में हो । अतः मैं प्रधान मंत्री और सरकार से अपील करता हूं कि वह यथार्थ वादी दृष्टिकोण अपनायें ताकि वहां पर और अधिक नुकसान न हो ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापूर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत ही व्यावहारिक ढंग से हमारे देश की गरीब जनता की भावनाओं और उनकी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। आज गरीब आदमी की स्थिति बडी विचित्र है । जब वह रोजगार प्राप्त करने के विचार से कोई मशीन आदि खरीदने के योजना बनाता है और किसी न किसी तरह धन की व्यवस्था करता है तो इस बीच उस वस्तु का मूल्य इतना बढ जाता है कि वह उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है । हमारे देश के कुछ लोग ऐसे है जो किसी भी समय कोई भी वस्तु खरीद सकते है परन्तु गरीब आदमी का यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। पेट्रोल का मूल्य बढाने से मोटर गाडियोंकी संख्या में कमी नहीं हुई क्यों कि वे लोग खर्च कर सकते है । परन्तु गरीब आदमी हताश होकर सरकार का मुह देखता रहता है। सरकार को उसे कठिनाइयों,में से निकालने का प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये कुछ सख्त कदम उठाये जाने चाहियें । सर्वप्रथम प्रधान मंत्री को योजना मंत्रालय बन्द कर देना चाहिये । एक आर्थिक मंत्री बनाय जाना चाहिये । जिसके अधीन वित्त सहित सभी आर्थिक मंत्रालय हों । फिर वर्तमान योजना आयोग की शक्तियां कम की जानी चाहियें। इस में केवल विशेषज्ञ होने चाहियें और इसे आर्थिक मंत्री के सलाहकार संस्था के रूप में काम करना चाहिये। हमारा अनुभव यह है कि लोकतंत्र में पांच वर्षीय योजनाएं बना कर काम नहीं चल सकता। हमारे देश में इस समय एक ही योजना की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जा सके ताकि वे कम से कम दोनों समय अपना पेट भर सकें । भारत में प्रत्येक नागरिक की क्रय शक्ति कम से कम इतनी अवश्य होनी चाहिये कि वे दिन में दो बार का भोजन खरीद सकें । ऐसा तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो । इस उद्देश्य के लिये ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढाना चाहिये जिनका निर्यात किया जा सके तथा जिनके उत्पादन के लिये अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजागर मिल सके ।

जहां तक खाद्यान्न वसूली कार्यक्रम का सम्बन्ध है यदि सरकार किसानों में एक निश्चित मूल्य पर खाद्यान्न खरीदना चाहती है तो उसे किसानों को उसी अनुपात में निश्चित मूल्यों पर खाद आदि भी उपलब्ध कराना चाहिये। यदि सरकार खाद्यान्न के मूल्यों को नीचा रखना चाहती है तो उसे इसी नीति को अनुसरण करना चाहिये। हमारे देश में मूल्य स्थिरीकरण का आशय है खाद्यान्न के मूल्यों को स्थिर रखना। यदि सरकार इस कार्य में सफल होती है तो देश में हडतालों आदि पर काबू पाया जा सकता है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जनता को निश्चित मूल्यों पर खाद्यान्न मिलता रहे ।

आज देश में काले धन को पूर्णतः समाप्त किये जाने की आवश्यकता है । इस उद्देश्य के लिए सरकार को विमुद्रीकरण तथा मुद्रा सम्बन्धी अन्य सुधार करने चाहियें । इसके अतिरिक्त, शिक्षा में भी सुधार किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिये अविलम्ब कदम उठाने चाहिये। बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों के

[श्री निम्बालकर]

विद्यार्थियों ने शिक्षा में सुधार किये जाने का प्रस्ताव किया है। उन्होनें बडे उपयोगी सुझाव दिये हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को आयात और निर्यात सम्बन्धी नीति को भी उदार बनाना चाहिये। यदि कोई उद्यमी अपने कारखाने के उत्पादों का निर्यात करके कुछ वस्तुओं का आपत्ति करने में सफल रहता है तो सरकार को उसके इस कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिये। इसमें रोजगार के अवसर बढेंगे, तथा देश को लाभ होगा।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद जैसे अनेक विवादों पर सरकार ने निर्णय करने में बहुत विलम्ब किया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार अनिर्णित मामलों पर शीघ्र निर्णय करें। बेलगांव में मराठी भाषी व्यक्तियों पर भारी अत्याचार किये गये। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ऐसी समस्याओं को अविलम्ब सुलझाने का प्रयत्न करें।

महोदय, 1951 में बम्बई में केवल 52,000 कन्नडभाषी लोग थे और 1971 में उनकी जनसंख्या 135,000 हो गई है। इसी प्रकार तामिलभाषी लोगों की जन संख्या 59,000 से बढ़कर 160,000 हो गई है। तेलगू भाषी और मलयालम भाषी लोगों की जनसंख्या में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई है। 1961 से 1971 तक की 10 वर्ष की अवधि में कन्नड के प्राइमरी स्कूलों की संक्या 45 से 58 हो गई और तमिल स्कूलों की 39 से 45 और तेलगू स्कूलों की 14 से 39 हो गई। मलयालम स्कूलों की संख्या 6 से बढ कर 10 हो गई। अतः यह कहना नितांत गलत है कि महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही। मेरे कहने का आशय यह है कि व्यदि इन व्यक्तियों को अपने राज्य में सभी सुविधायें मिल सके तो वे बम्बई में आए हीं क्यों?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): हमारी यह शिकायत नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार हमारे विरुद्ध है।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

---

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order, Sir, The State of Gujarat is under President's rule (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भाषण देने की अनुमति नहीं दी गई। आप व्यवस्था का प्रश्न ही उठा सकते है।

Shri Madhu Limaye : I want only five minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इतना समय कैसे दिया जा सकता है?

Shri Madhu Limaye : First, I will state the fact and formulate my point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको इसकी अनुमति देता हूं। किन्तु यह सभा की कार्यवाही से सम्बद्ध होना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : I want to raise it under rule 377.

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के तहत व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

Shri Madhu Limaye : I have given notice under rule 377 and I have to raise a point of order also.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने नोटिस दिया है तो आप ऐसा कर सकते है।

Shri Madhu Limaye : In the President's Address under discussion in the House, developments in Gujarat have also been mentioned.

Mr. Deputy Speaker : Sir, 16 members have resigned . . .

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

Shri Madhu Limaye : How can I say if you are not ready to listen (*Interruptions*)

श्री वसंत साठे (अकोला) : इन्हें यह बताना चाहिये कि संविधान की किस धारा अथवा किस नियम का उल्लंघन हुआ है। इन्हें नियम 376(3) के अनुसार इस प्रकार शुरु करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि श्री लिमये क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते है। व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर वह भाषण नहीं दे सकते।

Shri Madhu Limaye : Why should the hon. Member be allowed to intervene when I am on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये मैं इन्ह एक मिनट देता हूं यदि इससे उनका काम नहीं चल सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

Shri Madhu Limaye : It is not possible to do so within one minute.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकर दयाल सिंह अपना भाषण आरम्भ करें यदि वह नही बोलते तो मैं किसी और सदस्य को बुलाऊंगा।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr. Deputy Speaker, I want they should not interrupt while I speak because I will be speaking about their interests and about the interests of the nation (*Interruptions*). It is stated in the President's Address that the Presidents Rule was imposed in Gujarat in the beginning of this month. It is the responsibility of all the citizens to create an environment in which collective efforts get priority (*Interruptions*). They talk here about point of order but are creating disorders throughout the country. (*Interruptions*).

This is a critical time for the country. I want that the members from the opposition parties should cooperate in removing the shortages, profiteering, injustice and price-like ..(*Interruptions*). Sir, I will go on speaking till you order. I hardly care for what they say (*Interruptions*). History is a record of experiences both happy and sorrowful.... (*Interruptions*).... it is a record of glory. Whatever is happening today inside as well as outside this House, does it constitute the history of the glory of the nation? Undemocratic ways being adopted by the opposition parties have posed a danger to the democracy.

The principles adopted by the opposition parties have created chaos and disorders in the country. The opposition parties are answerable for that (*lnerruptions*). The Government wants to remove the sorrows and difficulties of the people but some people are causing those worries. The public condemned the indecent actions of the opposition parties on 18th February (*lnterruptions*). Some of the hon. members from the opposition want to dominate and create panic but we are not going to fall an easy prey to their actions (*lnterruptions*). We admit that our country is passing through crisis, but it is only Shrimati Gandhi who can overcome this crisis. The hon. members expressed their views over the President Address but I would like to know from them as to what has not been included in that Address (*Interruptions*).

Shri Madhu Limaye : Kindly permit me to raise a point of order .... (*Interruptions*)

Shri Shankar Dayal Singh : They should tell us as to what has not been included in that Address. Mention has been made about everything including shortages, discontentment, strikes, violence and profiteering in it. (*Interruptions*). The question which has now arisen is whether such persons should be allowed to destroy the democracy or they should be faced (*Interruptions*). The people condemn their actions (*Interruptions*).

Shri Madhu Limaye : For the first time I am not being allowed to raise a point of order in this House (*Interruptions*).

Shri Shankar Dayal Singh : Today the country needs discipline. What the opposition parties are doing today? (*Interruptions*).

Nothing has been said by any member about our achivements. (*Interruptions*).

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : What have they done for the country for the last 27 years? They have been murdering the people for the last 27 years. (*Interruptions*).

Shri Shankar Dayal Singh : The hon. members from the opposition have been misguiding the youths of the country.

Shri Madhu Limaye : I once again request you to permit me to raise a point of order (*Interruptions*).

Shri Shankar Dayal Sharma : This country needs nothing but discipline (*Interruptions*), The Government wanted to check black market but a particular party has been encouraging black market (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री मधु लिमये नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते है ।

श्री मधु लिमये को सहयोग देना चाहिये । व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर वह भाषण नहीं दे सकते क्योंकि इससे कार्यवाही के संचालन में कठिनाई पैदा हो जायगी। अब इन्हें सहयोग देना चाहिये और मैं उनकी बात मान रहा हूं । क्योंकि श्री शंकरदयाल सिंह ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है . . .

श्री शंकर दयाल सिंह : नहीं, मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि इन्होंनें अपना भाषण समाप्त नहीं किया तो अब कर लें। इसके बाद मै इस प्रश्न पर आउंगा।

Shri Madhu Limaye : Point of order can be raised immediately. He has not beegun his speech.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लिमये, मैं आपको अनुमति दूंगा (**व्यवधान**) मैं ने श्री शंकर दयाल सिह को बुलाया है वे अपना भाषण पुरा कर ले। अब मैं किसी की बात नही सुन रहा ।

Shri Shankar Dayal Singh : I was saying that the country is passing through a great crisis created by price-hike, shortages and other factors. We should think over the way and means to overcome these crisis. I should say that these crisis can be overcome only under the leadership of Smt. Indira Gandhi.

We made achievements in all the fields during the past 27 years. Anybody can see the network of small and big industries and their production and also increase in the agricultural production achieved during these years. In view of this, it will be baseless to say that there has been no progress.

Today, we require sense of service and dedication towards our nation and a strong character which will go a long way of for including a feeling of national integration.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लिमये आप अपना व्यवस्था का प्रश्न रखे ।

Shri Madhu Limaye : I want to draw your attention towards para 20 of the President's Address. A number of M.L. As both from the ruling and opposition parties have tendered resignations to the speaker Under article 179 of the constitution and Rule 269 of the Gujarat Assembly, the speaker has to accept the resignations.

Either Law or Home Minister should clarify the position by giving a statement on this point.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह नहीं नहीं आप की यह व्यवस्था क्या प्रश्न कैसे बन गया । गुजरात के मामले से चर्चा कैसे स्थगित की जा सकती है । गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष क्या करते है, हम यहां बैठकर इस बात का निर्णय नहीं कर सकते । आप चर्चा में भाग लेते हुए ही इस प्रश्न को उठा सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता हैं । और इसका उत्तर देना सरकार का काम है ।

श्री मधु लिमये : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बतायें कि **ये बातें** चर्चा के लिये किस प्रकार बाधक है।

Shri Madhu Limaye : This matter can be raised in Parliament under article 356 as now the powers of the Legislature of the State are exercisable by or under the authority of Parliament. I am not giving any opinion. I want clarification on a constitutional point.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात अब स्पष्ट हो गयी है । चर्चा के दौरान अनुरोध किया जा सकता है। मुझे ऐसी कोई बात दिखायी नहीं दे रही हैं जिससे हम चर्चा को जारी रखने में कोई बाधा पड़ती हो। यह प्रश्न नहीं हैं। मैं यह विनिर्णय देता हूं।...

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर जी; आप अपना भाषण समाप्त कर चुके है। कृपा करके बैठ जाइये ।

इससे किसी भी तरह से चर्चा को जारी रखने में बाधा नहीं पडती है।

श्री एच० एम० पटेल ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिड़े (सांगली) : अब जब कि हमने श्री मधु लिमये को सुन लिया है तो क्या वह अपने रोषपूर्व रयेवै के लिए जिससे वह अध्यक्षपीठ की ओर बढ़े थे खेद प्रगट करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अब श्री एच० एम० पटेल को बोलने के लिये बुलाया है। नियमों के अन्तर्गत यदि किसी सदस्य को बोलने के लिये बुलाया जाता है और वह नहीं बोलता है, तो इस पर विचार करना होता है। यदि प्रत्येक सदस्य यह कहता है कि वह कल बोलेगा, तो बहुत ही मुश्कील बात हो जाती है ।

प्रो० मधु दंडवते, क्या आप बोलना चाहेंग ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : मैं चाहता तो यह था कि कल बोलूं, किन्तु, चुंकि आप यह चाहते हैं, इसलिये मैं अभी बोलूंगा।

मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा है। चूंकि मेरे दल ने अभिभाषण का बहिष्कार किया था, इसलिये मैं इसे सुन नहीं सका। इस अभिभाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि जनता में भुखमरी तथा असंतोष व्याप्त है। इससे देश में विद्यमान आर्थिक और सामाजिक संकटों का उल्लेख नहीं किया गया है। सत्तारुढ़ दल पूर्ण बहुमत में होते हुये भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके परिणाम स्वरुप देश भर में असंतोष की लहर व्याप्त है।

जब देश में जनता आन्दोलन कर रही है, तो प्रधान मंत्री कहती है कि इन आन्दोलन के पीछे किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है। इसके साथ ही वह इसके लिये विरोधी दलों को भी समान रुप से दोषी ठरा रही हैं। विरोधी दलों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे जनता के रोष और भुखमरी की स्थिति का सरकार के समक्ष चित्रण करें और शान्तिपूर्ण ढंग से जनता के असंतोष का संचालन करें। जनता की गरीबी, भुखमरी और रोष के लिये सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार है।

चार पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वित किये जाने के पश्चात् भी देश की क्या स्थिति हो रही है ? घाटे की अर्थव्यवस्था 1975 करोड़ रुपये की है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो रही है।

कहा यह जाता है कि मूल्यों का बढ़ना एक विश्वव्यापी घटना है। जब हम अन्तर्राष्ट्रिय घटना की बात करते हैं तो हमें यह भी महसूस करना चाहिये कि कुछ अमीर देशों में मूल्यों में कितनी ही वृद्धि क्यों न हुई हो वहां लोगों की आय भी काफी रही है जिसके परीणाम स्वरूप मूल्यों में हुई वृद्धि का उन लोगों पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। किन्तु हमारे देश में स्थिति इसके बिलकुल ही विपरित है। हमारे यहां आर्थिक विषमता के साथ साथ सामाजिक विषमतायें भी विद्यमान हैं। ये सामाजिक विषमतायें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इनमें पीडित लोग अब चुपचाप सहन करने के लिये तयार नहीं है। अभि-भाषण में इस साम्राजिक विषमताओं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में पैदा होने वाले नये विद्रोह की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक सत्तारुढ दल इन बातों की ओर ध्यान नहीं देगा, तब इन समस्यायों का समाधान नहीं हो पायेगा।

मैं हर प्रकार के अत्याचार की निन्दा करता हूं। मैसूर राज्य में मराठी भाषी अल्प-संख्यकों पर अत्याचार ढायें जात हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी गैर-मराठी भाषी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये जाते हैं। इन अत्याचारों तथा सीमा विवादों को समाप्त करने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण भाषायी तनाव पैदा हो रहा है। बम्बई नगर में कुछ गैर-मराठी भाषी लोगोंने खोंमचे वालों को निर्दयता से पीटा जाता है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित करनी चाहिये। शिव सेना के समर्थ कोने बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करने के लिए एक अभिमान चलाया है।

हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के लोगोने संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना के लिए अपना खून पसिना बहाया था और हम इस बात की अनुमति नही देंगे कि बम्बई और महाराष्ट्र के बीच कोई दीवार खड़ी की जाये। हम चाहते हैं बम्बई महाराष्ट्र का अंग बना रहे। बम्बई में रहने वाले मल्यायम भाषी लोगोंने भी यह मांग कभी नही की कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग किया जाए।

किन्तु कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो इन तनावों का लाभ उठाना चाहते हैं और मांग करते हैं कि बम्बई को केन्द्र शासित क्षेत्र बना दिया जाये । मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जब तक चान्द और सूर्य है, बम्बई को महाराष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता। किन्तु साम्प्रदायिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाना चाहिये। मुझे खद है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

श्री के० के० शेट्टी (मंगलौर) : राष्ट्रपति अभिभाषण में यथार्थरुप से उन महत्वपूर्ण घटनाओं, चुनौतियों एवं कठिनाईयों का उल्लेख किया गया है जो हमारे देश और विश्व में व्याप्त हैं। इसमें हमारे देशमें विद्यमान स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी है।

यह बात गांधीवाद और गांधी जी के नाम पर धब्बा लगाने वाली है कि गुजरात में जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया और जहां उन्होंने अपना आश्रम भी खोला था और अहिंसा और सत्याग्रह पर अनेक अनुभव प्राप्त किये थे वहां हिंसात्मक कार्यवाहियों का विरोध करने के लिये भी पुराना गांधीवादी नेता नहीं है। यद्यपि यह राज्य पुराने गांधीवादियों तथा सर्वोदय नेताओं के लिये विख्यात है, किन्तु वे बिलकुल ही चुप रहे हैं। गांधीजी की तरह उन्होंने अनशन करने की भी धमकी नहीं दी ।

श्री मावलंकर हर समय इसी प्रकार का व्यवहार करते रहते हैं। **(व्यवधान)** 'हिज्जे की गलतियों' से श्री शमीम का क्या मतलब है।

राष्ट्रपति अभिभाषण में सभी मुख्य बातों और चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। यह बात सही है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अन्तिम पैरे में देश के सभी दलों और नागरिको से यह अपील की है कि सभी इकट्ठे होकर चुनौतियों तथा हर कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिये प्रयास करें ।

Shrimati Krishna Kumari (Jodhpur): Today we are facing a very difficult situation. Everywhere there is an atomsphere of scarcity, famine and discontentment.

The Government has been extending the sphere of nationalisation without taking care to see whether the nationalised industries are properly managed or not. The Government cannot achieve success, until corrupt people are removed from the management of these industries. The Government has not been successful in removing their corrupt and opportunist politicians.

Two years back the people returned the ruling party with absolute majority, but unfortunately the Government could not utilise this opportunity fully and they have failed to raise the standard of living of the people in the country and the people are getting poorer and poorer day by day. The unemployment is on the increase. The people are reeling under the pressure of high prices. Therefore, there are cases of violence and rioting. The Government should seriously consider this problem and arrange necessary buffer stock of foodgrains to tide over the present difficult situation.

My constituency is in Western Rajasthan. The condition of the people there is very serious. There was serious shortage in Jodhpur city. The proposed Scooter factory at Jodhpur has not come up so far. Sufficient employment opportunities have not been provided there. There is acute shortage of drinking water in some areas of Rajasthan. The canals and Tubewells should be provided there. Small training centres should be set up in the village for cottage industries. The quantity of ration of foodgrains in Rajasthan is very meagre. The Government should take steps to remedy the situation.

If all the people work together, the desired results can be achieved.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : आज देश को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में ईमानदारी से मूल्यांकन तथा विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। हमने इस बात का संकत भी दिया गया है कि देश की जनता को आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिये कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । आज देश मे जिन कारणों से गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है उनका भी इस अभिभाषण में पूरा विश्लेषण किया गया है। किन्तु इसमे इस बारे में बहुत ही कम कहा गया है कि सरकार के हाथ मजबूत करने के लिये नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिये । इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में सहयोग देने वाली अन्य एजेंसियों का भी समर्थन दे।

खाद्यान्नों की कमी तथा इनके सार्वजनिक वितरण मे त्रुटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न कारणों से खाद्यानों के उत्पादन में कुछ गिरावट आयी है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की असफलता का मुख्य कारण वसूली के लक्ष्य का पूरा न होना है। यह सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है और कोई भी ऐसा पग नहीं उठा सकती जिसके कि किसी उत्पादक के साथ जबरदस्ती की जाये और इस तरह उसके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाये। अतः वसूली के कार्य में चाहे यह खाद्यान्नों का हो अथवा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का कुछ कठिनाईयों का पैदा होना स्वाभाविक ही है।

यह भी पूछा गया है कि क्या सरकार के लिये उन सब एककों का, जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, राष्ट्रीयकरण करना सम्भव नहीं है । कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत हो सकता है कि सरकार को उन सभी एककों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये, क्योंकि सरकार उन्हें चलाने की स्थिति मे है। किन्तु उन्हें अपने हाथ मे ले लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि हमारे पास उन विशेष एककों को उनकी पूरी क्षमता के अनुसार चलाने के लिये प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति हों ।

अब मैं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र के बारे मे कहना चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने जो कुछ प्राप्त किया है, उसके बारे मे बहुत ही कम कहा गया है। उत्पादन मे वृद्धि करने के लिये अन्य बातों के साथ भारतीय उप-महाद्वीप मे स्थायी शान्ति का होना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है । आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन में कुछ तो 1971 के युद्ध की ही देन हैं, क्योंकि यह युद्ध पाकिस्तान ने हम पर जबरदस्ती सौंपा है। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी युद्ध से पूर्व, युद्ध के पश्चात तथा युद्ध के दौरान इस उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिये जो नीति अपनानी रही है, वह सफल रही है । भारत पहला देश था जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व मे बंगला देश को मान्यता प्रदान की थी। अब तो इसे पाकिस्तान ने भी मान्यता प्रदान कर दी है।

मुझे आशा है कि किसी भी स्तर पर भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान की त्रिपक्षीय वार्ता बहुत ही शीघ्र होगी, ताकि जिन समस्याओं का आज तीनों देश सामना कर रहे हैं, उनका समाधान करने के लिये ठोस प्रयास किये जा सकें ।

इस उप-महाद्वीप मे स्थायी शान्ति स्थापित करना तथा अन्य समस्याओं को हल करना अभी भी काफी सीमा तक पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रवैये और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुये पाकिस्तानी नेता रचनात्मक रवैया अपनायेंगे, ताकि इन समस्याओं को हल किया जा सके ।

1971 के भारत-पाक युद्ध से पैदा हुयी एक समस्या छम्ब क्षेत्र के शरणार्थियों की है। मैं बार-बार आप का तथा इस माननीय सभा का ध्यान उन की समस्याओं की ओर दिलाता

रहा हूं। सरकार को उनके समुचित पुनर्वास की ओर ध्यान देना चाहिये । गत युद्ध के दौरान इस क्षेत्र के लोगों ने सब से अधिक कुर्बानियां की हैं। केन्द्रीय सरकार का यह परम कर्त्तव्य है कि वह इन लोगों के समुचित पुनर्वास के लिये सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करे ।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि लगभग गत एक वर्ष से जम्मू तथा काश्मीर में राजनीतिक वातावरण तथा अन्य परिस्थितियों में काफी हद तक सुधार हुआ है। ऐसा वहां के मुख्य मंत्री, सैय्यद मीर कासिम के प्रभावी नेतृत्व के कारण ही हो पाया है। एक और खुशी की बात है कि शेख अब्दुल्ला ने अब राज्य एवं देश में नयी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। मैं शेख अब्दुल्ला के प्रयासों का स्वागत करता हूं जो उन्होंने सारे देश की धर्म निरपेक्ष शक्तियों को मजबूत करने के लिये किये हैं। किन्तु जब वह यह कहते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को स्वायतत्ता प्रदान की जानी चाहिये, तो मेरे विचार में क्या इस मामले के बारे में भ्रान्ति पैदा करने का प्रभास कर रहे हैं । जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोग समान स्तर से स्वायतत्ता चाहते है अर्थात वह उसी प्रकार की स्वायतत्ता चाहते है जो देश के अन्य राज्यों को प्राप्त है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह बात नहीं है ।

श्री इंद्रजीत मल्होत्रा : केवल आपके कहने से क्या होता है। मैं जम्मू तथा काश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं.... **(व्यवधान)** । वह अपने आपको राजनीतिक रुप से कितना ही शक्तिशाली क्यों न समझें, इससे जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के रवैये पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोगों ने राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिये काफी बलिदान किये हैं।

श्री एस० ए० शमीम : वह संसद में भाषण दे सकते हैं, इस से बाहर नहीं।

श्री इंद्रजीत मल्होत्रा : मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या वह लोगों का प्रतिनिधित्व करते है या कि शेख अब्दुल्ला का । मैं उनके अतीत तथा वर्तमान के बारे में जानता हूं किन्तु उनके भविष्य के बारे में नहीं जानता हूं।

अन्त में, मैं ईमानदारी से अपील करता हूं कि देश जिन आर्थिक अथवा राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा है, उनका हल करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक दल को भरसक प्रयास करना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई (सुरत) : मैं इस बात से अत्यधिक उद्विग्न हूं कि कांग्रेस ने जिन गुणों का प्रतिपादन किया और जिनका पालन किया उन्हीं गुणों का सत्तारूढ़ गए द्वारा उपहास किया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि समय बड़ा कठिण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने इसे माना है। इस तथ्य को कुछ समय पूर्व नहीं माना गया था। राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है वह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया हुआ है अत: मैं अपनी टिप्पणियां मंत्रिमंडल को सम्बोधित करूंगा।

सबसे अधिक खराब हालत आर्थिक क्षेत्र में है। 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे रह रहे हैं। वर्ष प्रति वर्ष महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है।

यदि हम यह कहें कि सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है तो सरकार कहेगी कि यह स्थिति तो विश्व-व्यापी है। जब कि अन्य देशों में वर्ष में 5 से 7 प्रतिशत से अधिक मूल्य नहीं बढ़ते हैं और साथ ही आय में भी 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है परन्तु हमारे यहां न केवल मूल्य 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ते है अपितु आय भी कम होती जा रही है।

[श्री मुरारजी देसाई]

सरकार के आंकड़ों के अनुसार बेरोज़गारी बढ़ रही है। जब ऐसा होता है तो सरकार यह तो कहकर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती है कि यह तो विश्व-व्यापी बात है। यह विश्व-व्यापी कैसे हुआ ? जब विरोधी दल सुझाव देते हैं तो सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करती है। प्रजातंत्र में जब सतारूढ़ दल विरोधी दलों के प्रति विनम्रता नहीं दिखाता तो बहुत कठिनाई हो जाती है। यहां तक कि महंगाई के लिये भी विरोधी दलों पर आरोप लगाया जाता है। सरकार इस बात को महसूस नहीं कर रही है।

मूल्यों के कम होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि नीतियां ही ऐसी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसका कोई उपचार नहीं सुझाया गया। इस वर्ष तो देश में काफी खाद्यान्न भी हुआ है। वर्ष 1965-66 में हमने 1460 लाख टन अनाज का उत्पादन किया था और दो वर्षों में हमें केवल 150 लाख टन अनाज ही आयात करना पड़ा था। गत दो वर्षों में 2000 लाख टन का उत्पादन हुआ हैं फिर भी 8 किलो से अधिक की पूरी सप्लाई करने में क्यों कठिनाई हो रही है ? यह कुप्रबन्ध और गलत नीतियों का परिणाम है जिससे देश में कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हुई है। इस बात को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये और नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए।

अपनी नीतियों में सुधार करने के स्थान पर सरकार इसका दोष मौसम तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर डाल रही है। सरकार प्रशासन पर भी दोष लगाती है और कहती है कि प्रशासनिक मशीनरी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है जिससे यह सब कुछ हो रहा है। परन्तु इस सब के लिए सरकार के अतिरिक्त किसे दोषी ठहराया जाये ?

प्राय: सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। वस्तुएं कम हैं और मुद्रा परिचालन में वृद्धि हो रही है जिससे मूल्य बढ़ रहे हैं। प्रति वर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ती ही जा रही है। अत: मूल्यों को बढ़ने से रोकने नहीं जा सकता। दो वर्षों में मूल्यों की यह वृद्धि 22 प्रतिशत है। अत: सरकार को इस मुद्रा स्थीति के लिए कुछ करना होगा। कहा गया है कि प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा पर बहुत खर्च हुआ है। कोई यह नहीं कहता कि प्रतिरक्षा पर व्यय कम करके देश की प्रतिरक्षा को कमजोर किया जाये। परन्तु इसको कमज़ोर किये बिना भी प्रतिरक्षा व्यय में कमी किये जाने की भारी गुंजाईश है। हमारे ईर्दगिर्द भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यदि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई ठोस उपाय किये जायें तो काफी बचत हो सकती है और मुद्रा परिचालन कम हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी बचत की जा सकती है।

जब तक हम उत्पादन करने वालों को प्रोत्साहन नहीं देते, तब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके साथ ही उत्पादन लागत को भी कम करना होगा। इसके बिना मूल्य वृद्धि को रोकने का कोई भी उपचार सम्भव नहीं हो सकेगा।

राजनीतिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। उड़ीसा में प्रतिपक्ष का बहुमत होने पर भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था राष्ट्रपति ने है अपने किसी एक भाषण में एक दिन सरकार की भ्रष्ट तथा अकुशल वितरण-प्रणाली को अनाज की कमी के लिये जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी गई है।

आर्थिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ऐसा भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में भी नहीं था। यदि लगातार प्रयास किये जायें तो भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। और प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने की बजाए मंत्रियों द्वारा करोड़ों रुपये अपने दल के चुनाव कार्य के लिये एकत्र किये जाते हैं। यदि मंत्री स्तर पर ऐसा होता है तो प्रशासन इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त रह सकता है ? अत: इस बुराई से छुटकारा पाना चाहिये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुजरात के प्रश्न का बहुत ही सीमित उल्लेख किया गया है जिससे पता चलता है कि सरकार गुजरात में होने वाली घटनाओं के प्रति उपेक्षा बरत रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल इतना उल्लेख किया गया है कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। किन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वहां राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया है और वहां क्या क्या हो रहा है।

प्रारम्भ में हिंसात्मक उपाय नहीं अपनाये गये थे। राशन की दुकानों को केवल 2 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रतिमास दिया जाता है। अनाज न मिलने तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुजरात में विद्रोह हो गया है। मैं इसे पसन्द नहीं करता। हिंसा से इसका निवारण नहीं हो सकता। मैंने स्वयं जाकर जांच की है। जिन 54 व्यक्तियों को गोली का शिकार बनाया गया है उनमें से 30 बेगुनाह लोग थे। पिछले 6 सप्ताह से हिंसात्मक कार्य चल रहे हैं।

बंबई में जो व्यक्ति मारे गये थे वे लूटमार हत्या आदि कर रहे थे। सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर गोली चलाने का समर्थन करता हूं।

पुलिस ने लोगों के घरो के भीतर घुस कर उन्हें पीटा और कई प्रकार के अत्याचार किये हैं।... **(व्यवधान)**

इन कारणों से गुजरात की सारी जनता विद्रोह कर रही है। वहां विधान सभा को भंग नहीं किया गया परन्तु राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। लोग ऐसी भ्रष्ट सरकार एवं सत्तारूढ़ पार्टी को सहन करने को तैयार नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैंने विरोधी सदस्यों के भाषणों को ध्यान पूर्वक सुना है। वास्तव में इस समय देश पर गम्भीर संकट है। देश आज इस सभा की ओर नेतृत्व करने के उद्देश्य से देख रहा है। यह संकट वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय है।

[**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** पीठासीन हुए
MR. DINESH CHANDRA GGSWAMI *in the Chair*]

चीन में आज एक और सांस्कृतिक क्रान्ति होने जा रहा है। अमरीका की राजनीतिक पद्धति ढलने को है। ब्रिटन में तीन दिन का सप्ताह चल रहा है।

भारत में गम्भीर आर्थिक संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार इस बारे में अनभिज्ञ नहीं है। परन्तु बहुत हद तक आर्थिक संकट के कारणों पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। आज यदि श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री होते तो भी सूखे की स्थिति बचा नहीं पाते।

सभा को पता है कि तेल के मूल्यों में तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से हमारी योजनाओं पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। इन बातों के लिये सरकार की निन्दा करना उचित नहीं है।

इस आर्थिक संकट पर रचनात्मक आलोचना और सहयोग का स्वागत करते हैं। एक प्रकार से ये संकट वास्तव में नैतिक एवं आध्यात्मिक है।

कांग्रेस के 10 वर्ष के इतिहास में बहुत उतार-चढ़ाव आये हैं। आज कांग्रेस पर्याप्ति शक्तिशाली है। पार्टी की आलोचना की हमें चिन्ता नहीं है।

श्री मावलंकर ने गुजरात की भयानक घटनाओं का उल्लेख किया है। इससे सारा देश चिन्तित है।

[डा० कर्ण सिंह]

मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री विधान सभा को भंग करने का निर्णय उचित समय पर लेगी। क्या हम यह चाहते हैं कि देश की लोकतन्त्रीय व्यवस्था समाप्त हो जाये। यह दलगत मामला नहीं है। हम सबने संविधान रक्षा कि शपथ ली हुई है। इस देश का युवा वर्ग देश की लोकतंत्री व्यवस्था में आस्था नहीं रखता। यह मामला दोष ढूंढने का नहीं है। यदि लोकतंत्रीय व्यवस्था भंग हो जाती है तो स्थिति बहुत बिगड़ जायेगी।

मैं समझता हूं कि यदि युवा पीढ़ी से उचित रीति से वार्ता की जाये तो उनकी ओर से उचित प्रतिक्रिया ही होती है। राजनीतिक मतभेदों की हमें चिन्ता नहीं है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में मतभेद होते ही हैं। जब राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के लिये संसद् में जाते हैं तो उनके घेराव द्वारा हमें कौनसी लोक-तंत्रीय परम्परा स्थापित करना चाहते हैं?

मैं स्वीकार करता हूं कि जिस प्रशासनिक पद्धति की श्री मोरारजी देसाई ने निन्दा की है उसे अवश्य बदला जाना चाहिये। वर्तमान नौकरशाही से हमें अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु एक ही पक्ष पर इसका उत्तदायित्व थोपना उचित नहीं है। भ्रष्टाचार राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध हो रहा है। उसके उन्मूलन के लिये हम किसी से पीछे नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री इस परिस्थिति को सुधारने के लिये कोई कदम उठाने वाली है।

देश में अध्यात्मिक मान्यताओं की आवश्यकता है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिये।

हमारे सिद्धांतों को पूरे विश्व ने ग्रहण किया है। हम विदेशी विचारधाराओं को स्वीकार नहीं कर रहें हैं। हमारे सिद्धांतों में हिंसा के लिये कोई स्थान नहीं।

मैं कहना चाहता हूं कि देश के शत्रु सजग हैं। हमारी किसी देश से शत्रुता नहीं है। कुछ शक्तिशाली देशों का हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया है और वे भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहें हैं। अतएव यह समय हमसे एकता की मांग करता है। देश की रक्षा व्यवस्था बहादुर जवानों के हाथों में है, जिनके शौर्य पर हमें पूरा भरोसा है। परन्तु उसके लिये यह आवश्यक है कि हम लोग संगठित रहें।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब यह देश में कमजोरी का बातावरण होता है तभी विदेशी शक्तियां लाभ उठाती हैं।

वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये पूरे राष्ट द्वारा सहयोग आवश्यक है।

***श्री ए० दुराई रासु** (पैंदरबलूर) : दोनों सदनों की संयुक्त सभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नीरस प्रथा बन कर रह गया है। सरकार लोगों की अन्न की मांग को पूरा करने में विफल रही है। एक राज्य की बिगडी हुई खाद्य स्थिति में पूरी जनता विद्रोह में उठ खड़ी हो गई है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है परन्तु खाद्य स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं किया गया। जनता का मात्र आश्वासनों से पेट नहीं भर सकता। इस कारण से 'द्रमुक' के सदस्यों ने अभिभाषण का बहिष्कार किया है।

तमिलनाडु में 'द्रमुक' सरकार द्वारा सफलतापूर्वक अधिक उपजाऊ विदेशी बीजों आदि की सहायता से हरित क्रांति लाई गई है। कई राज्यों को खाद्य सहायता भी दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Murena) : Sir, there is no quorum in the House.

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजाई रही है ।

अब कोरम हो गया है ।

श्री ए० दुराई रासु : अभिभाषण में राज्यों द्वारा वसूली के पूरा करने की बात कही गई है ।

वर्ष 1973-74 में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 40 लाख थी । केन्द्र अपनी वितरण की शक्ति का न्यायोचित उपयोग नहीं कर रही है । तमिलनाडु में प्रयाप्त रूई पैदा होती है परन्तु वितरण व्यवस्था केन्द्र के हात में होने के कारण तमिलनाडु में लाखों बुनकर बेकार हैं । राज्य के मंत्रियों द्वारा केन्द्र के साथ बातचीत से भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है । तमिलनाडु की सीमेंट, चीनी और धागे की आवश्यकता को पूरा करने में केन्द्र असमर्थ है । जब राज्य सरकार इन अभावों की पूर्ति के लिये अधिक शक्तियों की मांग करती है तब पृथकतावाद के नाम पर उसकी निन्दा की जाती है ।

वर्ष 1973-74 के लिये 1000 करोड़ रूपयों की घाटे की अर्थ-व्यवस्था है । केन्द्र ने 10,000 करोड रूपये के नोट छापे हैं । इस मुद्रास्फीति ने देश का गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है । प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से जनता की कमर टूट गई है ।

हाल ही में श्रीलंका की प्रधान मंत्री के साथ श्रीलंका के राज्यविहीन लोगों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं । इन सभी लोगों का तमिलनाडु ही से संबंध है । परन्तु राज्य की अपनी भी सीमाएं हैं । केन्द्र को राज्य के कल्याण की ओर भी ध्यान देना चाहिए । यह समझौता करने से पूर्व प्रधान मंत्रीने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री अथवा मंत्री-परिषद से बातचीत करना उचित नहीं समझा । राज्य की सारी जनता ऐसी बातचीत को उचित समझती है । राज्य की जनता और सरकार अधिकाधिक उत्पादन के पक्ष में है परन्तु उर्वरकों की कमी के कारण राज्य के इन प्रयत्नों में बाधा पड़ रही है ।

Shri Hukum Chand Kachwai : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बज रही है । अब कोरम हो गया है।

श्री ए० दुराई रासु : तमिलनाडु में उर्वरक उत्पादन की फैक्ट्रियां नहीं है। राज्य के पास आयात करने की शक्ति नहीं है । राज्य सरकार ऐसी फैक्ट्रियों के निर्माण की शक्ति की मांग करती है ताकि अपने जन-कल्याण के आह्वानों को पूरा कर पाये ।

स्वतंत्रता के 25 वर्ष पश्चात भी छूतछात् बनी हुई है । बाह्य खतरों के समय देश ने एकता प्रदर्शित की थी ।

इस समय जब राष्ट्र आंतरिक संकट से पीड़ित है, राष्ट्रपति को विदेश नीति की उपलब्धि की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी । केन्द्रीय सरकार सामाजिक अन्याय को मौन रूप से देखती रही है। केन्द्र को इस स्थिति पर नियंत्रण के उपाय करने चाहिये ।

वर्ष 1960–61 में प्रत्यक्ष कर 420 करोड़ के तथा अप्रत्यक्ष कर 1040 करोड़ रुपये के थे । 1971–72 में ये क्रमशः 1238 तथा 4511 करोड़ रुपए के हो गये । इतने अधिक करों से जनता का निर्वाह कैसे हो सकता है ? सरकार गरीबी हटाने के स्थान पर गरीबों को ही देश से हटाना चाहती है । केन्द्र को इन आर्थिक संकटों का शीघ्र समाधान करना चाहिए । प्रतिवर्ष राष्ट्रपति की अभिभाषण होता है, उस-पर चर्चा होती है परन्तु जनता की समस्याएं वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती ही जाती है । केन्द्र को निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव से अपने को संबद्ध करता हूं ।

[श्री ए० के० एम० इसहाक]

27 महीनों का अपना मौन त्यागने के पश्चात श्री मोरारजी देसाई ने केन्द्रीय कक्ष में मार्क्सवादियों के कृत्य की निन्दा तक भी नहीं की है । मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से मार्क्सवादियो की उक्त कार्यवाही की निन्दा करता हूं ।

इस समय देश महान संकट का सामना कर रहा है । हमारे शत्रू षडयंत्र में लगे हुए है ।

देश में पृथकतावादी तत्व क्रियाशील हैं । मैं उम्मीद लगाये हुए था कि श्री मोरारजी देसाई इन तत्वों की निन्दा करेंगे ।

राष्ट्रपतिजी ने उस उचित ही कहा है कि हम लोग आज संकट और परीक्षा के समय में पुनः समवेत हो रहे हैं । जब अनाज व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में था तब फसल कटते समय भाव कम हो जाते थे ।

जब वह किसानों के हाथों से निकलकर जमाखोरों के हाथों में गया, तो कीमतों में वृद्धि हो गई । फसल आने के समय जो कीमत होती है कमी के समय उस में 200 से 250 प्रतिशत की वृद्धी हो जाती है और पिछले दो साल से यह होता रहा है।

खाद्यान्नों की कीमत में अत्याधिक अनिश्चिता रहती थी । इसलिए खाद्यानों की एक निश्चित कीमत सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न-व्यापार का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया । इससे छोटे किसानो को शोषण से बचाया जा सकेगा । विरोधी पार्टियों ने सारे देश में इस का प्रयास किया कि गरीबों का कल्याण करने वाली यह नीति सफल न होने पाये । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अन्य विरोधी पार्टीयों के साथ मिलकर खाद्यान्न वसूली के कार्यक्रम में रुकावट डाली । अब हमारा उद्देश्य खाद्यान्नों का सरकारी व्यापार करना है, परन्तु इसके लिए एक विशाल प्रशासनीय व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है । यह रातों-रात नहीं किया जा सकता ।

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घन्टी बजाई जाय । . . . . अब गणपूर्ति है ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : बाजार का नियम यह है कि खाद्यान्नों की कीमत का निर्धारण, मांग और पूर्ति के अनुसार होता है, परन्तु भारत में खाद्यान्नों के मामले में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में 'बन्द' से 10 दिन पूर्व चावल की कीमत 2.10 रु० प्रति किलोग्राम थी, परन्तु बन्द से एक दिन पहले उसकी किमत 3.50 रु० प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई । 'बन्द' समाप्त होते ही कीमत फिर पूर्व स्तर पर आ गई थी । केन्द्रीय सरकार के यह घोषणा करते ही कि वह पश्चिम बंगाल सरकार की मांग के अनुरूप खाद्यान्न की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है, चावल की कीमत में फिर से वृद्धि हो गई ।

आज के सभी संकटों के लिए विरोधी पार्टियां जिम्मेदार है। वे आज भी कठिन स्थिति में लोगों से अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए कहती है । पाकिस्तान के साथ युद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री ने 'बन्द', 'तालाबन्दी' और 'हड़तालों' पर रोक लगाने के लिए आव्हान किया था । अगर हम उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि कर सकते हैं, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि करने सम्बन्धी सभी प्रयासों में रोक लगाई जाती है। संगठित क्षेत्र को लाभ उठाने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के कर्मचारियो के लिए एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए, जिससे सरकारी उपक्रमों के उत्पादन और लाभ में

वृद्धि हो सके। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश के श्रमिकों का अच्छी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। इस समय सर्वोच्च पदाधिकारी का वेतन निम्नतम स्तर के कर्मचारी के वेतन से 20 गुना है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यह अनुपात 5 1 का किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उत्पादन में स्वतः वृद्धि होने लगेगी।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : छोटी पार्टियो के पास समय भी कमी होने से वे सामान्य विषयों के बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती। इसलिए मैं अपने संशोधन तक अपने भाषण को सीमित रखूंगा।

[**श्री बसंत साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

मैं सबसे पहले मोपला विद्रोह में भाग लेने वाले देश भक्तों को राजनैतिक पेंशन देने का प्रश्न उठाना चाहता हूं। केरल सरकार ने, जिसमें कांग्रेस स्वयं भागीदार है, इन व्यक्तियों को पेंशन दी है, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उन्हें अभी तक पेंशन नहीं दी है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि श्री दीक्षित जी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और जनसंघ द्वारा लिखित इतिहास से सीख लेते हैं। बैरिस्टर ए० के० पिल्ले और अन्य विद्वानों द्वारा लिखित इतिहास के अनुसार यह विद्रोह गान्धीजी द्वारा प्रारम्भ किये गये खिलाफत आन्दोलन का ही एक भाग था। यह बात भी सही है कि अन्त में कुछ सांप्रदायिक घटनायें भी हुई, परन्तु ऐसी घटनाएं तो कांग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये गये आन्दोलनों के दौरान भी हुई थी।

मोपला क्षेत्र में छः महीने तक ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया था और इसका एक मात्र कारण स्वाधीनता सेनानियों का संघर्ष था। अगर सरकार उन्हें पेंशन नहीं देना चाहती तो न दे, परन्तु उनका यह कहकर अपमान न करे कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लिया था। केन्द्रीय सरकार को जनसंघ के बजाय केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लिखित इतिहास के तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अब अपने अल्पसंख्यक स्वरूप से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि प्रो० नूरूल हसन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम जल्दबाजी में पारित करवा दिया। जब तक इस अधिनियम में मूलतः संशोधन नहीं किया जायगा, तब तक मुस्लिम समुदाय संन्तुष्ट नहीं हो सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह मुस्लिमों की एक मात्र संस्था है।

उत्तर प्रदेश में चुनावों के समय उर्दू के बारे में जो वायदे किये गये थे अब उन्हें पूरा किया जायेगा। आशा है कि उन राज्यों में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया जायगा जहां यह बोली जाती है। उर्दू मुसलमानों की ही भाषा नहीं है, यह सब भारतियों की भाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में जनसंख्या का काफी भाग इस भाषा को बोलता है, मगर इसकी उपेक्षा की जाती रही है।

मुसलमानों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व है? यह कहा जाता है कि यह योग्यता पर आधारित है। आजादी के बाद मुसलमानों की योग्यता में ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? यह योग्यता का नहीं, पक्षपात का प्रश्न है। इस बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए, अन्यथा यह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अन्याय होगा। बंगला देश और इन्डोनेशिया के बाद हमारे देश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है।

[श्री सी० एच० मोहम्मद कोया]

बर्मा से आये शरणार्थियों को सरकार ने युद्ध के समय जो धनराशि दी थी, वह अब वापस नहीं लेनी चाहिए और जैसा कि स्वर्णकारों के मामले में किया गया था, इस राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए ।

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal) : Shri Morarji Desai had said in his speech that there is corruption, shortages, poverty, starvation and unemployment in the country, but he did not put forward any suggestion for removing these evils. He said that this Government must leave the power. I think that Shri Morarji Desai has been in power for the last 25 years, now he wants to come to power once again.

A true picture of the country has been portraited in the President's Address. If we want to progress and develop the country, we would have to fight against the evils unitedly. But the opposition wants to gherao the President.

Our country is marching on the path of progress under the leadership of the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. She went to the people in 1971 and told them that she wanted to bring about socialism in the country. The people gave her massive mandate.

Now it is alleged that the poor himself is being removed. The congress is not removing them, but it is the opposition which is putting hurdles in their way to progress. They are inciting the workers to go on strikes and thus cease production and stop movement of essential goods. The price rise is not confined to our country alone, but it is taking place throughout the world. The hoarders are encouraged by the opposition. The opposition wants to change the Government by creating restlessness among the people, but the people could not be befooled by them.

The situation in Gujarat was mentioned by Shri Morarji Desai in his speech. It was said that firing was resorted to and the people were shot dead, but he did not mention that the mob stoned the peace making police force and they had to open fire in self defence.

In these circumstances I would appeal to the opposition to co-operate with the Government and put forward concrete suggestions.

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या गलतियाँ हुई हैं या क्या त्रुटियाँ है । हमें इस पर विचार करना है कि अब किया क्या जाना चाहिए ।

मैं संविधान निर्माताओं के प्रति पूर्ण सम्मान सहित यह कहना चाहूंगा कि संविधान का हमारा वर्तमान ढाँचा जिन राजनैतिक विचारों पर आधारित है, उन राजनैतिक विचारों से अधिक महान हमारा अतीत रहा है । ग्रीक और रोमन राजनैतिक विचारधारा सभी विचारधाराओं का अन्तिम छोर नहीं है । अन्य विचारधाराओं का भी उद्‌भव हो रहा है । अमेरिका में पूंजीवाद भी समाजवाद की ओर अग्रेसर हो रहा है । प्रो० लिबरमेन की विचारधारा के कारण रूसी समाजवाद में भी परिवर्तन हुआ है । जब दो समानान्तर रेखायें एक दूसरे की ओर झुकने लगती हैं, तो वे एक निश्चित बिन्दु पर आकर मिल जाती हैं ।

यह बिन्दु राष्ट्रीयकरण नहीं है । हमें पिछली गलतियों से लाभ उठाना चाहिए । राष्ट्रीयकरण करते समय जनता को उसमें साझीदार बनाया जाना चाहिए था । पूंजीवाद को ट्रस्टीशिप की ओर अग्रसर किया जा सकता है । खाद्यान्न का राष्ट्रीयकरण आज अधिक सफल होता, अगर अधिकारियों के साथ जनता को बराबर का साझीदार बनाया गया होता । कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण भी एक बेहतर कदम साबित होता, अगर श्रमिकों को उसमें बराबरी का दर्जा दिया जाता ।

जनताकरण पूंजीवाद की सतर्क शक्तियों से भी अधिक सतर्क होगा । यह चीन की जन अदालतों से भी अधिक समाजवादी होगा । मैं सभी माननीय सदस्यों और देशवासियों से इस नवीन विचारधारा पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि देश को नवजीवन प्राप्त हो सके ।

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : I rise to support the motion of thanks on the Address of the President. I regret to say that when our Prime Minister gave a call to bring about socialism and for the removal of poverty, the imperialist and the reactionery forces are trying in a planned way to sabotage her programmes. We admit that there are certain defects in our system and these have to be rectified.

The farmers had given their wheat to the Government under levy system at the rate of Rs. 76 or Rs. 78 per quintal, but that very wheat is now not available in the market even at the rate of Rs. 150 per quintal. Our area is an agriculture-oriented area, but the fertilizers and the cement is not being supplied there. The Government should also make provision of seeds there. Our area is industrially backward but the Rajasthan Government has not declared it so. Due to short supply of coal, the brick-kilns have been closed and the labourers have been rendered jobless as a result thereof. The work on Rajasthan Canal should also be expedited.

From security point of view, it is very important to provide rail links between Jammu-Tawi to Dera Baba Nanak, and between Khemkaran to Husainiwala as also between Chandenwala to Hindumalkot. Similarly a rail link between Shrikoletji to Farandi be also provided.

The weaversare being exploited by the institutions. The Khadi Commission has appointed certain agents who exploit the weavers. There should be a direct dealing with the weavers.

Even after 25 years of independence, the suitable Harijan candidates are not able to get a good job. The Government has a liberal attitude towards the Harijan, but the bureacrats are not implementing the Government policies. All the people irrespective of their caste and breed should get a chance to progress.

Dr. Kailas (Bombay-South) : I am sorry to say that the members of opposition parties have not put forward concrete suggestions to solve the economic, political and social maladies facing the country. The state Governments might have certain defects and the union Government might also have committed certain mistakes, but the opposition parties should also change their attitude and help to distribute the essential commodities to the people.

There are 3,800 fair price shops in Bombay and there is no problem of distribution. Wheat was supplied from Haryana, and 400 trucks of rice was sent from Madhya Pradesh If it has not reached the fair price shops, there are certain defect in the process, which have to be removed by the State Governments. The opposition parties have obstructed the movement of trains and trucks as also the production in the factories.

The intellectuals like the Engineers and Doctors are causing troubles to the public for their small selfish ends. Their emoluments have been raised and the Minister has called upon them to join their duties so that their problems could be solved. A Kartar Singh Committee was appointed to go into the problems of the doctors. The Government has given them more than what was recommended by the Committee.

Shri Morarji Desai has said that a violent revolution is going to take place in the country. He has tried to create a feeling of panic and fear among the people. He has never said that violence must stop. He should have condemned the violent incidents. We are very sorry for the people who have been shot dead. The police has to resort to firing as an extreme step, when they are attacked by stones and bottles and the situation went beyond control. The Police should be given training to terrorise the mischief mongers and not to shoot them dead.

The Shiv Sena in Bombay has proved by its activities as to how it is going to rule over the state. The chief Minister, Shri Naik has to make arrangements for maintaining law and order in the State. He has clearly stated in the Assembly that all the persons residing in Maharashtra are Maharashtrians irrespective of their mother-tongue. There might have been some incidents in Belgaon or at Sholapur, but steps have been taken to check such incidents and to protect the minorities.

The political fights and difference of opinions might be there on the eve of elections but at the time of national crisis all the parties should unite to help solve the problems facing the country.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 फरवरी, 1974/8 फाल्गुन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday the 27th February, 1974/ Phalguna 8, 1895 (*Saka*).

भा०स०मू०ना०–वि8–2 लो०स०स०/9-5-74–490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].